



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2015/आश्विन 20, 1937

No. 265]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2015/ASVINA 20, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2015

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताइपेई, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड प्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जाँच ।

फा. सं. 15/04/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए संबंधित नियमावली के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 25

नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताइपेई, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश/क्षेत्र भी कहा गया है) से एसटीएम ए240/ए480एम की समस्त श्रृंखला के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों, जिन पर कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) से आगे कार्य न किया गया हो, जिनकी चौड़ाई 600 मिमी. से 1250 मिमी. तक हो (मिल किनारे के लिए +30 मिमी. और ट्रिम्ड किनारे के लिए +4 मिमी. की चौड़ाई सहनशीलता), तथा मोटाई 4 मिमी. तक हो (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच शुरू की थी।

2. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए गए थे और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. 38/2009-सीमाशुल्क द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा 24 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे। उक्त जाँच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाएजाने की तारीख अर्थात् 22 अप्रैल, 2009 से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

3. उक्त शुल्क की अवधि समाप्त होने से पहले भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख घरेलू विनिर्माता मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जिन्हें एतदपश्चात याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन दायर किया है जिसमें शुल्क के समाप्त होने पर संबद्ध देशों/ क्षेत्रों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों/ क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए उसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

4. घरेलू उद्योग द्वारा दायर एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 17 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. 15/04/2014-डीजीएडी द्वारा उक्त नामित देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू

शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है। निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के परिणामस्वरूप 12 मई, 2014 की अधिसूचना सं. 20/2014-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केन्द्र सरकार द्वारा 21 अप्रैल, 2015 तक और उसे शामिल करते हुए बढ़ाया गया था।

5. निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार जाँच को पूरा करने की अवधि को छह माह अर्थात् 15 अक्टूबर, 2015 तक बढ़ाया था।

6. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देशों/ क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

1. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. नियम 6 (2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/मिशनो को जाँच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया।
- ii. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/मिशनो को उपलब्ध कराई थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति एक सार्वजनिक फाइल के रूप में भी उपलब्ध रखी गई और मांगे जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई गई।
- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और नियमों 6(2) और 6(4) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

1. मै. शंघाई क्रुप स्टेनलैस, चीन
2. मै. झंगजियागेंग पास्को स्टेनलैस स्टील कंपनी लि., चीन
3. मै. एएलजेड एनवी, बेल्जियम
4. मै. यूजाइन(यूसीनर का डिविजन), इम्ब्यूबल पैसिफिक, फ्रांस
5. मै. एसेरिनाक्स एसए, स्पेन
6. मै. एसेरिनाक्स एसए, इटली

7. मै. थाइसेनक्रुप निरोस्टा जीएमबीएच, जर्मनी
 8. मै. थाइसेनक्रुप एसीसीएआई स्पेशलटेरेनीएसपीए, इटली
 9. मै. आटोकुम्पू स्टेनलैस, यू. के.
 10. मै. आटोकुम्पू स्टेनलैस, फिनलैंड
 11. मै. आटोकुम्पू स्टेनलैस, एबी, स्वीडन
 12. मै. ए. के. स्टील कार्पोरेशन यूएसए
 13. मै. एलीघेनी लुडलम, यूएसए
 14. मै. नार्थ अमेरिकन स्टेनलैस, यूएसए
 15. मै. जे एंड एल स्पेशियलिटी स्टील, इंक, यूएसए
 16. मै. यार्डह यूनाइटेडस्टील कार्पोरेशन (यूस्को), चीनी ताइपेई
 17. मै. कालम्बस स्टेनलैस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका
 18. मै. पोस्को, कोरिया
 19. पास्को, थाइनाक्स, थाइलैंड
- iv. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत स्थित चीन जन. गण. के दूतावास को भी भेजी गई थी जिसमें विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया। यद्यपि जाँच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके किया गया है तथापि, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया है कि उन्होंने आवेदक के दावे की यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में जाँच की है। अंतः चीन जन. गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि चीन जन. गण. के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान किया जा सकता है। तथापि, चीन जन. गण. के किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने चीन जन. गण. को दिये गए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का खंडन करते हुए एमईटी प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

v. जॉच शुरुआत संबंधी अधिसूचनाओं के उत्तर में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है:

- क. मै. एसेरिनाक्स एसए, स्पेन
- ख. मै. कालम्बस स्टेनलैस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका
- ग. मै. पोस्को, कोरिया
- घ. मै. देवू इंटरनेशनल, कोरिया
- ङ. मै. हयूंडई कार्पोरेशन, कोरिया
- च. मै. पोस्को थाइनाक्स, थाइलैंड

vi. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं/एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां भेजीं और नियम 6(4) के अनुसार उन्हें पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने की सलाह दी:

- क. मै. ओनेस्ट एंटरप्राइजेज लि., वदोदरा
- ख. मै. कुबेर स्टील इम्पेक्स, मुम्बई
- ग. एम. एम. एंटरप्राइजेज, रायगढ़
- घ. एडवांस मेटलन कार्पोरेशन, मुम्बई
- ङ. भंडारी फाइल्स प्रा. लि., देवास
- च. एंजेल पाइप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि., मुंबई
- छ. आईडीएमसी लि., गुजरात
- ज. एम. के. स्टील सेंटर, रायगढ़
- झ. रिद्धि सिद्धि इम्पेक्स, मुम्बई
- ञ. सलेम स्टेनलैस स्टील सप्लायर्स, चेन्नई
- ट. वेस्टर्न मेटर (इंडिया), मुम्बई
- ठ. स्टार स्टेनलेस स्टील, मुम्बई
- ड. एडवांस मेटल कार्पोरेशन

- ढ. अरिहंत स्टील एंटरप्राइजेज, मुंबई
 ण. जिंदत्त स्टील, मुम्बई
 त. मद्रास स्टील एजेंसीस, चेन्नई
 थ. नोबल इम्पेक्स, मुम्बई
 द. ऑल इंडिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 ध. स्टेनलैस स्टील एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन
 न. प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- vii. केवल दो आयातकों द्वारा आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं अर्थात :
- क. मै. पोस्को इंडिया चेन्नई स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लि. (आईसीपीसी), चेन्नई
 ख. पोस्को इंडिया दिल्ली स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लि. (आईडीपीसी), दिल्ली
- viii. तथापि, निम्नलिखित द्वारा क्षति आदि के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:
- i. मै. ऑल इंडिया स्टेनलेस इम्पोर्टर एसोसिएशन,
 ii. मै. एमपी इंडस्ट्रीज,
 iii. मै. विनोद कुकवेयर,
 iv. मै. मीना मेटल इम्पेक्स प्रा. लि.
- ix. निम्नलिखित अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों से भी जाँच से संगत सूचना प्रदान करने के लिए भी कहा गया था। तथापि, इनमें से किसी ज्ञात उत्पादक ने इस जाँच से संगत कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है:
- क. मै. सलेम स्टेनलैस स्टील, चेन्नई
 ख. मै. शाह अलॉय लि., गुजरात
 ग. मै. बीआरजी:- कार्पोरेट कार्यालय, पश्चिम बंगाल
- x. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़ों पर वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में भरोसा किया गया है। इसके अलावा प्राधिकारी ने संभावना के आकलन के प्रयोजनार्थ प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए जाँच अवधि के बाद (जनवरी 2014 - जून 2014) के बाद की अवधि की भी जाँच की है।
- xi. ऐसे निर्यातक, उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्ष जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है

और न ही इस जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है।

- xii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- xiii. नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया गया। सैनडिस्क के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आकड़ों के अगोपनीय अंश को उस मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में प्राधिकारी द्वारा दायर की गई अपील पर ध्यान दिए बिना हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में खुला रखा गया।
- xiv. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा अपनी सतत रीतियों के अनुसार भारत से संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने जिससे इस बात की जांच की जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, हेतु घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।
- xv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 28.10.2014 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध अपने अनुरोध को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- xvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण नई सार्वजनिक सुनवाई 18 अगस्त, 2015 को की गई ताकि जाँच के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हितबद्ध पक्षों को उनके विचार रखने का अवसर मिल सके।
- xvii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 6 अक्टूबर, 2015 को जारी प्रकटन विवरण के द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षों को अनिवार्य तथ्यों प्रकटन किया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक विचार किया गया है। जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों और सार्वजनिक सुनवाई के बाद के लिखित अनुरोधों का उनके संगत होने और साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा

तक इस प्रकटन में समाधान किया गया है।

- xviii. भागीदार घरेलू उत्पादकों और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई और व्यवहार्य सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xix. जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने उसे असहयोगी माना है और अपेक्षित सीमा तक निर्धारणों के लिए अपने पास "उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना" का उपयोग किया है।
- xx. इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- xxi. इस जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि जनवरी, 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक (12 महीने) की है। और क्षति जाँच के आंकड़ों के प्रयोजनार्थ 2010-11, 2011 - 2012, 2012-2013 की अवधि तथा जांच की अवधि पर विचार किया गया है।
- xxii. निर्यातों के देशों में स्थानीय मुद्राओं में सौदों के मूल्यों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सहयोगी/प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उनके प्रश्नावली के उत्तरों में बताई गई विनिमय दरों को लिया है। ऐसे सभी परिवर्तनों जिनमें विनिमय की वास्तविक दर उपलब्ध नहीं थी पीओआई के लिए औसत विनियम दर को इस प्राधिकारी द्वारा 58.97 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

8. मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अंतिम सिफारिशों में उत्पाद के दायरे को सीमित कर दिया जिनपर कतिपय अपवर्जनों के साथ केवल 1250 मिमी. तक और उसे शामिल करते हुए स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर शुल्क की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार ने शुल्क तालिका में उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित करते हुए शुल्क लगाया :

'600 मिमी. से 1250 मिमी. तक की चौड़ाई के सभी श्रृंखला वाले स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों जो 4 मिमी. तक की मोटाई के साथ कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) से कम कार्य किया गया हो।

संबद्ध वस्तु में उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित अपवर्जन किए जाएंगे:

- i. मै. थाइसेनक्रुप स्टेनलैस इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड एआईएसआई 420 हाईकार्बन (0.28 प्रतिशत-0.40 प्रतिशत), ग्रेड 420, ग्रेड 430 बीए, ग्रेड एआईएसआई 441 और ग्रेड एआईएसआई 443,
- ii. डुप्लेक्स स्टेनलैस स्टील ग्रेड 2205 (एस31803), 2304 (एस32304), ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 और 1.4833 और फेरिटिक ग्रेड ईएन 1.4509 और 1.4512,
- iii. कम निकेल वाले और क्रोमियम निकेल मैंगनीज-तांबा आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील वाली वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी ताइपेई (ताइवान) के मै. याइह यूनाइटेड स्टील कार्प. (यूस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेडों वाईयू1 और वाईयू4 को दर्शाने वाले ।

9. तत्पश्चात घरेलू उद्योग ने मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन दायर किया, घरेलू उद्योग के आवेदन के आधार पर और कानून की आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 8.6.2011 की अपनी अंतिम जाँच परिणाम (मध्यावधि समीक्षा) सं. 15/16/2009-डीजीएडी द्वारा 20 फरवरी, 2010 की मूल सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 14/2010-सीमाशुल्क में संशोधनों की सिफारिश की। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 6.9.2011 की संशोधन अधिसूचना सं. 86/2011-सीमाशुल्क जारी की जिसमें शुल्क तालिका के बाद पैरा 1 में उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित को शामिल किया गया:

(क): (+) 30 मिमी. की चौड़ाई सहनशीलता मिल किनारे 1000 मिमी. या उससे अधिक परंतु 1250 मिमी. से कम की विनिर्दिष्ट चौड़ाई के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर लागू होगी।

(ख): (+) 4 मिमी. की चौड़ाई सहनशीलता ट्रिम किनारे, 1000 मिमी. या उससे अधिक परंतु 1250 मिमी. से कम की विनिर्दिष्ट चौड़ाई के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर लागू होगी।

10. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मध्यावधि समीक्षा की थी जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 5.12.2011 के शुद्धिपत्र द्वारा पाटनरोधी शुल्कों के दायरों से पहले हटाये गए उत्पादों में आगे और कतिपय संशोधन किए गए। केन्द्र सरकार ने दिनांक 7.2.2012 की शुद्धिपत्र अधिसूचना द्वारा प्राधिकारी के संशोधित

अंतिम जाँच परिणामों को स्वीकार किया। उक्त समीक्षा के बाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित को बाहर रखा गया:

- i. 1250 मिमी. से अधिक की चौड़ाई की संबद्ध वस्तु (सहनशीलता सहित)
- ii. ग्रेड एआईएसआई 420 उच्च कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509
- iii. कम निकेल वाले और क्रोमियम निकेल मैंगनीज-तांबा आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील वाली वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी ताइपेई(ताइवान) के मै. याइह यूनाइटेड स्टील कार्प. (यूस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेडों वाईयू1 और वाईयू4 को दर्शाने वाले ।

11. पूर्वोक्त को देखते हुए इस निर्णायक समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया :

समस्त श्रृंखला के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों, जिन पर कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) से आगे कार्य न किया गया हो, जिनकी चौड़ाई 600 मिमी. से 1250 मिमी. तक हो (मिल किनारे के लिए +30 मिमी. और ट्रिम्ड किनारे के लिए +4 मिमी. की चौड़ाई सहनशीलता), तथा मोटाई 4 मिमी. तक हो, जिनमें निम्न शामिल नहीं हैं:

- i. 1250 मिमी. से अधिक की चौड़ाई की संबद्ध वस्तु (सहनशीलता सहित)
- ii. ग्रेड एआईएसआई 420 उच्च कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509
- iii. कम निकेल वाले और क्रोमियम निकेल मैंगनीज-तांबा आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील वाली वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी ताइपेई(ताइवान) के मै. याइह यूनाइटेड स्टील कार्प. (यूस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेडों वाईयू1 और वाईयू4 को दर्शाने वाले ।

12. याचिका के अनुसार संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 में बेस मेटल्स और बेस मेटल्स की वस्तुएं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 टैरिफ कोडों के अंतर्गत आयात किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल

सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

13. याचिकाकर्ता ने अपने अनुरोधों में शुल्क के संग्रहण के लिए शुल्क तालिका में दर्शाए गए अंतिम पीयूसी पर लगाई गई सीमा को हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि 1250 मिमी. से अधिक की चौड़ाई (सहनशीलता सहित) को बाहर रखने का एकमात्र आधार निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में अपनी मौजूदा सुविधा से मूल जाँच में जाँच अवधि के दौरान सटीक आकारों की आपूर्ति नहीं की थी। चूंकि घरेलू उद्योग अब अपेक्षाकृत चौड़ी वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पर लगाई गई सीमा को नहीं हटाने का कोई विधिक और तार्किक कारण नहीं है।

ग.1 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग से इतर हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का उन ग्रेडों जिन्हें मूल जाँच में बाहर रखा गया था को शामिल करने का अनुरोध अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 17 अप्रैल, 2014 की जाँच शुरूआत संबंधी सूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा के दौरान यथा संशोधित मूल जाँच में यथा परिभाषित उत्पाद के दायरे को परिभाषित किया है। अतः, ऐसे उत्पाद/वस्तुएं, जिन्हें उत्पाद के पूर्ववर्ती दायरे से स्पष्ट रूप से इतर या बाहर रखा गया है, पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर हैं। अतः अधिनियम की धारा 9क(5) के परंतुक के अनुसार, मूल जाँच में उत्पाद के दायरे से बाहर के किसी अन्य उत्पाद/वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को लगाने की जरूरतकी जाँच करने के लिए कोई समीक्षा(परिवर्तित/निर्णायक समीक्षा) नहीं हो सकती है। यह तर्क दिया गया है कि यह निर्विवाद कानूनी स्थिति है कि किसी वस्तु/स्थिति का जारी रहना या पुनरावृत्ति होना तब संभव है, यदि वह पहले मौजूद रही हो। ऐसे उत्पाद/वस्तुएं जिन्हें पाटित और इस प्रकार क्षतिकारी नहीं पाया गया की जाँच पाटन/क्षति के जारी रहने और/या उसकी पुनरावृत्ति होने के लिए नहीं की जा सकती है।

15. यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी हैं इसलिए वह अपने पूर्ववर्ती निर्णयों से भटक नहीं सकते हैं और सुसंगतता और अनुमेयता जो मनमाने ढंग से निर्णय लेने को नियंत्रित करती है, के लिए उन्हें अपने पूर्ववर्ती निर्णयों का पालन करना होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक प्रथा के अनुसार निरंतर माना है कि उत्पाद के

दायरे को समीक्षा में बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसे देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जॉच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को नहीं बढ़ाना चाहिए।

16. कुछ हितबद्ध पक्षों ने यह अनुरोध भी किया है कि संबद्ध वस्तु के कतिपय ग्रेडों, जो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं होते हैं, को पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी नए समामेलन या विस्तार की मांग नहीं की है। उन्होंने केवल शुल्क के संग्रहण के लिए शुल्क तालिका में दर्शाए गए अंतिम पीयूसी पर लगाई गई सीमा को हटाने का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी स्मरण कर सकते हैं कि 1250 मिमी. से अधिक की चौड़ाई (सहनशीलता सहित) को बाहर रखने का एकमात्र आधार निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में अपनी मौजूदा सुविधा से मूल जॉच में जॉच अवधि के दौरान सटीक आकारों की आपूर्ति नहीं की थी। चूंकि घरेलू उद्योग अब अपेक्षाकृत चौड़ी वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पर लगाई गई सीमा को नहीं हटाने का कोई विधिक और तार्किक कारण नहीं है।

18. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि वे सभी तैयार उत्पादों के साथ सभी ग्रेडों की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा, कतिपय ग्रेडों जिनका उत्पादन मूल जॉच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा था, को घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और आपूर्तित किया जा रहा है।

19. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि वह इस तथ्य को मानने को तैयार नहीं हैं कि प्रतिवादी निर्यातक यह दावा कर रहे हैं कि एक ओर निर्णायक समीक्षा में पीयूसी को संशोधित नहीं किया जा सकता है, जबकि वे स्वयं अपवर्जनों की मांग करके पीयूसी को संशोधित करना चाहते हैं। घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि इस समीक्षा के भाग के रूप में कोई नया अपवर्जन नहीं किया जा सकता है। तथापि, प्राधिकारी को निश्चित रूप से अधिकार है कि वे ऐसे अपवर्जनों पर शुल्क लगाएं जो हमेशा से पीयूसी का भाग थे परंतु उन्हें मूल पीओआई के दौरान आपूर्ति के न होने के कारण बाहर किया गया था।

20. घरेलू उद्योग के अनुसार बाहर रखी गई श्रेणियों को शामिल करने से पीयूसी के दायरे में बदलाव नहीं होगा। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं विशेष के हितों को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क के दायरे को सीमित किया था। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी कहा है कि कूल जॉच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लगाई गई सीमाओं को हटाया जा सकता है विशेष रूप से यदि ऐसी सीमाओं/अपवर्जनों की कारक परिस्थितियों में अब बदलाव हो गया हो। घरेलू उद्योग अपने इस तर्क के समर्थन में अनुरोध करता है कि इस समीक्षा के लिए जॉच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख था कि समीक्षा के दायरे में दिनांक 20.2.2014 की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमाशुल्क और 6.9.2011 और दिनांक 7.2.2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 86/2011 के सभी पहलू शामिल होंगे।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

21. याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि मूल जॉच में कतिपय उत्पाद किस्मों को बाहर रखने के लिए एकमात्र कारण यह तथ्य था कि उन्होंने उन ग्रेडों की आपूर्ति नहीं की थी और अब यह कि याचिकाकर्ता ने ऐसे बाहर रखे गए ग्रेडों या उन उत्पाद प्रकारों की आपूर्ति शुरू कर दी है इसलिए ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जॉच की जॉच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

समस्त श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों, जिनपर कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) से आगे कार्य न किया गया हो (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)। विचाराधीन उत्पाद में उक्त विवरण की स्टेनलेस स्टील काइल, शीटें और प्लेटें शामिल हैं। संबद्ध वस्तु का प्रयोग सफेद वस्तुओं, प्रसंस्कृत उपकरण, डेयरी उपकरण, आटोमोटिव कलपुर्जों, रेल कार्टों, मेट्रो के कोचों, वास्तुशिल्प, भवन और निर्माण आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत उपशीर्ष 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 में वर्गीकृत किया जाता है.....'

23. जॉचकी प्रक्रिया के दौरान उठाये गए विभिन्न मुद्दों की काफी विस्तृत जॉच करने के बाद

प्राधिकारी ने पीयूसी के दायरे से कतिपय ग्रेडों/विनिर्देशनों के उत्पादों को बाहर रखने के लिए कतिपय व्यापक सिद्धांतों को अपनाया है। ऐसा एक सिद्धांत यह है कि क्या हितबद्ध पक्ष द्वारा बताया गया विनिर्देशन/ग्रेड/ उत्पादन प्रक्रिया/उत्पादन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप भौतिक विशेषताओं और रासायनिक संघटन के अनुसार अलग उत्पाद का उत्पादन हुआ जिसके द्वारा स्पष्ट और उचित ढंग से उत्पाद की भिन्नता को सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह था कि क्या घरेलू उद्योग उनके उत्पाद बाजार के माध्यम से इन ग्रेडों के विनिर्माता के रूप में दावा करता है और वह पूरी पीओआई के दौरान या पीओआई से पहले भी ऐसी अलग मर्कों का विनिर्माण/आपूर्ति करता था। तीसरा यह कि क्या यह सिद्ध करने के लिए कोई तकनीकी साक्ष्य है कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद ग्रेड बाहर रखे जाने के लिए प्रस्तावित/विचारित ग्रेडों के समतुल्य थे। काफी विस्तृत सोच-विचार के बाद प्राधिकारी ने मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार पुनःपरिभाषित किया:

‘समस्त श्रृंखला के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों, जिनपर कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) से आगे कार्य न किया गया हो, तथा मोटाई 4 मिमी. तक हो (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)’

संबद्ध वस्तु (पीयूसी) में ऊपर बताए गए आधारों पर उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित अपवर्जन होंगे :

- क. मै. थाइसेनक्रुप स्टेनलैस इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड एआईएसआई 420 हाईकार्बन (0.28 प्रतिशत-0.40 प्रतिशत), ग्रेड 420, ग्रेड 430 बीए, ग्रेड एआईएसआई 441 और ग्रेड एआईएसआई 443,
- ख. डुप्लेक्स स्टेनलैस स्टील ग्रेड 2205 (एस31803), 2304 (एस32304), ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 और 1.4833 और फेरिटिक ग्रेड ईएन 1.4509 और 1.4512,
- ग. कम निकेल वाले और क्रोमियम निकेल मैंगनीज-तांबा आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील वाली वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी ताइपेई (ताइवान) के मै. याइह यूनाइटेड स्टील कार्प. (यूस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेडों वाईयू1 और वाईयू4 को दर्शाने वाले ।

24. तत्पश्चात् उत्पाद के दायरे को घरेलू उद्योग के अनुरोध पर और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों पर जून 2011 और दिसम्बर 2011 में की गई मध्यावधि समीक्षा में आगे और संशोधित किया गया और उसमें किनारे की सहनशीलता और अन्य समामेलनों/अपवर्जनों पर विचार किया गया और आज मौजूद अंतिम उत्पाद का दायरा और जिसपर शुल्क लागू है और जिसके लिए निर्णायक समीक्षा शुरू की गई है निम्नानुसार है:

समस्त श्रृंखला के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों, जिनपर कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) से आगे कार्य न किया गया हो, जिनकी चौड़ाई 600 मिमी. से 1250 मिमी. तक हो (मिल किनारे के लिए +30 मिमी. और ट्रिम्ड किनारे के लिए +4 मिमी. की चौड़ाई सहनशीलता), तथा मोटाई 4 मिमी. तक हो, जिनमें निम्न शामिल नहीं हैं:

- i. 1250 मिमी. से अधिक की चौड़ाई की संबद्ध वस्तु (सहनशीलता सहित)
- ii. ग्रेड एआईएसआई 420 उच्च कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509
- iii. कम निकेल वाले और क्रोमियम निकेल मैंगनीज-तांबा आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील वाली वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी ताइपेई(ताइवान) के मै. याइह यूनाइटेड स्टील कार्प. (यूस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रेडों वाईयू1 और वाईयू4 को दर्शाने वाले ।

विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 में बेस मेटल्स और बेस मेटल्स की वस्तुएं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और आगे सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 टैरिफ कोडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। इसका प्रयोग सफेद वस्तुओं, प्रक्रिया उपकरण, डेयरी उपकरण, आटोमोटिव कलपुर्जों, रेल कारों, मेट्रो के कोचों, वास्तुशिल्प, भवन, रसोई के उत्पादों और निर्माण आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है।

25. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर कतिपय उत्पादों को शामिल करने के संबंध में दिए गए तर्कों को नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अब उनका विनिर्माण शुरू कर दिया है और मूल जाँच परिणाम में वास्तविक आपूर्ति और उत्पादन

का मापदंड अब पूरा हो गया है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अंतिम जॉच परिणाम के समय पीयूसी से कतिपय ग्रेडों/किस्मों आदि को बाहर रखने से वास्तव में पीयूसी या जॉच के दायरे में बदलाव नहीं हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि पीयूसी के दायरे को परिभाषित करने का अनिवार्य सिद्धांत है कि क्या विशिष्ट उत्पाद आयातित किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु है अथवा नहीं। मूल जॉच में कतिपय उत्पाद ग्रेडों/किस्मों को बाहर रखने का औचित्य यह था कि समान वस्तु होने के बावजूद इन उत्पादों के इस आधार पर नुकसान पहुंचाने का अंदेशा नहीं था कि ऐसे उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जा रहे थे। अब चूंकि घरेलू उद्योग इन उत्पाद प्रकारों/ग्रेडों/आकारों का उत्पादन और आपूर्ति करता है इसलिए उन उत्पाद प्रकारों/ग्रेडों/आकारों को निरंतर बाहर रखने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

26. जबकि इस परिदृश्य में घरेलू उद्योग के तर्कों में कुछ तथ्य हैं जब उत्पाद की परिभाषा व्यापक रही हो परंतु कतिपय प्रतिबंध या अपवर्जन केवल शुल्क लगाने और उसके संग्रहण के लिए लगाए गए हों। मामले की सावधानीपूर्वक जॉच से पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे को विभिन्न निर्धारणों के लिए कार्यवाही से पहले विस्तृत चर्चा के बाद ही प्रतिबंधित किया गया है और उनके संबंध में पाटन और क्षति जॉच में केवल उन्हीं उत्पाद प्रकारों/ग्रेडों/आकारों को शामिल किया गया है। अतः ऐसा मामला नहीं है जहां पीयूसी का दायरा व्यापक बना हुआ है परंतु शुल्क को सीमित तरीके से लगाया गया है जैसा तर्क दिया गया है।

27. यह भी देखा गया है कि इस मामले में समीक्षा अंतिम जॉच परिणाम में यथा परिभाषित और उसके बाद समीक्षाओं में यथा संशोधित उत्पाद के दायरे के लिए शुरू की गई है। घरेलू उद्योग ने 2011 की तरह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में परिवर्तन करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना में बाहर रखे गए उत्पादों की जानकारी नहीं है। यहां तक कि सहयोगी हितबद्ध पक्षों से बाहर रखे गए उत्पादों से संबंधित सूचना शामिल करने के लिए नहीं कहा गया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर बाहर रखे गए ग्रेडों को शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग के तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

28. अन्य हितबद्ध पक्षों के तर्कों के अनुसार कतिपय अन्य ग्रेडों को बाहर रखने के मामले के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उन्होंने उन ग्रेडों का विनिर्माण और आपूर्ति की है। तदनुसार, कतिपय ग्रेडों को बाहर रखने के संबंध में हितबद्ध पक्षों के तर्क में कोई तथ्य नहीं है और इसलिए प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

29. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मामले में किसी हितबद्ध पक्ष ने कोई अन्य तर्क नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जाँच (यथा संशोधित) और इस जाँच के प्रयोजनार्थ उक्त पैरा 24 के रूप में यथा परिभाषित के समान ही रहेगा।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित की जा रही वस्तु के समान वस्तु है। अतः घरेलू वस्तुओं को नियमावली के अर्थ के भीतर आयात की जारी संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

31. निर्णायक समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन में, जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड ने दायर किया है जिनका जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में 83 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात् मै. बीआरजी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. का सलेम स्टील प्लांट और मै. शाह अलॉय हैं। वर्तमान जाँच में देश में किसी अन्य उत्पादक ने घरेलू उद्योग के आवेदन का कोई विरोध नहीं किया है। अतः याचिकाकर्ताओं के पास आवेदन दायर करने की योग्यता है और वह क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुसार इसके अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं। किसी उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

इ. इस जाँच में हितबद्ध पक्ष

32. उक्त पैरा 7 में उप पैरा v, vii और viii में सूचीबद्ध प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक और आयातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर और अन्य अनुरोधों के आधार पर इस जाँच में नामित देशों

की सरकारों और भारत में घरेलू उद्योग को इस जाँच में हितबद्ध पक्ष माना जा रहा है।

च. गोपनीयता के दावों के संबंध में मुद्दे

33. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों ने घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह कि याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और गोपनीय आधार पर उसके द्वारा प्रदत्त सूचना का कोई सार्थक सारांश भी उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ऐसे कारण बताने में विफल रहा है कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का सारांश क्यों नहीं किया जा सकता है। इससे प्रतिवादी याचिका में क्षति के दावों का पूरा विश्लेषण नहीं कर पाया है।

ख. याचिकाकर्ता ने याचिका के खंड VI लागत निर्धारण सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यद्यपि याचिकाकर्ता का यह दावा कि सूचनाके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को भारी लाभ मिल सकता है सही और निर्विवाद हो सकता है तथापि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता को ऐसी लागत निर्धारण सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होता है। याचिकाकर्ता लागत के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का एक ही प्रकार से उत्तर नहीं दे सकता है। जहां भी संभव हो, अनुरोधों का एक सूचीबद्ध अंश उपलब्ध कराया जाए याचिकाकर्ता उसे उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

ग. याचिकाकर्ता ने उत्पादन प्रक्रिया, खरीद नीति, बिक्री नीति, मालसूची और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया आदि भी उपलब्ध नहीं करा पाया है।

34. घरेलू उद्योग ने भी गोपनीयता के दावों और हितबद्ध पक्षों के तर्कों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह कि घरेलू उद्योग ने गोपनीयता का दावा व्यापार संवेदी सूचना के संबंध में विधिक उपबंधों और प्राधिकारी द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त कारणों के साथ किया है। गोपनीयता के दावे के कारण और आधार आवेदन के अगोपनीय अंश में दिए गए हैं। इस प्रकार, अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में कतिपय हितबद्ध पक्षों का आरोप निराधार है।

ख. यह कि निर्यातकों ने अपने उत्तर में विभिन्न स्थानों पर () या ***** रखकर कोई कारण बताए बिना महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय रखा है। निर्यातक ने गोपनीयता के दावे

वाली सूचना का कोई सारांश भी नहीं दिया है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग अपने तर्क देने और अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है।

- ग. निर्यातकों द्वारा प्रयोग किए गए उत्पाद विनिर्देशन और उत्पाद कोडिंग प्रणाली को कोई कारण बताए बिना गोपनीय रखा गया है।
- घ. यह कि सभी परिशिष्टों में मात्रा से संबंधित आंकड़े प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा गोपनीय रखे गए हैं जबकि घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी समस्त सूचना को अगोपनीय अंश में प्रस्तुत किया है।
- ङ. यह कि अलग-अलग लागत केन्द्रों के बीच लागत का आबंटन निर्यातकों द्वारा गोपनीय रखा गया है। इसके अलावा, क्या उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टियों को खरीदा जाता है या कंपनी द्वारा आबद्ध रूप से उत्पादित किया जाता है, को भी अगोपनीय अंश में नहीं बताया गया है।
- च. यह कि निर्यातकों ने पूरा बिक्री और वितरण चैनल नहीं बताया है। इस संदर्भ में, घरेलू उद्योग ने आशंका जताई है कि यह सूचना पूरी आपूर्ति श्रृंखला को छुपाने के लिए जानबूझकर गोपनीय रखी गई है। घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि यदि अगोपनीय अंश में पूरी आपूर्ति श्रृंखला बताई गई होती तो वह कारगर अनुरोध कर पाते और प्राधिकारीको अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करा पाते जिससे उनका पूरा उत्तर अस्वीकार हो सकता था।

च.1 मामले की जाँच

35. वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच और समाधान किया गया है:

36. सूचना की गोपनीयता के संबंध में घाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट

होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

37. हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की पर्याप्तता और गोपनीयता के दावे के संबंध में जाँच की गई थी। लागत निर्धारण संबंधी सूचना का प्रकटन नहीं करने के संबंध में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों की दलील के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागत और कीमत संबंधी सूचना गोपनीय प्रकृति की होती है और इसलिए आमतौर पर उसका सारांश नहीं हो सकता है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षों का दावा वैध नहीं है और इसलिए अस्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर, प्राधिकारी देखते हैं कि घरेलू उद्योग ने जबरदस्त ढंग से दलील दी है कि निर्यातकों ने उनकी मात्रा संबंधी सूचना के संबंध में कतिपयमूल सूचना का प्रकटन नहीं किया है और प्रश्नावली के उत्तर में अधिकांश परिशिष्टों को सूचीबद्ध नहीं किया है जो संबंधित पक्षों के लिए सार्थक समझ प्रदान कर सकते थे। प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों के गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी द्वारा विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा गया। तदनुसार, गोपनीयता के दावों और अगोपनीय प्रकटन के मुद्दे के संबंध में पक्षों के सभी तर्कों को निपटाया गया है।

छ. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दे

छ.1 निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

38. निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में निम्नानुसार तर्क/दलील दी है:

- i. यह कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा को पर्याप्त न्याय व्यवस्था के अभाव में नहीं चलाया जा सकता है और इसे तत्काल समाप्त किया जाए। चूंकि शुल्क 21 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो गया है और उसके समय विस्तार को दिनांक 12 मई, 2014 की अधिसूचना द्वारा ही औपचारिक किया गया है इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा को जारी रखना कानून के अंतर्गत अमान्य हो जाता है।
- ii. निर्णायक समीक्षा को समाप्त किया जाए क्योंकि समीक्षा की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जा सकती है। नियम 23(2) के साथ पठित धारा 9क(5) केन्द्र सरकार को केवल एक वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने की शक्ति देता है और निर्णायक समीक्षा उस अवधि के समाप्त होने से पहले होनी चाहिए।
- iii. यह कि निर्णायक समीक्षा की शुरुआत स्वतः नहीं की गई है बल्कि डीजीएडी से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर आधारित है। यह सूचना याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है परंतु ऐसी अपर्याप्त और गलत सूचना को पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) के अनुसार विधिवत रूप से साक्ष्यांकित सूचना नहीं कहा जा सकता है।
- iv. यह कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई याचिका में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उसे प्राप्त अपरिष्कृत आयात आकड़ों से आयात आकड़ों को कैसे निकाला है। याचिका यह बताने में भी विफल रही है कि याचिकाकर्ता ने कैसे संबद्ध उत्पाद को असंबद्ध उत्पाद से अलग किया है और क्या सभी उत्पाद किस्मों को माने गए आयात आकड़ों में शामिल किया गया है। आयात आकड़ों को चुनने के समय याचिकाकर्ता द्वारा विचारित किसी अन्य कारक के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। जब तक ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक क्षति के आरोप के संबंध में प्रदत्त सूचना की सत्यता का उचित ढंग से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

- v. यह कि घरेलू उद्योग ने निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभारों, अंतरदेशीय भाड़ा और बिक्री कमीशन या बैंक प्रभारों की श्रेणी के अंतर्गत कटौतियों का कोई साक्ष्य याचिका में नहीं दिया है।
- vi. यह कि जिंदल 80 प्रतिशत से अधिक के बाजार हिस्से के साथ भारतीय बाजार में एकमात्र प्रचालक है और उसके पास असीमित आपूर्ति और कीमत निर्धारण की शक्ति है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिंदल को हजारों प्रयोक्ता उद्योगों की कीमत पर और सीमाशुल्क आय के घाटे पर लाभ पहुंचाया जाए।
- vii. यह कि सभी संबद्ध देशों से आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हैं और इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का कोई मामला नहीं है।
- viii. यह कि पाटनरोधी शुल्क का समय नहीं बढ़ाया जाए क्योंकि इससे घरेलू उद्योग का वास्तविक एकाधिकार हो जाएगा।
- ix. यह कि प्राधिकारी को संबद्ध वस्तु की तकनीकी विशेषताओं और विभिन्न ग्रेडों के अंतिम प्रयोग में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए संबद्ध वस्तु के प्रत्येक ग्रेड के लिए पाटन और क्षति मार्जिन को निर्धारित करना चाहिए।
- x. यह कि घरेलू उद्योग को मूल जाँच में अनंतिम शुल्क लागू किए जाने से डीजीएडी से पर्याप्त संरक्षण मिला है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क का समय और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क/अनुरोध किया है कि:

- i. यह कि संबद्ध वस्तु के आयात आकड़ों को सौदा-वार आयात आकड़ों में प्रत्येक सौदे में दिए गए विवरण के आधार पर चुना गया है। पीयूसी के लिए आयात आकड़ों के संकलन का आधार याचिका में ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अलावा, अपरिष्कृत आकड़ों के स्रोत, अवधि और टैरिफ शीर्षों को आवेदन में ही दर्शाया गया है। जब तक

पीयूसी से संबंधित प्रविष्टियां और वे शीर्ष जिनसे इन्हें लिया गया है को अगोपनीय अंश में प्रकट किया जाता है तब तक अपरिष्कृत आकड़ों को बताने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यदि हितबद्ध पक्षों की दलील स्वीकार की जाती है तो इसका वस्तुतः अर्थ यह होगा कि घरेलू उद्योग को उन उप-शीर्षों के ब्योरे भी प्रस्तुत करने होंगे जिनका उपयोग आयात आकड़ों के संकलन में नहीं किया गया है।

- ii. यह कि घरेलू उद्योग ने उसके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध समस्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार निर्यात कीमत में समायोजनों का दावा किया है, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार कोई जाँच शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना गया है।
- iii. यह कि लागत के आकड़े प्रति टन के अनुसार प्रदान किए गए हैं ताकि विचाराधीन उत्पाद के अलग-अलग ग्रेडों/किसमों की लागतों और कीमतों की उचित तुलना सुकर बन सके।
- iv. यह कि हितबद्ध पक्षों का यह दावा कि निर्णायक समीक्षा को इसलिए समाप्त किया जाए क्योंकि किसी विधिक या तार्किक तथ्य के बिना समीक्षा की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक की अवधि तक नहीं चल सकती है। इस संदर्भ में, धारा 9क (5) के उपबंधों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह विहित है कि शुल्क उन्हें लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। पहले परंतुक के अनुसार इस अवधि को उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन आगे और पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरे परंतुक के अनुसार जाँच के पूरा होने तक और एक वर्ष की अवधि के लिए शुल्क संग्रह किया जा सकता है। तदनुसार, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि छह वर्ष से अधिक अवधि तक जाँच के जारी रहने पर प्रत्यक्षया अप्रत्यक्ष कोई रोक नहीं है यद्यपि दूसरे परंतुक के अंतर्गत एक प्रतिबंध यह हो सकता है कि शुल्क एक वर्ष से कम के लिए जारी रह सकता है। स्पष्ट रूप से एक वर्ष से अनधिक शब्दों को सर्वोत्तम रूप से शुल्क के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है और न कि समीक्षा जाँच के संदर्भ में।

- v. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 की ओर दिलाया है जिसमें जाँच पूरी करने के लिए 18 माह तक की अवधि की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, नियम 23(3) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के उपबंध समीक्षा जाँच पर आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे। तदनुसार, नियम 17 के उपबंध निर्णायक समीक्षा के मामले में भी लागू होते हैं। नियम 17(1) का पहला परंतुक स्पष्ट रूप से बताता है कि केन्द्र सरकार जाँच पूरी करने के लिए एक वर्ष की अवधि को छह माह तक बढ़ा सकती है।
- vi. प्राधिकारी का ध्यान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय (कुम्हो पेट्रोकेमिकल लि. बनाम भारत संघ के एनबीआर मामले में) की ओर दिलाया गया जिसमें प्राधिकारी को इस तथ्य के बावजूद जाँच को जारी रखने की अनुमति दी गई कि पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क को अलग रखा गया। यह भी अनुरोध किया गया कि धारा 9क(5), नियम 23 और 17 के उपबंधों की सुमेलित व्याख्या से ही जाँच की कार्यवाही को पूरा करने के लिए अनुमत अवधि से शुल्क के संग्रहण से अलग कर सकता है। कोई अन्य व्याख्या अनन्य रूप से धारा 9क(5) में घरेलू उद्योग को प्रदत्त निहित अधिकारों का उल्लंघन करेगी। किसी मामले में नियम 23 को इस ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है कि वह विधायिका में निहित शक्ति को समाप्त कर दे। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी नियम की व्याख्या इस प्रकार से नहीं की जा सकती है कि वह मुख्य अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल कर दे। अंतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्णायक समीक्षा के मामले में भी, कार्यवाही को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है और प्रतिषेध को ज्यादा से ज्यादा छह वर्ष की अवधि के बाद शुल्क के संग्रहण पर लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में कोई कमजोरी या कमी नहीं है।
- vii. यह कि प्राधिकारी ने संगत विचार लिया है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन समान अवसर वाला बाजार सृजित करना है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव या शुल्क को वापस लेने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका के खतरे के कारण घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना है।

- viii. यह कि एकाधिकार के हो जाने की आशंका निराधार है क्योंकि घरेलू उद्योग भारतीय घरेलू बाजार में एकमात्र कंपनी नहीं है। इसके घरेलू उत्पादकों के अलावा घरेलू उद्योग को आयातित संबद्ध वस्तु से प्रतिस्पर्धा करनी होगी जो संबद्ध देशों और अन्य देशों से भी बाजार में मुक्त रूप से उपलब्ध है। अतः हितबद्ध पक्षों के अनुरोध विधिक और वास्तविक रूप से अव्यवहार्य हैं।
- ix. आयातों का निर्धारित न्यूनतम सीमा का मापदंड निर्णायक समीक्षा जाँच पर लागू नहीं होता है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में गिरावट का कारण आयातकों द्वारा उच्चतर चौड़ाई अर्थात् केवल 1250 मिमी से अधिक चौड़ाई को लाया जाना है ताकि पाटनरोधी शुल्क से बचा जा सके। यही कारण है कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान कार्यवाही और मूल जाँच में भी प्राधिकारी से चौड़ाई के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित नहीं करने का अनुरोध किया था।
- x. यह कि संबंधित आयातक मै. पोस्को, कोरिया ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा उनके द्वारा इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उनके संबंधित आयातक द्वारा आयातक प्रश्नावली का उत्तर क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- xi. यह कि कोरिया से निर्यातक/उत्पादकों के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पूरी मूल्य शृंखला उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। पोस्को कोरिया के सभी निर्यातकों ने उत्तर नहीं दिया है और जाँच में भाग नहीं लिया है। अतः उनके उत्तरों को पूरा नहीं माना जा सकता है और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

40. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य पक्षों द्वारा उनके विभिन्न अनुरोधों में उठाए गए मुद्दों की जाँच की है। हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा मौजूदरा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जा सकता है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और माननीय न्यायालय ने माननीय दिल्ली

उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रचालन पर अंतरिम स्टे दिया है। वर्तमान मामले में, जाँच की शुरुआत शुल्क की समाप्ति से पहले हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी ही स्थिति में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने (कुम्हो पेट्रोकेमिकल लि. बनाम भारत संघ के एनबीआर मामले में) निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत को सही माना था और इस तथ्य के बावजूद जाँच को जारी रखने की अनुमति दी थी कि पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क को अलग रखा गया।

41. हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क भी दिया है कि समीक्षा की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक तक नहीं चलाई जा सकती है और इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा को समाप्त कर देना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) और नियमावली के नियम 23 की रचनात्मक व्याख्या से पता चलता है कि जाँच शुरुआत की तारीख से एक वर्ष से बाद समीक्षा जाँच को जारी रखने के संबंध में कोई विशेष रोक नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले को विभिन्न पक्षों द्वारा माननीय न्यायालयों के समक्ष उठाया गया है और न्यायालयों ने अब तक इस व्याख्या के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया है। पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों को पढ़ने के केवल सुमेलित तरीके से ही यह माना जाता है कि निर्णायक समीक्षा कार्यवाही को कानून के किसी विशिष्ट उपबंध का उल्लंघन किए बिना एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलाया जा सकता है।

42. इस मुद्दे के संबंध में कि पिछले पांच वर्षों के लिए घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है और शुल्क को जारी रखना प्रयोक्ता उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि याचिकाकर्ता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इस संरक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य एक लेवल प्लेइंग फील्ड सर्जित करना और पाटन के क्षति प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को राहत उपलब्ध कराना मात्र है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की जाँच घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि संबद्ध देशों से आयात के लिए शुल्क को जारी रखना किस प्रकार अर्थव्यवस्था अथवा देश के व्यापक हित को हानि पहुंचाएगा। तथापि, संरक्षण का मुद्दा यदि कोई हो, की संबंधित धाराओं में जाँच की गई है ताकि अवधि, जिसके बाद यह अपेक्षित है, के लिए अनुचित शुल्क नहीं लगाया गया है।

43. जहां तक निर्णायक समीक्षा के लिए अपने आवेदनों में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना की पर्याप्तता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की जांच की गई थी और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर संबद्ध जांच शुरू की गई थी। तथापि, वास्तविक निर्धारण प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों और आयातकों के वास्तविक आंकड़ों तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य तथ्यों पर आधारित है। इसलिए पक्षों के हित से समझौता नहीं किया गया है।

44. जहां तक निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के प्रस्तुतीकरण और पोस्को, कोरिया के संबंधित आयात का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिक्रिया रिकॉर्ड में है और इस मुद्दे का कोरिया से यह प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातक/उत्पादक के पाटन मार्जिन के निर्धारण में इस मुद्दे का समाधान किया गया है।

45. अपने पश्च प्रकटीकरण अनुरोधों में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षों ने जांच के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपनी-अपनी स्थितियां दोहराई हैं। जांच के लिए पक्षों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मुद्दे इस विवरणी में संबंधित खण्डों में उस सीमा तक देखे गए हैं जहां तक वे इससे संगत हैं और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहां नहीं दोहराया गया है।

46. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध में यह तर्क दिया है कि 9 सहयोगी निर्यातकों को व्यक्तिगत व्यवहार प्रदान किया जाए क्योंकि उन्होंने विभिन्न देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति में शामिल उनके संबद्ध पक्षकारों के संबंध में महत्वपूर्ण छिपाई है। यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि पोस्को, कोरिया के दो संगत आयातकों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दाखिल किया है, तीसरे संगत आयातक और पुणे स्थित प्रोसेसर ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है इसलिए पोस्को के प्रत्युत्तर को अस्वीकार किया जाए। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के निर्णय के संबंध में प्राधिकारी के हाल ही में जारी अन्तिम जांच परिणाम में उल्लेख किया है जिसमें कि कुछेक निर्यातकों के प्रत्युत्तर इस आधार पर अस्वीकार किए गए थे कि प्रतिवादी निर्यातकों की संगत कंपनियों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तरों के उत्तर दाखिल नहीं किए। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले में उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर निर्धारण के लिए आवश्यक पर्याप्त और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हैं और दाखिल की गई सूचना की अपेक्षा के अनुसार पुष्टि की गई

है । वर्तमान मामले में निर्धारण से अन्य देशों में सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के संगत पक्षकारों के कथित भाग न लेने से किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यदि किसी तीसरे देश में प्रतिवादी उत्पादक/ निर्यातक के कुछ संगत पक्षकार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल हैं उन्होंने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया है तो कथित पक्षकार गैर सहयोगी शेष शुल्कों के तहत स्वतः ही शामिल होंगे । अतः न तो निर्धारण और न ही घरेलू उद्योग का हित अन्य देशों में सहयोगी निर्यातकों के कथित संगत पक्षकारों के भाग न लेने के कारण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता । उपरोक्त को देखते हुए इस संबंध में घरेले उद्योग की आपत्तियां स्वीकार नहीं की गई हैं ।

47. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि प्रतिवादी निर्यातकों के आंकड़ों का डी जी सिस्टम के आंकड़ों से मिलान किया जाए जैसा कि अन्य मामलों में किया गया है । इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डी जी सिस्टम के आंकड़ों अथवा किसी अन्य आंकड़ा आधार के साथ मिलान का सहारा कुछेक मामलों में लिया गया है जहां निर्यातक के आंकड़ों कुछ कमियां हैं अथवा इस संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है । यह न तो कोई अनिवार्य अपेक्षा है और नही कोई सामान्य प्रक्रिया है । इस कार्य के लिए आवश्यक जांच के दौरान प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई विशिष्ट त्रुटि सामने नहीं आई ।

ज. सामान्य मूल्यों, निर्यात कीमतों और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ज.1 कानूनी स्थितियां

48. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) में व्यवस्था है कि:-

"पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा:

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी;

परंतु आगे यह कि 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व समीक्षा जांच इस प्रकार की समाप्ति से पूर्व किसी परिणाम पर नहीं पहुंची हो तो पाटनरोधी शुल्क 1 वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए इस प्रकार की समीक्षा के परिणाम के लंबित रहने तक जारी रहेगी।"

49. तदनुसार, एक निर्णायक समीक्षा जांच की जानी है:

- क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात् पाटन जारी है। यदि हां, तो क्या इसके जारी रहने की संभावना है।
- उन मामलों में जहां पाटन जारी नहीं है उनमें क्या पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी।
- क्या घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति सहन करता रहेगा। यदि हां, तो क्या यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होते रहने की संभावना है।
- उस मामले में जहां घरेलू उद्योग क्षति वहन नहीं कर रहा है वहां घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

50. इसलिए, पाटन के जारी रहने और क्षति की शुल्क निरस्त किए जाने की स्थिति में, पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने और इस प्रकार की स्थिति में क्षति के जारी रहने की संभावना अथवा पुनरावृत्ति होने की जांच करने से पूर्व इसकी जांच की गई है।

ज.2 पाटन के जारी रहने की जांच: सामान्य मूल्यों, निर्यात कीमतों और पाटन मार्जिन का निर्धारण

51. चीनी जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताइपेइ, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाली अथवा निर्यातित वस्तुओं के लिए जांच शुरू की गई थी। जांच अधिसूचना के प्रतिक्रिया में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल की हैं:

- i. मैसर्स एसेरिनाक्स एस.ए., स्पेन
- ii. मैसर्स कोलंबस स्टेनलेस (प्रा.) लि., साउथ अफ्रीका
- iii. मैसर्स पोसको, कोरिया
- iv. मैसर्स दैवू इंटरनेशनल, कोरिया
- v. मैसर्स ह्यूंडै कारपोरेशन, कोरिया
- vi. मैसर्स पोसको थाइनाक्स, थाईलैंड

52. चीनी जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेइ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रतिक्रिया फाइल नहीं की है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इन देशों/राज्य क्षेत्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन देशों/राज्य क्षेत्रों में सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग में उपलब्ध सूचना सहित उपलब्ध बेहतर सूचना के अनुसार संरचित किया जाना चाहिए।
53. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर विचार किया है और जांच के पश्चात्, जहां आवश्यक समझा गया है और सिरे से नकारा नहीं गया है, इन अनुरोधों पर आधारित निर्धारण किया है। ओसीटी (ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड टेस्ट) और पर्याप्तता टेस्ट लागू करने के पश्चात् प्रत्येक सीरीज के अंतर्गत ग्रेड दर ग्रेड तुलना करके और नियमावली के तहत निर्धारित पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य निकाला गया है। निर्यात कीमत और दावा किए गए समायोजनों की अनुरोधों के आधार पर अनुमति दी गई है और जहां अपेक्षित है, जांच की गई है।
54. संबद्ध देशों/राज्य क्षेत्रों में सहयोगी निर्यातकों और अन्य गैर-सहयोगी निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण का आधार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 06 अक्टूबर को जारी किए गए प्रकटन विवरण में प्रकट किया गया था। पद्धति और उसमें आंकड़ों की शुद्धता के संबंध में हितबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और जिस सीमा तक वे संगत हैं, इस अंतिम निर्धारण में उन पर विचार किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से वर्तमान पाटन की मात्रा और सीमा का निर्धारण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

क. चीनी जनवादी गणराज्य

55. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन के एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था होने के कारण उक्त देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य उक्त देश में विद्यमान कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए इसे संरचित किए जाने की आवश्यकता है। चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिए हैं कि:
- बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि प्रतिक्रिया देने वाली निर्यातक/कंपनी और संपूर्ण रूप से इसके समूह दावा नहीं करते। वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था विवेचन के लिए कोई दावा नहीं है। किसी भी चीनी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल नहीं की है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था विवेचन के लिए दावा किया है।
 - चीन ने सामान्य मूल्य, (क) भारत में कीमत तथा (ख) भारत में उत्पादन की लागत, विधिवत रूप से समायोजित, इसमें अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित पद्धति के अनुसार

विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ शामिल हैं, के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है और यदि निर्यातक द्वारा कोई प्रतिक्रिया फाइल नहीं की गई है तो प्राधिकारी द्वारा निरंतर इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। चीन में सामान्य मूल्य भारत में विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

- iii. चीन में सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करते हुए और खपत मानदंड और घरेलू उद्योग में उपलब्ध सूचना सहित बेहतर उपलब्ध सूचना के अनुसार परिवर्तन लागत को अपनाते हुए संरचित किया जाना चाहिए।

सामान्य मूल्य: चीनी जनवादी गणराज्य

56. प्रारंभिक चरण में प्राधिकारी की यह अवधारणा थी कि चीनी जनवादी गणराज्य एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश है। जांच प्रारंभ होने के पश्चात् प्राधिकारी ने शुरुआत की सूचना की प्रतिक्रिया देने के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी और उनके बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे के निर्धारण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खण्डन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह देने हेतु चीन सरकार से भी अनुरोध किया। तथापि, किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रतिक्रिया फाइल नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में पिछले कुछ वर्षों में चीनी जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है।
57. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और किसी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था धारणा का खण्डन नहीं किए जाने के कारण प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीनी जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानना उचित समझता है और चीनी जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है।
58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में निम्नलिखित व्यवस्था है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की

जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

59. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में प्रथम और द्वितीय विकल्पों की शर्तों के अनुसार चीन में सामान्य मुद्दों के निर्धारण की संभावना की जांच की है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि उस देश में लागत और कीमत अथवा ऐसे देश से दूसरे देशों को कीमत जिसमें भारत भी शामिल है, उपरोक्त संदर्भित पैरा 7 में प्रथम दो विकल्पों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्यों के रूप में लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में किसी उपयुक्त तीसरे देश का चयन करने के लिए कोई अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
60. इसलिए चीन में सामान्य मूल्य उपरोक्त संदर्भित नियमावली में उपलब्ध तीसरे विकल्प के अनुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है और सामान्य मूल्य प्रमुख कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के लिए अपेक्षित समायोजन करने के पश्चात् भारत में दक्ष घरेलू उत्पादक/संयंत्र के उत्पादन की लागत के आधार पर संरचित की गई है। प्राधिकारी ने अपनी सतत् प्रक्रिया के अनुसार उचित लाभ के लिए भी व्यवस्था की है। तदनुसार, चीनी जनवादी गणराज्य से आने वाली अथवा निर्यातित वस्तुओं के ग्रेडों/सीरीजों के लिए भारत औसत संरचित सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव किया है:

देश	सीरीज 200	सीरीज 300	सीरीज 400
	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी
चीन	****	****	****

निर्यात कीमतें - चीनी जनवादी गणराज्य

61. चीनी जनवादी गणराज्य से आयातित संबद्ध वस्तुओं के ग्रेडों/सीरीजों की भारत औसत निर्यात कीमत चीनी जनवादी गणराज्य के निर्यातकों से सहयोग के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार समुद्र माल भाड़ा के लिए सीआईएफ कीमत तथा बीमा, अंतर्देशीय मालभाड़ा और संभाल व्यय को समायोजित करने के पश्चात् प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि संबद्ध वस्तुओं पर @13% की दर से वैट रिफंड लागू है। इसलिए 4% वैट का भुगतान किया गया है और रिफंड नीचे दिए गए अनुसार सीरीजों में भारत औसत निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकालने के लिए समायोजित किया गया है:

ब्यौरा	यूओएम	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज
निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत	यूएसडी/एमटी

पाटन मार्जिन - चीनी जनवादी गणराज्य

62. नीचे दिए गए अनुसार पाटन मार्जिन निकालने के लिए भारत औसत निवल निर्यात कीमत के साथ सीरीज स्तर पर भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना की गई है।

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज	भारत औसत
मात्रा एमटी में	7017	743	37	7797
सामान्य मूल्य	
निर्यात कीमत	
पाटन मार्जिन	
पाटन मार्जिन %	
पाटन मार्जिन रेंज	125-135	35-45	30-40	105-115

ख. यूरोपियन यूनियन

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएण्डएस से प्राप्त की गई आयात सांख्यिकी के अनुसार और जांच की अवधि के दौरान यूरोपियन यूनियन से विश्लेषण की गई 2085 एमटी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है जिसमें 300 और 400 सीरीजें शामिल हैं। तथापि, यूरोपियन यूनियन में स्थित केवल एक उत्पादन कंपनी अर्थात् मैसर्स एसेरिनॉक्स एस.ए., स्पेन ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल की है। तथापि, प्रश्नावली यूरोपियन यूनियन में कई उत्पादकों को भेजी गई थी। इसलिए प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और नीचे दिए अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यूरोपियन यूनियन से निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

सामान्य मूल्य: एसेरिनॉक्स यूरोपा,एस.ए.यू, स्पेन (एसीरोनॉक्स)

64. एसेरिनॉक्स ग्रुप विश्व में स्टेनलेस स्टील के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक है जिसकी एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में पहुंच है और हॉट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील दोनों तरह के उत्पादों का उत्पादन करता है। इस सहयोगी उत्पादक निर्यातक द्वारा फाइल प्रश्नावली प्रतिक्रिया की उसी समय जांच की गई थी। एसेरिनॉक्स एस.ए., स्पेन संपूर्ण यूरोपियन यूनियन में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करता है और उनका उत्पादन करता है। इस जांच के प्रयोजन के लिए यूरोपियन यूनियन एकमात्र बाजार होने के कारण सभी बिक्री यू.ई. देशों के भीतर सभी ग्राहकों को होने के कारण इसे घरेलू बिक्री माना गया है। **** एमटी संबद्ध वस्तुओं के कुल यूरोपियन यूनियन के भीतर घरेलू बिक्री के **** सौदे हुए। कंपनी ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के तीन ग्रेड अर्थात् 304, 316 और 430 का उत्पादन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 300 और 400 सीरीज में संबद्ध पक्षों को बिक्री की गई **** एमटी की तुलना में घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षों को **** एमटी की बिक्री की थी। संबद्ध पक्षों के लिए औसत कीमत घरेलू बाजार में असंबद्ध पक्षों के लिए कीमत की तुलना में मामूली अधिक पाई गई है। इसलिए घरेलू बाजार में सभी बिक्री इस उत्पादक निर्यातक के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है।
65. घरेलू बिक्री सौदे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात सौदों में संबंधित ग्रेडों के साथ उचित तुलना के लिए अलग-अलग ग्रेडों के सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए कंपनी द्वारा रखी गई सत्यापित ग्रेड-वार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य कारोबारी जांच की अवधि तक के लिए अध्यधीन थे। जहां कहीं संगत निर्यातित ग्रेड की वस्तुएं घरेलू बाजार में बेची नहीं गई अथवा घरेलू लेनदेन सामान्य जांच परीक्षा पास नहीं कर पाए वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य बिक्री लेनदेनों अथवा उत्पादन की सत्यापित लागत और 5 प्रतिशत के समुचित लाभ के

आधार पर किया गया है ताकि उस ग्रेड का सामान्य मूल्य निकाला जा सके। घरेलू विक्रय कीमतें कारखाना बाह्य कीमतों का पता लगाने के लिए यथासत्पापित सभी बिक्री व्यय के लिए समायोजित की गई है। तदनुसार, पीओआई के दौरान उत्पादित एसेरिन्नॉक्स एस.ई., स्पेन द्वारा भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न ग्रेडों का कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य अलग-अलग ग्रेड स्तर पर पहले निर्धारित किया गया है और नीचे दिए अनुसार सीरीज स्तर बाद में समेकित किया गया है:

ग्रेड/सीरीज	एमटी में बेची गई मात्रा (भारत को निर्यात किए गए ग्रेडों की)	एन वी अमरीकी डॉलर/एमटी
200	शून्य	-
300	****	****
400	****	****
कुल	****	

आयातित कीमत: एसेरिन्नॉक्स एस.ए.

66. कम्पनी ने पीओआई के दौरान सीधे असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को कुल **** एमटी के 300 और 400 सीरीज को शामिल करते हुए संबद्ध वस्तुओं के केवल दो ग्रेडों का उत्पादन किया गया था। भारत को निर्यात के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष विक्रय व्यय जिसमें सम्भारिकी के लिए व्यय, बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन और क्रेडिट लागत शामिल है, नीचे दिए अनुसार भारत को निर्यात किए गए ग्रेडों/सीरीजों की कारखाना बाह्य निर्यात कीमतों का पता लगाने के लिए समायोजित की गई है:

ग्रेड	मात्रा का जोड़ (एमटी)	यूएसडी में निवल बीजक मूल्य का जोड़	कुल कटौतियों का जोड़ (यूएसडी)	कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का जोड़	निवल ईपी यूएस \$/एमटी
200	-	-	-	-	-
300	****	****	****	****	****
400	****	****	****	****	****
सकल योग	****	****	****	****	****

पाटन मार्जिन: एसेरिनाक्स एस.ए.

67. इस प्रकार निर्धारित कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य और निवल कारखाना बाह्य निर्यात मूल्य की नीचे दिए अनुसार प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु तुलना की गई है:

ग्रेड/सीरीज	एनवी यूएस \$/एमटी	निवल ईपी यूएस \$/एमटी	डीएम यूएस \$/एमटी	डीएम %
200	-	-	-	
300	****	****	****	
400	****	****	****	
भारित औसत			****	25-35%

यूरोपियन यूनियन से अन्य सभी निर्यातक

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में संबद्ध वस्तुओं के ऐसे अन्य उत्पादकों की संख्या काफी हैं जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और निर्यात किया है और मूल जांच में भागीदारी की है। तथापि, उनमें से किसी ने भी चालू समीक्षा जांच में भागीदारी नहीं की है, चूंकि ईयू में किसी भी अन्य उत्पादक और निर्यातक ने संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए यूरोपियन यूनियन के सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना और याचिका में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध बेहतर तथ्यों के आधार पर शेष गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, यूरोपियन यूनियन के गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिए अनुसार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

ग्रेड/सीरीज	निवल ईपी यूएस \$/एमटी	एनवी यूएस \$/एमटी	डीएम यूएस \$/एमटी	डीएम %
300	****	****	****	

400	****	****	****	
भारत औसत	****	****	****	50-60%

ग. दक्षिण अफ्रीका

69. डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान दक्षिण अफ्रीका से केवल **** एमटी संबद्ध वस्तु निर्यात की गई है। केवल दक्षिण अफ्रीका में उत्पादक निर्यातक अर्थात् मैसर्स कोलंबस स्टेनलेस (प्रा.) लि., दक्षिण अफ्रीका द्वारा इस समीक्षा जांच में प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल की गई है। इस कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूचना की ऑन स्पॉट जांच में भी जांच की गई थी। प्राधिकारी ने नीचे दिए अनुसार अपने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए इस सहयोग उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास किया है:

सामान्य मूल्य: कोलंबस स्टेनलेस

70. कम्पनी ने **** सौदों के लिए पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में **** एमटी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की। सभी बिक्री दक्षिण अफ्रीका में असंबद्ध ग्राहकों को की गई है। घरेलू बिक्री सौदे पाटनरोधी मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात सौदों में संबंधित ग्रेडों के साथ उचित तुलना के लिए अलग-अलग ग्रेडों के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कम्पनी द्वारा उत्पादन करने और बिक्री करने के लिए सत्यापित ग्रेड-वार लागत के आधार पर सामान्य कारोबारी जांच के परीक्षण के अधीन है। जहां कहीं समरूपी निर्यातित ग्रेड घरेलू बाजार में नहीं बेचे गए अथवा घरेलू सौदे सामान्य कारोबारी जांच के परीक्षण में स्वीकृत नहीं हुए, उनके लिए केवल लाभ योग्य बिक्री लेनदेन के आधार पर अथवा उत्पादन की सत्यापित लागत में 5% उचित लाभ जोड़ने के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। सभी प्रत्यक्ष बिक्री व्यय कारखाना बाह्य स्तर पर सामान्य मूल्य का पता लगाने के लिए घरेलू सौदों से पाट दिए गए हैं। तदनुसार, पीओआई के दौरान कोलंबस द्वारा भारत को निर्यातित विभिन्न ग्रेडों के भारत औसत कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य नीचे दिए गए अनुसार सीरीज स्तर पर अलग-अलग ग्रेड स्तरों पर और उसके बाद समेकित स्तर पर पहले निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

कोलंबस स्टेनलेस प्रा. लि., दक्षिण अफ्रीका	बिक्री की गई मात्रा (भारत को निर्यात किए गए ग्रेड)	एनवी
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी

200	****	****
300	****	****
400	****	****
योग	****	

निर्यात कीमत: कोलंबस

71. पीओआई के दौरान कोलंबस ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सभी तीन सीरीज शामिल करते हुए भारत को **** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। भारत को निर्यात के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष विक्रय व्यय जिसमें सम्भारिकी के लिए व्यय, बीमा, बैंक प्रभार और क्रेडिट लागत शामिल हैं, नीचे दिए अनुसार भारत को निर्यात किए गए ग्रेडों/सीरीज को कारखाना बाह्य निर्यात कीमतों का पता लगाने के लिए समायोजित की गई है:

कोलंबस स्टेनलेस प्रा. लि., दक्षिण अफ्रीका	मात्रा	ईपी
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी
200	****	****
300	****	****
400	****	****
योग	****	

पाटन मार्जिन: कोलंबस

72. इस प्रकार निर्धारित कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य और निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की नीचे दिए अनुसार प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु तुलना किए जाने का प्रस्ताव है:

कोलंबस स्टेनलेस	निर्यात	ईपी	एनवी	डीएम	डीएम %
-----------------	---------	-----	------	------	--------

प्रा. लि., दक्षिण अफ्रीका	मात्रा				
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%
200	****	****	****	****	
300	****	****	****	****	
400	****	****	****	****	
योग	****			****	10-20%

दक्षिण अफ्रीका से अन्य निर्यातक

73. दक्षिण अफ्रीका के अन्य सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिए अनुसार कोरिया आरपी में सहयोगी निर्यातकों द्वारा फाइल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

सीरीज	एनवी (यूएस \$/एमटी)	ईपी (यूएस \$/एमटी)	डीएम (यूएस \$/एमटी)	%
200	****	****	****	
300	****	****	****	
400	****	****	****	
कुल			****	45-55%

घ. कोरिया आरपी

74. डीजीसीआईएण्डएस द्वारा विश्लेषित आयात आंकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान कोरिया आरपी से 2306 एमटी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया था। मैसर्स पोसको कोरिया जो प्रमुख उत्पादक है और कोरिया में संबद्ध वस्तुओं का निर्यातक है, ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल की है। पीओआई के दौरान पोसको ने दो कोरियाई ट्रेडिंग कम्पनियों अर्थात् मैसर्स दैवू इंटरनेशनल और मैसर्स ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। पोसको ने अपने प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल की हैं क्योंकि उपरोक्त ट्रेडिंग कंपनियों की प्रश्नावली का उत्पादक ने समर्थन किया है। पोसको और उपरोक्त ट्रेडिंग कंपनियों के प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के

अनुसार जांच की गई थी। इस कोरियाई उत्पादक का पाटन मार्जिन उनके द्वारा फाइल प्रतिक्रियाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। कोरिया के अन्य गैर-सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सहयोगी निर्यातकों द्वारा फाइल सूचना और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

सामान्य मूल्य: पोसको, कोरिया

75. पोसको एक एकीकृत इस्पात विनिर्माता है और हॉट रोल्ड कॉयल तथा शीट, एलॉय स्टील, कोल्ड रोल्ड कॉयल तथा शीट, इलेक्ट्रिकल कॉयल, गैल्वेनाइज्ड कॉयल तथा शीट, प्लेट और वायर रॉड के साथ-साथ विभिन्न स्टेनलेस स्टील कॉयल और शीट उत्पादों सहित कार्बन स्टील उत्पादों की संपूर्ण रेंज का उत्पादन करता है। पोसको ने **** सौदों के लिए कोरिया में संबद्ध और असंबद्ध ग्राहकों को पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में ग्रेडों की विस्तृत रेंज की **** एमटी की संबद्ध बिक्री की। पोसको का एकल डिस्ट्रिब्यूशन चैनल है और अपने उत्पाद फैक्ट्री से अथवा वेयर हाउस से सीधे घरेलू उपभोक्ताओं को अपने संबंधित उत्पादों की बिक्री करता है। संबद्ध पक्ष बिक्री घरेलू बाजार में कुल बिक्री की लगभग **** प्रतिशत है। तथापि, केवल कुछ ग्रेड भारत को निर्यात किए गए हैं और भारत को बेचे गए ग्रेडों के मामले में संबद्ध पक्ष बिक्री लगभग **** प्रतिशत है और घरेलू बाजार में असंबद्ध क्रेता के लिए औसत कीमत संबद्ध पक्षों के लिए औसत कीमतों की तुलना में अधिक है। इसलिए संबद्ध पक्ष सहित भारत को निर्यात किए गए संगत ग्रेडों की सभी बिक्री और असंबद्ध बिक्री निर्यात सौदों के साथ इसी प्रकार की तुलना के लिए पोसको हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार किए गए हैं। पोसको, कोरिया ने प्रकटीकरण विवरण की अपनी टिप्पणियों में घरेलू मूल्य का निर्धारण करते समय घरेलू बिक्री लेन देन में कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है। उन त्रुटियों को दूर कर लिया गया है और तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।
76. घरेलू बिक्री सौदे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात सौदों में संबंधित ग्रेडों के साथ उचित तुलना के लिए अलग-अलग ग्रेडों के सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए कंपनी द्वारा रखी गई सत्यापित ग्रेड-वार उत्पादन लागत के आधार पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड टेस्ट के अध्यक्षीन थे। जहां कहीं समानरूपी निर्यातित ग्रेड घरेलू बाजार में नहीं बेचे गए अथवा घरेलू सौदे सामान्य कारोबारी जांच के परीक्षण में स्वीकृत नहीं हुए हैं उनके लिए उस ग्रेड के सामान्य मूल्य का पता लगाने के लिए लाभ योग्य बिक्री लेन-देन के आधार पर अथवा उत्पादन की सत्यापित लागत में 5% उचित लाभ जोड़ने के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। घरेलू बिक्री यथासत्यापित सभी बिक्री व्यय के लिए समायोजित की गई है। तदनुसार, पीओआई के दौरान भारत को पोसको द्वारा निर्यातित विभिन्न ग्रेडों का भारत औसत कारखाना बाह्य सामान्य

मूल्य अलग-अलग ग्रेड स्तर पर पहले निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और नीचे दिए अनुसार सीरीज स्तर पर बाद में समेकित किया गया है:

पोसको कोरिया	बेची गई मात्रा (भारत को निर्यात किए गए ग्रेडों की)	एन वी
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी
200	शून्य	-
300	****	****
400	****	****
कुल	****	

निर्यात कीमतें: पोसको कोरिया

77. जांच की अवधि के दौरान पोसको ने भारत को निर्यात के लिए कोरिया में दो ट्रेडरों नामतः मैसर्स दैवू इंटरनेशनल और मैसर्स ह्यूंडै कारपोरेशन को विचाराधीन उत्पाद के सीमा के भीतर **** सीआर कॉयल की बिक्री की। असंबद्ध ट्रेडर अर्थात् ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए **** एमटी का निर्यात किया गया। शेष **** एमटी की बिक्री भारत को निर्यात के लिए उनकी संबद्ध ट्रेडिंग कंपनी मैसर्स दैवू इंटरनेशनल को की गई। तथापि, वस्तुएं ट्रेडिंग कंपनियों के ग्राहकों को पोसको की उत्पादन सुविधाओं से भारत को सीधे भेजी गई जबकि वाणिज्यिक बीजक ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा भारतीय ग्राहकों को प्रस्तुत किए गए हैं। ह्यूंडै कारपोरेशन और दैवू इंटरनेशनल ने पृथक-पृथक प्रश्नावली प्रतिक्रिया फाइल की हैं। सभी प्रतिक्रिया की ऑन स्पॉट जांच के जरिए जांच की गई है। प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में निर्यातक द्वारा यथाउल्लिखित निर्यात मूल्यों की गणना में कुछेक मामूली त्रुटियों को निर्यात मूल्य के निर्धारण में शामिल कर लिया गया है।

(i) पोसको: ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए

78. ह्यूंडै कारपोरेशन ने पोसको द्वारा संरचित **** एमटी संबद्ध वस्तुओं का भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया है। निर्यात बिक्री सीआईएफ शर्तों पर है। कारखाना बाह्य कीमतों का पता लगाने के लिए पोसको और ह्यूंडै ने संभारिकी, संभाल, बीमा लागत, समुद्री भाड़ा तथा क्रेडिट लागत आदि के व्यय का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। तदनुसार, ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए पोसको द्वारा निर्यात की निवल कारखाना बाह्य कीमतें नीचे दिए गए अनुसार तैयार की गई हैं:

पोसको	ग्रेड	कुल मात्रा	निवल ईपी यूएस\$/एमटी
ह्यूंडै कारपोरेशन	200 सीरीज	-	-
	300 सीरीज	****	****

	400 सीरीज	-	-
--	-----------	---	---

(II) पोसको: दैवू कारपोरेशन के जरिए

79. पोसको ने भारत को निर्यात के लिए दैवू को **** एमटी संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति की थी। तथापि, दैवू ने विचाराधीन उत्पाद की सीमा के अनुरूप 399.888 एमटी स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों का निर्यात किया और शेष मात्रा ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार लोअर विड्थ हेतु पोसको के स्थानीय सेवा केन्द्र में उनके द्वारा स्लिट की गई थी और गैर-पीयूसी के रूप में भारत को निर्यात की गई। दैवू ने भारत में इसके संबद्ध पक्षों और असंबद्ध ग्राहकों को वस्तुओं का निर्यात किया। भारत ने संबद्ध ग्राहक अर्थात् पोसको इंडिया दिल्ली स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लि. (आईडीपीसी) और पोसको इंडिया चेन्नई स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लि. (आईसीपीसी) तथा ट्रेडिंग कंपनी अर्थात् दैवू इंटरनेशनल ने पृथक-पृथक प्रश्नावली फाइल की है। इसलिए, वह निर्यात कीमत जिस पर आईडीपीसी और आईसीपीसी द्वारा भारत में पहले वस्तुएं बेची गई थी, को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 9क(1)(ख) की शर्तों के अनुसार संरचित की गई है, के निर्धारण के लिए सभी कंपनियों को एकल कंपनी माना गया है। तदनुसार, दैवू इंटरनेशनल के जरिए निर्यातित पोसको की संरचित निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमतें नीचे दिए गए अनुसार संरचित की गईं:

पोसको	ग्रेड	मात्रा	संरचित ईपी यूएस\$/एमटी
दैवू इंटरनेशनल	200 सीरीज	-	-
	300 सीरीज	-	-
	400 सीरीज	****	****

80. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध में यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी सभी बिक्री संबंधी व्ययों और देवू और संगत आयातकों के लाभ मार्जिन की कटौती की पुष्टि करे ताकि लेन-देन में शामिल पक्षकारों के संबंधों को देखते हुए उत्पादक की पूर्व कार्यों के निर्यात कीमतों का आकलन हो सके । इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मध्यवर्ती संगत पक्षकार अर्थात् मै0 देवू और आईडीपीसी और आईसीपीसी ने बिक्री संबंधी व्ययों और लाभ को शामिल करने के लिए पर्याप्त मार्जिन पर वस्तुएं बेची ।
81. पोसको ने अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा दावा की गई शुल्क वापसी का समायोजन करने की प्राधिकारी द्वारा अनुमति

प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह समायोजन कच्चे माल/निविष्टियों पर देय ऐसे शुल्कों और करों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रदान किया गया है जिनकी वस्तुओं के निर्यात के मामले में वापसी/छूट प्रदान की जानी है। निविष्टियों के संबंध में कराधान के स्तरों में अंतर होने के कारण बिक्री कीमत में अंतर होना अनुचित कीमत व्यवहार नहीं होता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क वापसी के समायोजन का दावा भारत को निर्यातित उत्पादों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध स्पष्ट रूप से पुष्टि योग्य साक्ष्यों के साथ पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं हैं। अतः दावा स्वीकार नहीं किया जा सका।

पोसको और इसके निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

82. निर्धारित कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य और कारखाना बाह्य निर्यात कीमतें, उपरोक्त, प्रतिक्रिया देनेवाले उत्पादक और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए तुलना किए जाने के लिए नीचे दिए गए अनुसार प्रस्तावित की गई है:

उत्पादक: पोसको, कोरिया	निर्यात मात्रा	ईपी	एनवी	डीएम	डीएम %
निर्यातक: ह्यूंडै कारपोरेशन					
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	
200	-	-	-	-	
300	****	****	****	****	25-35
400	-	-	-	-	
कुल	****	****	****	****	25-35
निर्यातक: दैवू इंटरनेशनल					
सीरीज					
200	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	
400	****	****	****	****	10-20
कुल	****	****	****	****	10-20

कोरिया आरपी से अन्य सभी निर्यातक

83. कोरिया आरपी के सभी अन्य निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिए अनुसार कोरिया आरपी में सहयोगी निर्यातकों द्वारा फाइल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

अन्य सभी	ईपी	एनवी	डीएम	डीएम%
सीरीज				
200	-	-	-	
300	****	****	****	40-50%
400	****	****	****	30-40%
भारत औसत	****		****	35-45%

इ. थाईलैंड

84. विश्लेषित डीजीसीआईएण्डएस आयात आंकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान थाईलैंड से 1394 एमटी संबद्ध वस्तुएं आयातित की गई थीं। मैसर्स पोसको थाईनॉक्स, जो थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रतिक्रिया फाइल की हैं।

पोसको, थाईनॉक्स, थाईलैंड

85. पोसको थाईनॉक्स अन्य उत्पादकों से खरीदी गई एचआर/ब्लैक कॉयल से कोल्ड रोल्ड उत्पादों का उत्पादन करता है और तथा अनीलिंग तथा पिकलिंग, कोल्ड रोलिंग और सर्फेस फिनिशिंग करता है। पीओआई के दौरान पोसको थाईनॉक्स ने भारत को **** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। कंपनी ने **** एमटी संबद्ध वस्तुएं ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए निर्यात की और शेष सीधे निर्यात की गई। मैसर्स ह्यूंडै कारपोरेशन ने पोसको थाईनॉक्स द्वारा संरचित वस्तुओं के निर्यात से संबंधित सूचना भी प्रस्तुत की है। पोसको थाईनॉक्स और उपरोक्त नाम की इसकी ट्रेडिंग कंपनी की प्रतिक्रियाओं की भी प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई थी। इसलिए थाईलैंड से इस उत्पादक/निर्यातक का पाटन मार्जिन नीचे दिए गए अनुसार सहयोगी निर्यातकों द्वारा फाइल की गई प्रतिक्रियाओं तथा अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

सामान्य मूल्य: पोसको थाईनॉक्स

86. थाईनॉक्स ने विभिन्न रेंज के ग्रेडों को शामिल करते हुए घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कुल *** एमटी मात्रा की बिक्री की थी। कुल घरेलू बिक्री में से केवल *** एमटी (***) थाईलैंड में इसकी संबद्ध कंपनियों को बिक्री की गई थी। तथापि, घरेलू बाजार में बेचे गए ग्रेडों की काफी संख्या की तुलना में पीओआई के दौरान भारत को केवल छः ग्रेडों का निर्यात किया गया। इसलिए निष्पक्ष तुलना के लिए इस निर्यातक के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए भारत को निर्यात किए गए ग्रेडों को ही ध्यान में रखा गया है। घरेलू बाजार में *** एमटी तुलना करने योग्य ग्रेडों की बिक्री की गई और 100% बिक्री थाईलैंड में असंबद्ध ग्राहकों को की गई थी। घरेलू बिक्री लेनदेन पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात संबंधी लेनदेनों में संबंधित

ग्रेड के साथ उचित तुलना करने के लिए व्यक्तिगत ग्रेड के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुष्टिकृत ग्रेडवार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य कारोबारी जांच परीक्षण के अध्यक्षीन हैं। जहां कहीं संगत निर्यातित ग्रेड की वस्तुएं घरेलू बाजार में बेची नहीं गईं अथवा घरेलू लेनदेन सामान्य जांच परीक्षा पास नहीं कर पाए वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य बिक्री लेनदेनों अथवा उत्पादन की सत्यापित लागत और 5 प्रतिशत के समुचित लाभ के आधार पर किया गया है ताकि उस ग्रेड का सामान्य मूल्य निकाला जा सके। ये घरेलू बिक्री सौदे अलग अलग ग्रेड के उत्पादन की जांच की गईं लागत के अनुसार ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड टेस्ट के अध्यक्षीन हैं। निर्यातक ने कारखाना बाह्य कीमत जो ऑन स्पॉट जांच में भी सत्यापित की गई थी, का पता लगाने के लिए घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष बिक्री व्यय का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है। तदनुसार, इस उत्पादक निर्यातक का कारखाना बाह्य के सामान्य मूल्य नीचे दिए अनुसार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

पोसको, थाईनॉक्स	मात्रा एमटी	एनवी
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी
200	-	-
300	****	****
400	-	-
कुल	****	****

निर्यात कीमतें: पोसको थाईनॉक्स

87. मैसर्स पोसको थाईनॉक्स ने कुल *** टीएचबी मूल्य के लिए पीओआई के दौरान **** एमटी सौदों के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। कंपनी ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात सीधे भारत को और आरपी कोरिया में स्थित एक असंबद्ध ट्रेडिंग कंपनी ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए किया है। कंपनी ने ह्यूंडै कारपोरेशन के जरिए **** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया और शेष सीधे निर्यात की गई है। वस्तुएं भारत में ग्राहकों को थाईनॉक्स की उत्पादन सुविधा से भारत को सीधे भेजी गई है। ट्रेडिंग कंपनी के जरिए निर्यात के मामलों में केवल वाणिज्यिक बीजक भारतीय कंपनियों से ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा वसूले गए थे जबकि वस्तुएं थाईनॉक्स द्वारा सीधे भेजी गई थी। ह्यूंडै कारपोरेशन ने इन सौदों को शामिल करते हुए पृथक प्रश्नावली प्रतिक्रिया भी फाइल की है।
88. निर्यात सीआईएफ और एफओबी शर्तों पर है और भुगतान एल/सी अथवा टीटी के जरिए प्राप्त हुआ। कारखाना बाह्य कीमतों का पता लगाने के लिए थाईनॉक्स और ह्यूंडै ने संभारिकी, संभाल, बीमा लागत, समुद्री भाड़ा, जहां लागू हो, पैकिंग लागत, बैंक प्रभार, क्रेडिट अवधि के लिए क्रेडिट लागत आदि के व्यय का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। तदनुसार, थाईनॉक्स द्वारा सीधे निर्यात और ह्यूंडै कारपोरेशन की निवल कारखाना बाह्य कीमतें नीचे दिए गए अनुसार तैयार की गई हैं:

थाईनॉक्स	सीरीज	कुल मात्रा	निवल ईपी यूएस\$/एमटी
डायरेक्ट	300 सीरीज	****	****
हयूंडै	300 सीरीज	****	****
कुल		****	****

पाटन मार्जिन: थाईनॉक्स और इसके निर्यातक

89. निर्धारित कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य और निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमतें, उपरोक्त, प्रतिक्रिया देनेवाले उत्पादक और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए तुलना किए जाने के लिए नीचे दिए गए अनुसार प्रस्तावित की गई है:

उत्पादक: पोसको थाईनॉक्स	निर्यात मात्रा	ईपी	एनवी	डीएम	डीएम%
निर्यातक: डायरेक्ट					
सीरीज	एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%
200	-	-	-	-	
300	****	****	****	****	0-10%
400	-	-	-	-	
कुल	****	****	****	****	0-10%
निर्यातक: हयूंडै कारपोरेशन					
सीरीज					
200	-	-	-	-	
300	****	****	****	****	20-30%
400	-	-	-	-	
कुल	****	****	****	****	20-30%

थाईलैंड में अन्य सभी निर्यातक

90. थाईलैंड के सभी अन्य निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिए अनुसार थाईलैंड में सहयोगी निर्यातकों द्वारा फाइल प्रश्नावली प्रतिक्रिया में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

अन्य सभी	ईपी	एनवी	डीएम	डीएम%
सीरीज				
200	-	-	-	-
300	****	****	****	25-35%

400	-	-	-	-
कुल	****	****	****	25-35%

च. यूएसए

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने जांच अधिसूचना की प्रतिक्रिया नहीं दी है अथवा उस देश से संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों के निर्धारण के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, जांच किए गए आयात आंकड़ों के अनुसार इस देश से लगभग 1014 एमटी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है। इसलिए घरेलू बाजार में बेची गई और भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के बारे में और अन्य किसी सूचना के अभाव में इस देश से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

सामान्य मूल्य: यूएसए

92. किसी गैर-भागीदार उत्पादक के कारण यूएसए में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू विक्रय कीमतों के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य प्रशासन के लिए औचित्यपूर्ण वृद्धि, विक्रय और सामान्य लागत और लाभ सहित मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के दूसरे परंतुक की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया है। संभव सीमा तक इस निर्धारण के प्रयोजन के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय लागत, खपत मानदंड और घरेलू उद्योग की अंतरण लागत उपलब्ध बेहतर तथ्यों के आधार पर अपनाई गई है तथा आयात आंकड़ों में उपलब्ध सूचना पर विश्वास करते हुए भारत को निर्यात किए गए उत्पाद के संबंधित ग्रेडों/सीरीज के सामान्य मूल्य का पता लगाने के लिए 5% औचित्यपूर्ण लाभ मार्जिन जोड़ा गया है। तदनुसार, यूएसए के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सीरीज स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं:

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज
सामान्य कीमत	****	****	****

निर्यात कीमतें: यूएसए

93. यूएसए से आयातित संबद्ध वस्तुओं के ग्रेडों/सीरीज की भारित औसत निर्यात कीमतें नीचे दिए गए अनुसार इस देश से निर्यातकों के सहयोग के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार समुद्री भाड़ा तथा बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा तथा अन्य संभाल खर्चों के लिए सीआईएफ कीमतों को समायोजित करने के पश्चात् आयात आंकड़ों पर विश्वास करने के आधार पर निर्धारित किए जाने

का प्रस्ताव है।

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज
निर्यात कीमत	****	****	****

पाटन मार्जिन: यूएसए

94. यूएसए के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का पता लगाने के लिए भारत औसत निवल निर्यात कीमतों के साथ सीरीज स्तर पर भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज	भारित औसत
मात्रा	118	836	55	1009
सामान्य मूल्य	****	****	****	****
निर्यात कीमत	****	****	****	****
पाटन मार्जिन	****	****	****	****
पाटन मार्जिन %				40-50%

छ. ताइवान

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ताइवान में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने जांच अधिसूचना की प्रतिक्रिया नहीं दी है अथवा उस देश से संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों के निर्धारण के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, जांच किए गए आयात आंकड़ों के अनुसार इस देश से लगभग 322 एमटी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है। इसलिए घरेलू बाजार में बेची गई और भारत को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के बारे में और अन्य किसी सूचना के अभाव में इस देश से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

सामान्य मूल्य: ताइवान

96. किसी गैर-भागीदार उत्पादक के कारण ताइवान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू विक्रय कीमतों के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य प्रशासन के लिए औचित्यपूर्ण वृद्धि, विक्रय और सामान्य लागत और लाभ सहित मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के दूसरे परंतुक की शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई है। संभव सीमा तक इस निर्धारण के प्रयोजन के लिए कच्चे माल की

अंतर्राष्ट्रीय लागत, खपत मानदंड और घरेलू उद्योग की अंतरण लागत उपलब्ध बेहतर तथ्यों के आधार पर अपनाई गई है तथा आयात आंकड़ों में उपलब्ध सूचना पर विश्वास करते हुए भारत को निर्यात किए गए उत्पाद के संबंधित ग्रेडों/सीरीज के सामान्य मूल्य का पता लगाने के लिए 5% औचित्यपूर्ण लाभ मार्जिन जोड़ा गया है। तदनुसार, ताइवान के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सीरीज स्तर पर भारत औसत सामान्य मूल्य नीचे दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं:

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज
सामान्य मूल्य	****	****

निर्यात कीमतें: ताइवान

97. ताइवान से आयातित संबद्ध वस्तुओं के ग्रेडों/सीरीज की भारत औसत निर्यात कीमतें नीचे दिए गए अनुसार इस देश से निर्यातकों के सहयोग के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार समुद्री भाड़ा तथा बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा तथा अन्य संभाल खर्चों के लिए सीआईएफ कीमतों को समायोजित करने के पश्चात् आयात आंकड़ों पर विश्वास करने के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज
निर्यात कीमत	****	****

पाटन मार्जिन: ताइवान

98. ताइवान के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का पता लगाने के लिए भारत औसत निवल निर्यात कीमतों के साथ सीरीज स्तर पर भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

यूएसडी/एमटी	200 सीरीज	300 सीरीज	भारत औसत
मात्रा	70	252	322
सामान्य मूल्य	****	****	****
निर्यात कीमत	****	****	****
पाटन मार्जिन	****	****	****
पाटन मार्जिन %			45-55%

पाटन मार्जिन सारणी

देश / उत्पादक	सीरीज / निर्यातक	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज	भारित औसत	%
चीनी जनवादी गणराज्य						
सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	****	****	****	****	100-115
कोरिया आरपी						
पोसको कोरिया	ह्यूंडै कारपोरेशन	****	****	****	****	20-30
पोसको कोरिया	दैवू इंटरनेशनल	****	****	****		
अन्य सभी उत्पादक:	अन्य सभी निर्यातक	****	****	****	****	35-45
ताइवान						
सभी उत्पादक:	सभी निर्यातक	****	****	****	****	45-55
दक्षिण अफ्रीका						
कोलंबस स्टेनलेस	कोलंबस स्टेनलेस	****	****	****	****	10-20
अन्य सभी उत्पादक	अन्य सभी निर्यातक	****	****	****	****	45-55
थाईलैंड						
पोसको थाईनॉक्स	पोसको थाईनॉक्स	****	****	****	****	5-15
पोसको थाईनॉक्स	ह्यूंडै कारपोरेशन	****	****	****		
अन्य सभी उत्पादक	अन्य सभी निर्यातक	****	****	****	****	25-35
यूएसए						
सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	****	****	****	****	40-50
यूरोपियन यूनियन						
एसेरिनॉक्स एस.ए	एसेरिनॉक्स एस.ए	****	****	****	****	25-35
अन्य सभी उत्पादक:	अन्य सभी निर्यातक	****	****	****	****	50-60

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त निर्धारित किए गए अनुसार प्रत्येक संबद्ध देश से आने वाली अथवा निर्यात की गई वस्तुओं के पाटन का मार्जिन काफी है।

झ. घरेलू उद्योग और अनौपचारिक लिंकों को क्षति की जांच

100. जैसा कि क्षति की जांच के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में पहले ही नोट किया गया है कि प्राधिकारी को निम्नलिखित जांच करनी अपेक्षित है:

- क्या घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण क्षति वहन करता रहेगा। यदि हाँ, तो क्या पाटनरोधी शुल्क निरस्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होते रहने की संभावना है;
- उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग ने निरंतर क्षति वहन नहीं की है तो क्या पाटनरोधी शुल्क के निरस्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

101. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया है कि, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन है। तथापि, चालू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप पाटित आयात की मात्रा में गिरावट आई है और चालू पाटनरोधी शुल्क निरस्त किया जाता है तो पाटन के बढ़ने की संभावना है।

102. इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से शुल्क के निरस्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच शुरू करने से पूर्व संबद्ध देशों से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति होते रहने की जांच की है। घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति की जांच पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार है।

103. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

104. यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील, जिसका भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में बड़ा हिस्सा है, ने आवेदन फाइल किया है। नियमावली के नियम 2(ख) की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग माना गया है। इसलिए इस निर्धारण के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ता की लागत और क्षति सूचना, नियम 2(ख) में परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग संस्थापित करने की जांच की गई है।

झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के संबंध में प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों और आयातकों के मत

105. क्षति और अनौपचारिक लिंक के संबंध में अपने विभिन्न अनुरोधों में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:
- ऋषिरूप पॉलिमर्स मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए जो पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय विद्यमान थे और उस प्रकार की परिस्थितियों की तुलना वर्तमान परिदृश्य से करनी चाहिए कि क्या परिस्थितियां उस सीमा तक बदल गई हैं कि शुल्क को आगे जारी रखना अपेक्षित नहीं है।
 - मूल जांच के समय मांग में सभी संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा 34% था और मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा 42% था। तथापि, वर्तमान पीओआई में संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा मांग में अत्यधिक घटकर 5.39% हो गया है जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा अत्यधिक बढ़कर 82% हो गया है। संबद्ध देशों से इतने कम आयात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में प्रबल स्थिति में हैं इसलिए संबद्ध देशों के विरुद्ध वर्तमान समीक्षा बंद की जानी चाहिए।
 - संबद्ध आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा भारत में मांग की दृष्टि से बहुत कम है।
 - इन 5 वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुएं अत्यधिक दरों पर उपलब्ध करा रहा था और इससे प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद की पेशकश करने की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किए बिना उन्का लाभ बन रहा था। घरेलू उद्योग लेवी को जारी रखना चाहता है ताकि यह भारतीय प्रयोक्ताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था की लागत पर लाभ कमाता रहे।
 - याचिकाकर्ता की यह अवधारणा कि संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतें घट गईं क्योंकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीआर स्टील, विशेष रूप से 300 सीरीज का मूल्य निर्धारण काफी हद तक कच्चे माल की कीमतों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करना सही नहीं है।

- vi. आवेदक घरेलू उत्पादकों का यह तर्क कि वे आयात कीमतों के आधार पर अपनी कीमतें निर्धारित कर रहे हैं, पूरी तरह से गलत है। आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा फाइल की गई याचिका के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि बाजार का पर्याप्त हिस्सा और संबद्ध देशों से आयात में बाजार का हिस्सा मात्र 3.85% है। संबद्ध देशों से आयात के इस कम हिस्से की तुलना में घरेलू उत्पादकों का बाजार में हिस्सा लगभग 85% है। घरेलू उद्योग का दावा आडंबरपूर्ण है और प्राधिकारी द्वारा इसे अस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- vii. स्थानीय संबद्ध वस्तुओं की उच्च लागत के कारण प्रक्रमण उद्योग बंद होने की चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि ग्राहक उनकी वस्तुएं खरीदने में कम रुचि ले रहे हैं। यदि यह रुख जारी रहा तो डाउन स्ट्रीम उद्योग समाप्त हो जाएगा और बेरोजगारी के कारण लाखों परिवार सड़क पर आ जाएंगे।
- viii. क्षति प्राचल घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं दर्शाते क्योंकि क्षति की विश्लेषित अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री में निरंतर सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, आवेदन में उपलब्ध कराई गई बहुत ही सीमित गैर-गोपनीय सूचना से स्पष्ट रूप से यह परिणाम निकलता है कि संबद्ध देशों से आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई औपचारिक लिंक नहीं है।
- ix. अधिशेष क्षमता, उच्च ब्याज लागत और मूल्य हास लागत घरेलू उद्योग की क्षति का कारण है।
- x. याचिका में उपलब्ध कराया गया कीमत में कमी और कम विक्रय कीमत विश्लेषण पीओआई से संबंधित है और पीओआई के बाद की अवधि के लिए नहीं है। जब तक पीओआई के बाद संबंधित जानकारी की जांच नहीं की जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- xi. पिछले कुछ वर्षों के लिए याचिकाकर्ता कंपनी का लाभ और हानि खाता दर्शाता है कि 2012-13 के दौरान घरेलू उद्योग को विद्युत और ईंधन व्यय के लिए पर्याप्त राशि खर्च की है जो याचिकाकर्ता के लिए हानि का एक प्रमुख कारण था।
- xii. अनुच्छेद 11.3 के तहत निर्धारण की संभावना उपलब्ध सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर भावी घटनाक्रमों के विश्लेषण को अपरिहार्य बनाता है और इसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन की गणना अनुच्छेद 11.3 के तहत अपेक्षित बोझ वहन नहीं करेगा। आगे यह भी परिकल्पित है कि घरेलू उद्योग द्वारा फाइल की गई याचिका में पीओआई बाद के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
- xiii. हितबद्ध पक्षों ने प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को यह निर्देश देने के लिए अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा संभव निर्धारण करने में पीओआई बाद के आंकड़े प्रस्तुत करे और उन पर टिप्पणियों के लिए उसके प्रति हितबद्ध पक्षों को भी उपलब्ध कराए।
- xiv. संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य पूरी तरह से वास्तविक नहीं है।

- xv. घरेलू उद्योग ने पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अतिरिक्त, पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तर्क में कोई दम नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग में शामिल संघटकों को प्रकट किए गए बगैर-कुछ गोपनीय दृष्टिकोणों के आधार पर गैर-क्षति कीमत और परिणामी कम विक्रय कीमत निर्धारित की है। इस बात की पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर गैर-क्षति कीमतें निर्धारित नहीं की हैं। प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षों द्वारा भेजी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के तहत उपलब्ध कराए गए सिद्धांतों को लागू करके गैर-क्षति कीमतें निर्धारित करनी चाहिए।
- xvii. डीजी संरक्षण ने मार्च, 2015 में 400 सीरीज के कोल्ड रोल्ड इस्पात उत्पादों के आयात के विरुद्ध अपनी जांच में निर्णय दिया था कि घरेलू उद्योग उच्च वित्त प्रभारों और मूल्य हास प्रभारों जैसे आंतरिक कारणों की वजह से क्षति वहन कर रहा है जिससे प्रचालनात्मक हानि होती है और न कि आयात के कारण क्षति वहन कर रहा है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

106. क्षति तथा अनौपचारिक लिंकों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी कृपया मूल और निर्णायक समीक्षा जांच के बीच मूलभूत अंतर स्पष्ट करें। मूल जांच में प्राधिकारी को जांच की अवधि के दौरान विद्यमान पाटन और पाटित आयात के बीच संबंध तथा घरेलू उद्योग को उसके कारण हुई क्षति सिद्ध करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ, पाटन, चालू क्षति और उनका अनौपचारिक संबंध निर्णायक समीक्षा में संगत नहीं है। यह मत और कानून की व्याख्या कई मामलों में निर्णायक समीक्षा के समरूप और कार्यक्षेत्र के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा अपनाई गई है।
- ii. किसी निर्णायक समीक्षा में, जहां पाटन के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है और क्षति निर्धारित की जानी अपेक्षित है, भारत में चालू आयात के महत्व को इसकी पृष्ठभूमि में संभावना का निर्णय लेते समय इसे कम करती है।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आयात बहुत कम हैं, असंगत है क्योंकि बहुत कम आयात का सिद्धांत, निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में लागू होता है। इस परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग ने आगे यह निवेदन भी किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातक, भारत में 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई की वस्तुओं को ला कर शुल्कों को मात कर दे रहे हैं, जब कि ये मूल जांच में शुल्कों की श्रेणी से बाहर थीं। इसी तथ्य

के कारण कि 1250 एमएम से कम चौड़ाई की वस्तुओं के आयात कम प्रतीत होते हैं क्योंकि चौड़ाई का पारस्परिक रूप से प्रयोग किया जाता है।

- iv सही और उचित तुलना करने के लिए सभी संबद्ध देशों के लिए ग्रेड-वार/शृंखला-वार विश्लेषण किया जाना चाहिए। जहां तक कीमत में कटौती करने, कम कीमत पर बिक्री करने आदि सहित कीमत का विश्लेषण करने का संबंध है, घरेलू उद्योग, निर्यातकों के प्रस्ताव से भी सहमत है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से घरेलू उद्योग ने पहले से ही सभी संबद्ध आंकड़े और विश्लेषण, प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिए हैं।
- v घरेलू उद्योग ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार सभी सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने सभी साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर ही अंतिम समीक्षा जांच शुरू की है। घरेलू उद्योग पुनः आग्रह करता है कि उसकी याचिका, नियमावली के नियम 93 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार विधि की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- vi संबद्ध देशों से निर्यातकों ने घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए इस आरोप का खंडन नहीं किया है कि निर्यातक संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन कर रहे हैं। यह संपुष्ट सिद्धांत है कि निरंतर पाटन किया जाना, इस तथ्य का एक बहुत अच्छा संकेतक है कि यदि शुल्कों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में निरंतर पाटन होते रहने की संभावना बनी रहती है।
- (vii) आयात के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य, घरेलू कीमतों में गंभीर कटौती कर रहा है। इसके अतिरिक्त पाटित और क्षति पहुंचाने वाले आयातों की मौजूदगी में घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की कीमतें, अत्यधिक कम हो जाती हैं।
- viii संबद्ध देशों से निर्यातकों ने मात्रा संबंधी कोई सूचना प्रदान नहीं की है और इसलिए घरेलू उद्योग, उनके दावों और अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी से किसी भी प्रकार का अनुरोध करने अथवा उनकी सहायता करने में असहाय महसूस करता है।
- (ix) घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करवाने के प्रयोजनार्थ अपने आवेदन पत्र में गैर-क्षति कीमत निर्धारित करने और उसे प्रस्तुत करते समय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण किया है। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की बारीकी से

जांच की है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने अनुबंध - 3 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया है, गलत है और दर्ज तथ्य के विपरीत है।

- x कम कीमत पर बिक्री करना अत्यधिक सकारात्मक है और इसलिए यदि प्राधिकारी पाटन-रोधी शुल्क को वापस लेने के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उस स्थिति में संबद्ध देशों से ऐसी क्षतिपूर्ण कीमतों पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरंतर वृद्धि होने की पूरी संभावना है।
- xi क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है जो कि एक ऐसा स्पष्ट संकेतक है, जिससे पता चलता कि यदि प्राधिकारी, पाटन-रोधी शुल्क को वापस लेने के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ऐसी संभावना है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित और क्षतिपूर्ण आयात निरंतर जारी रहेंगे।
- xii विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xiii व्यापार की ऐसी कोई प्रतिबंधित प्रक्रिया नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण बनी हो।
- xiv उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही निकट भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए प्रोद्योगिकी में विकास, क्षति का कोई कारक नहीं है।

1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 107. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा गया है और इस जांच के संबद्ध भाग में रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच की गई है। तथ्यों और आंकड़ों से संबंधित सभी संबद्ध मुद्दों का निदान, क्षति का विश्लेषण करते समय स्वयमेव हो जाता है।
- 108. जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिए हैं, निर्णायक समीक्षा जांच के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच, मध्यावधि जांच और निर्णायक समीक्षा जांच के अधिकार क्षेत्र वस्तुतः भिन्न होते हैं और इन्हें विभिन्न अपील न्यायालयों द्वारा सुपरिभाषित और सु-निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ऐसे निर्धारित सिद्धांतों

का निरंतर अनुपालन कर रहे हैं और इस जांच में भी उन्हीं सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है। जबकि निर्णायक जांच समीक्षा में आयातों के वर्तमान स्तर, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की भी जांच की जाती है, लेकिन विशेष ध्यान इस तथ्य पर संकेन्द्रित होता है कि यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तो उसके क्या संभावित प्रभाव होंगे। तदनुसार हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आयातों की मात्रा कम है अथवा बहुत न्यूनतम है और इसलिए जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, युक्ति संगत नहीं है। न्यूनतम श्रेणी के सिद्धांत, निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में लागू नहीं होते हैं।

109. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस आशय के निवेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग भारत में अपना एकाधिकार स्थापित रखने के लिए पाटन-रोधी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहा है, यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी कानून का उद्देश्य अन्य देशों से उत्पादकों की अनुचित व्यापारिक प्रक्रियाओं के खिलाफ वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के संरक्षण द्वारा भारतीय बाजार में वस्तुओं के उत्पादन और खपत के क्षेत्र में समान अवसर पैदा करना है। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादन के आधार के अस्तित्व को बनाए रखना और उसकी सुस्थिरता, सामान्य आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे क्षति पहुंचाने वाले पाटन से सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में पाटन-रोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करना नहीं है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाले आयातों सहित अन्य आपूर्तिकर्ताओं से आयातों को भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने से रोकते नहीं हैं। तथापि, प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में घरेलू उत्पादकों की लागत और कीमत के चलन की स्थिति की जांच एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से की है ताकि घरेलू उद्योग की चिन्ताओं का निदान करने के लिए क्षति और कारणात्मक संपर्क पर निष्कर्ष निकाला जा सके।
110. विभिन्न पक्षकारों के आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान सत्यापित आंकड़ों और सूचनाओं को जिस हद तक आवश्यक और व्यवहारिक समझा गया है, उनका इस जांच में उपयोग किया गया है।

111. हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के संबंध में कि संभावित विश्लेषण की जांच के लिए जांच पश्चात आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के पश्चात भी पर्याप्त समय तक पाटन-रोधी शुल्क लगे हुए थे और इसलिए इस अवधि के दौरान के आंकड़े प्रवृत्तियों के बारे में कोई स्पष्ट संकेत प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी संभावित विश्लेषण के संबद्ध भागों में जिस हद तक ऐसे आंकड़े उपलब्ध थे और जितना आवश्यक समझा गया है, विभिन्न प्राचलों पर जांच पश्चात अवधि के आंकड़ों की पर्याप्त रूप से जांच की गई है।
112. हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण लागत और ईंधन आदि में अत्यधिक मूल्यहास होना था, यह कहना है कि उनके इस तर्क को नोट कर लिया गया है और घरेलू उद्योग की गैर-क्षति कीमत का परिकलन करते समय उनका उपयुक्त रूप से निदान किया गया है। इसलिए इन कारकों से यदि कोई क्षति हुई है, तो उसके लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।
113. यहां तक 400 श्रृंखला के कोल्ड-रोल्ड स्टील उत्पादों के आयात के प्रति जांच करने में डीजी सुरक्षा कवच के परिणामों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियां भिन्न प्रकृति की हैं और इस जांच के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पाद के एक भाग के बारे में हैं। वर्तमान जांच, लागू पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच करना है तथा इस जांच का कार्यक्षेत्र पूर्णतया भिन्न है। तथापि, प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों को नोट किया है और मौजूदा मामले में उनकी तथ्यपरक मापदंड के अनुसार उपयुक्त ढंग से जांच की है।
114. जांच अवधि पश्चात के आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकटन के उपयुक्त भाग में पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण करने के लिए जांच अवधि पश्चात के आंकड़ों की उपयुक्त ढंग से जांच की गई है।
115. इस जांच के बारे में पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी अन्य मुद्दों का उपयुक्त स्थलों पर निदान किया गया है और इसलिए उन्हें यहां नहीं दोहराया जाता है।

अ. वर्तमान क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

116. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 2 में निम्न दो बिंदुओं की उद्देश्य पूर्ण जांच करने का प्रावधान निहित है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और सदृश वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों के मात्रा के प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को इसकी जांच करनी आवश्यक होती है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णतया स्थिर अथवा भारत में उत्पादन या खपत की अपेक्षाकृत अत्यधिक वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को इसकी जांच करनी आवश्यक होती है कि क्या भारत में सदृश उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्यधिक कटौती हुई हैं अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों में अत्यधिक श्रेणी तक हास हुआ है अथवा इनसे कीमतों में वृद्धि होनी रुकी है, जो कि अन्यथा कुछ श्रेणी तक हो सकती थी ।
117. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संबद्ध कारकों और सूचकों पर नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है, जिनमें बिक्री, लाभों, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट आना, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, पूंजी की व्यवस्था या निवेश करने की क्षमता शामिल हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले समस्त आर्थिक प्राचलों की निम्नलिखित पैराओं में जांच की गई है ।
118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, चीनी ताईपाई, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की कथित संभावना होने तथा उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करने के लिए ही यह समीक्षा जांच शुरू की गई है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में वस्तुएं पाटित कीमतों पर निरंतर प्रवेश कर रही हैं तथा पाटित आयातित वस्तुओं और घरेलू सदृश वस्तुओं के बीच परस्पर प्रतिस्पर्द्धा होने की स्थिति बनी रहती है, ऐसे आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है ताकि इनसे होने वाली क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की जा सके । इसलिए प्राधिकारी पाटित आयातों के प्रभाव की तदनुसार जांच करने की कार्यवाही शुरू करते हैं ।

(क) पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव

119. पाटित आयातों की मात्रा के बारे में प्राधिकारी को इस पर विचार करना आवश्यक होता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णतया स्थिर अथवा भारत में उत्पादन या खपत में अपेक्षाकृत अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

(i) आयात की मात्रा और आयातों में हिस्सा

120. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार-आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों/क्षेत्रों और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा की जांच की है । सेन-डिस्क मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार-आयात आंकड़ों को जनता की जानकारी के लिए भी उपलब्ध कराया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद, श्रेणी शुल्क विभाग के शीर्ष 7219 के अंतर्गत आते हैं और इनका आयात विभिन्न चौड़ाई के विभिन्न आकारों में किया जाता है, जबकि इस जांच में विचारार्थ शामिल किए गए उत्पाद, 600 से 1250 एमएम की चौड़ाई मात्र के हैं । इसलिए आयात आंकड़ों की उचित आधार पर छंटाई की गई है, ताकि विचाराधीन उत्पादों के लिए आयात की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके । तदनुसार उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार क्षति की जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा निम्नानुसार है : -

वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
चीन जन.गण.	मी.टन	1996	4257	9092	7797	4117	8235
चीनी ताईपाई	मी.टन	176	289	211	322	216	432
यूरोपीय यूनियन	मी.टन	1948	3285	3248	428	1204	2407
कोरिया गण. जन.	मी.टन	14626	20596	2583	1188	376	752
दक्षिण अफ्रीका	मी.टन	624	33	56	166	551	1102
थाईलैंड	मी.टन	797	729	1320	1376	624	1248
संयुक्त राज्य अमरीका	मी.टन	97	512	1399	1014	904	1808
संबद्ध देशों से आयात (मी.टन)	मी.टन	20264	29701	17909	12291	7992	15984
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	88	61	39	79
अन्य देशों से आयात (मी.टन)	मी.टन	24588	31566	48593	38556	18034	36068
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	198	157	73	147
कुल आयात (मी.टन)	मी.टन	44852	61267	66502	50847	26026	52052
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	148	113	58	116
आयातों में संबद्ध देशों का % हिस्सा	%	45%	48%	27%	24%	31%	31%
आयातों में अन्य देशों का % हिस्सा	%	55%	52%	73%	76%	69%	69%

121. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों से कुल आयात में लगभग 12 % की गिरावट आई है, हालांकि चीन जन.गण. से इनमें चार गुणा से भी अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कोरिया गण.जन. से आयात में प्रमुख गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि क्योंकि विचाराधीन उत्पादों की चौड़ाई संबंधी प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए इन देशों में निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पादों के अधिक चौड़ाई के उत्पादों अथवा ऐसे उत्पादों को उनकी चीरी हुई (स्लिट) दशाओं निर्यात किया है। इसलिए हालांकि विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा कम है, कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के वास्तविक आयात काफी अधिक होंगे।

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को चौड़ाई के प्रतिबंध के साथ परिभाषित किया गया है। इसलिए यह समीक्षा जांच केवल उतनी ही चौड़ाई के उत्पादों तक ही सीमित है। तथापि, ऐसी संभावना है कि विनिश्चित चौड़ाई से अधिक चौड़ाई वाले उत्पादों के काफी निर्यात हो सकते हैं और कुछेक मामलों में यह नोट किया गया है कि वस्तुओं को वास्तविक रूप से कम चौड़ाई का बनाने के लिए चीरा (स्लिट किया) गया है तथा उनका निर्यात ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किया गया है। वास्तव में आयात के आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि विनिश्चित चौड़ाई की श्रेणी से बाहर के उत्पादों के आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है :-

1250 एमएम से अधिक चौड़ाई	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात वार्षिकीकृत
चीन जन.गण.	मी.टन	616	144	7737	18942	17848	19188	16202
चीनी तार्ईपाई	मी.टन	2326	896	5988	6871	2114	1591	13877
यूरोपीय यूनियन	मी.टन	10612	8960	23735	23757	19604	16422	28952
कोरिया गण. जन.	मी.टन	2818	234	4688	10276	27554	28523	3611
दक्षिण अफ्रीका	मी.टन	2596	1278	1606	1861	3359	2143	2561
थाईलैंड	मी.टन	716	59	1451	1585	979	788	3424
संयुक्त राज्य अमरीका	मी.टन	252	249	1598	6263	7889	8197	8513
संबद्ध देशों से आयात (मी.टन)	मी.टन	19936	11820	46804	69555	79346	76852	77140
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	235	349	398	385	387

123. उपरोक्त आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि हालांकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से समग्र कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयात में काफी वृद्धि हुई है, विचाराधीन उत्पादों के आयात में गिरावट आई है, जब कि इस जांच के अधिकार क्षेत्र से बाहर के उत्पादों के आयात में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 300 % तक की वृद्धि हुई है। वास्तव में कारोबार-वार आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि कुछ किस्मों/ग्रेड/शृंखलाओं के उत्पादों के आयात के बदले विचाराधीन उत्पादों के

अंतर्गत शामिल की गई चौड़ाई से अधिक चौड़ाई वाले उत्पाद के पूर्णतया आयात होने लगे हैं जो कि घरेलू उद्योग के तर्कों की पुष्टि करते हैं ।

124. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्धपक्षकारों के इस आशय के तर्क कि संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा कम है और इसलिए इनका घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही प्रतीत नहीं होते हैं।

(ii) मांग और बाजार का हिस्सा

125. देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का अनुमान, भारतीय उत्पादकों और समस्त स्रोतों से आयातों की घरेलू बिक्रियों के योग फल के रूप में लगाया गया है । मांग में प्रवृत्ति और घरेलू उद्योग का हिस्सा तथा कुल मांग में पाटित आयात निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात	जांच अवधि पश्चात वार्षिकीकृत
आवेदक की घरेलू बिक्रियां	मी. टन	121191	147564	177949	209827	138446	276893
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	147	173	114	228
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	34124	38844	56119	58925	32500	65000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	164	173	95	190
संबद्ध देशों से पाटित आयात	मी. टन	20264	29701	17909	12291	7992	15984
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	88	61	39	79
अन्य देशों से आयात	मी. टन	24588	31566	48593	38556	18034	36068
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	198	157	73	147
कुल आयात	मी. टन	44852	61267	66502	50847	26026	52052
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	148	113	58	116
भारत में कुल मांग	मी. टन	200167	247675	300570	319599	196972	393945

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	150	160	98	197
मांग में संबद्ध देशों का % हिस्सा	%	10.12	11.99	5.96	3.85	4.06	4.06
मांग में अन्य देशों का % हिस्सा	%	12.28	12.74	16.17	12.06	9.16	9.16
मांग में घरेलू उद्योग का % हिस्सा	%	60.55	59.58	59.2	65.65	70.29	70.29
मांग में अन्य घरेलू उत्पादकों का % हिस्सा	%	17.05	15.68	18.67	18.44	16.5	16.5
कुल		100	100	100	100	100	100

126. उपरोक्त आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में अच्छी वृद्धि हुई है और क्षति की जांच अवधि के दौरान मांग में लगभग 60 % की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में लगभग 5 % की समग्र वृद्धि हुई है तथा संबद्ध देशों के हिस्से में लगभग 6 % की गिरावट आई है। तथापि, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में गिरावट आई है, जबकि विचाराधीन उत्पादों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि हुई है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद में यथा परिभाषित चौड़ाई वाले उत्पादों के बदले ऐसे अन्य उत्पादों के आयात होने लगे हैं जिनकी चौड़ाई उन उत्पादों से अधिक है, इसलिए केवल संबद्ध वस्तुओं के आधार पर मांग और बाजार के हिस्से का विश्लेषण, घरेलू उद्योग पर बाजार के हिस्से के रूप में पाटित आयातों के प्रभाव और पाटित आयातों से बाजार के हिस्से में गिरावट की सही मात्रा की सही छवि प्रस्तुत नहीं करता है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिए गए हैं, वे सही प्रतीत नहीं होते हैं।

(ख) पाटित आयातों का कीमत प्रभाव घरेलू उद्योग पर प्रभाव

127. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में सदृश उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी हास करता है अथवा कीमत में वृद्धि होने को रोकता है जो कि अन्यथा कुछ श्रेणी तक होती । इसलिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत हास होने और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है ।
128. इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की भारित औसत लागत, निबल बिक्री वसूली (एनएसआर) और गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) की तुलना, संबद्ध देशों से आयात के औसत पहुंच मूल्यों से की गई है । घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अदा किए गए करों, प्रदत्त छूटों, डिस्काउंट्स और कमीशन को समंजित किया गया है । आयातों के पहुंच मूल्यों का निर्धारण, संबद्ध देशों से तदनरूपी ग्रेड-वार और श्रृंखला-वार आंकड़ों को ध्यान में रख कर किया गया है ।

(i) कीमत कटौती के प्रभाव

129. जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, कीमत कटौती का विश्लेषण करने के लिए संबद्ध वस्तुओं की भारित औसत घरेलू बिक्री कीमतों की तुलना, संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्यों से की गई है । संचयी स्तर पर सभी संबद्ध देशों से आयातों की कीमत कटौती निम्नानुसार है : -

देश	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देश	मात्रा मी. टन	20,263	29,700	17,908	12,291	15983

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	88	61	79
निबल बिक्री वसूली	रूपए/ मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	140	131	131
पाटन रोधी शुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रूपए/ मी. टन	98,277	91,355	1,19,979	93,429	113900
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	122	95	116
कीमत में कटौती	रूपए/ मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	0 - 10	0 - 10	15-25	40-50	15-25
पाटन रोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रूपए/ मी. टन	105670	97631	134719	108203	138274
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	127	102	131
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रूपए/ मी. टन	(****)	****	****	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	%	(****)	****	****	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	श्रेणी	(5) - 5	0 - 10	0 - 10	20 - 30	(5) - 5

130. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए बिना ही संबद्ध देशों से आयात, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं और क्षति की जांच अवधि के दौरान ऐसी कीमत कटौती के स्तर में काफी वृद्धि हुई है, हालांकि इसी अवधि के दौरान आयात की मात्राओं में गिरावट आई है, इस तथ्य के बावजूद

कि आयात में समग्र वृद्धि हुई है, यदि हम परिभाषित चौड़ाई की श्रेणियों से बाहर के आयात पर विचार करें ।

131. हालांकि हुई क्षति का विश्लेषण, संचयी रूप से किए जाने की आवश्यकता है, प्रवृत्तियों को देखने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश/क्षेत्रों से आयातों की भी जांच की गई है । पृथक देशों से आयात के भारित औसत पहुंच मूल्य की तुलना, समान ग्रेडों/शृंखलाओं की संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निबल बिक्री वसूली से किए जाने पर पृथक देश के स्तर पर कीमत कटौती के मार्जिन का आकलन नीचे किया गया है ।

चीन जन. गण.	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	0-10	25-35	15-25	65-75	0-10
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	(****)	****	****	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	%	(****)	****	****	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	(5) - 5	0 - 10	0 - 10	20 - 30	(5) - 5
चीनी ताईपाई						
कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	(****)	(****)	(****)	****	****
कीमत में कटौती	%	(****)	(****)	(****)	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	(10) - 0	(10) - 0	(5) - 5	0-10	45-50
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	(****)	(****)	(****)	(****)	****
पाटन रोधी शुल्क	%	(****)	(****)	(****)	(****)	****

सहित कीमत में कटौती						
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	(20)- (10)	(15)- (5)	(10)-0	(10)-0	15-25
यूरोपीय यूनियन						
कीमत में कटौती	रुपए/ मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	0-10	0-10	10-20	20-30	0-10
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	(****)	(****)	(****)	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	%	(****)	(****)	(****)	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	(15) - (5)	(10) - 0	(5) - 5	0 - 10	(15) - (5)
कोरिया गण. जन.						
कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	0-10	0-10	0-10	25-35	0-10
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	(****)	****	****	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	%	(****)	****	****	****	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	(10) - 0	0 - 10	0 - 10	15 - 25	(25) - (15)
दक्षिण अफ्रीका						
कीमत में कटौती	रुपए/मी. टन	****	****	****	****	****

कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	15-25	50-60	50-60	15-25	15-25
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रूपए/मी. टन	(****)	****	****	(****)	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	%	(****)	****	****	(****)	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	(10) - 0	25 - 35	20 - 30	(10) - 0	(15) - (5)
थाईलैंड						
कीमत में कटौती	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	15-25	5-15	40-50	20-30	40-50
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	%	****	****	****	****	****
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	5 - 15	0 - 10	25 -35	5 - 15	25 -35
संयुक्त राज्य अमरीका						
कीमत में कटौती	रूपए/मी. टन	****	****	****	(****)	****
कीमत में कटौती	%	****	****	****	(****)	****
कीमत में कटौती	श्रेणी	0-10	65-75	25-35	(5)- 5	25-35
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	रूपए/मी. टन	(****)	(****)	(****)	(****)	(****)
पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	%	(****)	(****)	(****)	(****)	(****)

पाटन रोधी शुल्क सहित कीमत में कटौती	श्रेणी	(45) - (35)	(35) - (25)	(35) - (25)	(40) - (30)	(25) - (15)
-------------------------------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

132. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका से आयातों को छोड़ कर क्षति की जांच अवधि के दौरान पाटन-रोधी शुल्क लगाए बिना ही संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातों के पहुंच मूल्य, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं। पाटन-रोधी शुल्क लगा कर भी कुछेक देशों की कीमत कटौती का मार्जिन सकारात्मक रहा है।

(ii) कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव

133. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच भी पाटित आयातों के कीमत कटौती के प्रभावों के संदर्भ में की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आयात आंकड़ों के ग्रेड-वार और श्रेणी-वार विश्लेषण के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों के भारत औसत पहुंच मूल्यों की तुलना, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समान ग्रेडों की गैर-क्षति कीमतों के भारत औसत से की गई है जिसके लिए जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा गया है।

जांच अवधि	इकाई	संबद्ध देश जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
मात्रा	मी. टन	12291	15983
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130
गैर-क्षति कीमत	रुपए/मी. टन	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100
पहुंच मूल्य	रुपए/मी. टन	93429	113900
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100
पाटन रोधी शुल्क के बिना कम कीमत पर बिक्री	रुपए/मी. टन	****	****

कम कीमत पर बिक्री	%	****	****
कम कीमत पर बिक्री	श्रेणी	45-55	35-45
पाटन रोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रूपए/मी. टन	108203	138274
कम कीमत पर बिक्री	रूपए/मी. टन	****	****
कम कीमत पर बिक्री	%	****	****
कम कीमत पर बिक्री	श्रेणी	25 - 35	10-20

134. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की भारत औसत पहुंच कीमत, संबद्ध वस्तुओं के समान ग्रेड के लिए घरेलू उद्योग की औसत गैर-क्षति कीमतों से काफी नीचे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम कीमत पर काफी बिक्री हुई है। जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री काफी सकारात्मक रही है। समान पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने पर भी कम कीमत पर समग्र बिक्री का मार्जिन काफी अधिक है।

135. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्येक देश से भारत औसत पहुंच मूल्य की समान ग्रेड के औसत एनआईपी के साथ तुलना करके प्रवृत्तियों को देखने के लिए पृथक देशों की कम कीमत पर बिक्री करने के मार्जिन की भी जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	चीन	चीनी ताईपाई	यूरोपीय यूनियन	कोरिया	दक्षिण अफ्रीका	थाई लैंड	संयुक्त राज्य अमरीका
मात्रा	मी. टन	7797	322	428	1188	166	1376	1014
भारत औसत गैर- क्षति कीमत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****	****	****
पाटन-रोधी शुल्क बिना भारत औसत पहुंच मूल्य	रूपए/मी. टन	76557	142421	146243	80562	138866	120695	155939
कम कीमत पर बिक्री	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****	****	****
कम कीमत पर बिक्री	%	****	****	****	****	****	****	****

कम कीमत पर बिक्री	श्रेणी	70-80	15-25	30-40	20-30	30-40	35-45	5-15
पाटन-रोधी शुल्क सहित भारित औसत पहुंच मूल्य	रूपए/मी. टन	81942	164986	171898	84254	177348	135583	244766
कम कीमत पर बिक्री	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****	****	(****)
कम कीमत पर बिक्री	%	****	****	****	****	****	****	(****)
कम कीमत पर बिक्री	श्रेणी	60 - 70	0 - 10	10 - 20	15 - 25	0 - 10	15 - 25	

136. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान जांच किए गए प्रत्येक देश से आयात के पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की गैर-क्षति कीमत से काफी नीचे बने रहे हैं। हालांकि पाटन-रोधी शुल्कों के साथ भी पहुंच मूल्य, संयुक्त राज्य अमरीका से आयातों को छोड़ कर, एनआईपी से काफी नीचे रहे हैं।

(iii) कीमत हास और न्यूनीकरण के प्रभाव

137. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत हास और न्यूनीकरण के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली की प्रवृत्ति को तुलना, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेची गई समान ग्रेडों/शृंखलाओं की संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की लागत से की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

200 शृंखला	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात
बिक्रियो की लागत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	117	115	123
बिक्री कीमत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	103	106	109

300 श्रृंखला	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात
बिक्रियों की लागत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	106	109	117
बिक्री कीमत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	93	88	93

400 श्रृंखला	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात
बिक्रियों की लागत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	114	129	139
बिक्री कीमत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	103	106	117

138. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में 200 श्रृंखला के लिए लगभग 23 प्रतिशत, 300 श्रृंखला के लिए 17 % और 400 श्रृंखला के लिए 39 % की वृद्धि हुई है, लेकिन इस अवधि के दौरान बिक्री कीमतें कम बनी रही हैं और बिक्रियों की लागत में वृद्धि होने के समनुरूप उनमें वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक प्राचलों की जांच

139. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 2 में यह अपेक्षित है कि क्षति का निर्धारण करने में सदृश उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की लक्ष्य परक जांच करना निहित होगा। इस नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और सूचकों का लक्ष्य परक और गैर-पक्षपाती मूल्यांकन किया जाएगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें बिक्री, लाभों, आउटपुट, बाजार के हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट आना, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, माल सूचियों, रोजगार, वेतन, पूंजी की व्यवस्था और निवेश करने की क्षमता शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के विभिन्न प्राचलों की जांच की गई है जो कि निम्नानुसार है।

(i) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

140. याचिकादाता घरेलू उद्योग का कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों का उत्पादन के लिए मूलतः केवल एक यूनिट है जो कि हिसार में स्थित है। कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों का उत्पादन करने के लिए दूसरा यूनिट वर्ष 2011 में ओडिसा में स्थापित किया गया था जिसने जनवरी, 2012 से उत्पादन करना शुरू कर दिया था। परवर्ती अवधि में इस नए यूनिट की क्षमताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए इन संयंत्रों की कटिबद्ध क्षमताएं नहीं हैं क्योंकि ये संयंत्र केवल 1699 एमएम के रोल का उत्पादन करते हैं। इसलिए क्षति की जांच अवधि के दौरान इन संयंत्रों में विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन रोल्ड उत्पादों के लिए क्षमताओं को उनके उत्पाद के अनुपात के आधार पर प्राप्त की गई है। तदनुसार घरेलू उद्योग की क्षमताओं, उत्पादन और बिक्रियों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
कोल्ड रोलिंग की क्षमता	मी. टन	2,75,000	3,87,500	7,25,000	7,25,000	7,25,000
विचाराधीन उत्पाद की क्षमता	मी. टन	2,00,696	2,11,768	4,39,009	4,74,994	552525
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	219	237	275
उत्पादन	मी. टन	1,60,949	1,91,821	2,51,299	2,96,611	356072
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	156	184	221
क्षमता उपयोग	%	80	91	57	62	64
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	71	78	80
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	121191	147564	177949	209827	276893
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	147	173	228

141. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमताओं में लगभग 137 % की तथा उत्पादन में लगभग 84 % की वृद्धि हुई है। इसलिए आधार वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। लेकिन विगत वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।

142. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में लगभग 74 % की वृद्धि हुई है क्योंकि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान

उत्पादन के साथ-साथ मांग में भी वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री की मात्रा में यह वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में केवल 5 % हुई है जबकि मांग में लगभग 60 % की वृद्धि हुई है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मांग और उत्पादन की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग क्षति की जांच अवधि के दौरान 5 % अधिक हिस्सा अधिप्राप्त करने में सक्षम हुआ है।

143. तथापि, जैसा कि पहले नोट किया गया है, उत्पाद की मांग कम निरूपित की जाती है क्योंकि आयात की पर्याप्त मात्रा, विचाराधीन उत्पाद के अधिकार क्षेत्र से बाहर चौड़े उत्पादों में परिवर्तित हो गई है। इसलिए घरेलू उद्योग में क्षमता संवर्धन, देश में समग्र फ्लेट रोल्ड उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि के अनुरूप हुआ प्रतीत होता है।

(ii) लाभप्रदता, लाभ, निवेश पर प्रतिफल और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

144. क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य-निष्पादन को, निवेश के प्रतिफल और ब्याज पूर्व और पश्चात लाभ/हानि तथा नकदी लाभ के रूप में नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
भारित औसत बिक्री कीमत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	97	97	99
भारित औसत लागत	रूपए/मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	111	115	123
लाभ	लाख रूपए	****	(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-588	-802	-1286	-2372
लाभ/हानि	रूपए/मी. टन	****	(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-483	-546	-743	-1038
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रूपए	****	(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-90	-115	-226	-541
नकदी लाभ	लाख रूपए	****	(****)	(****)	(****)	(****)

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-214	-250	-413	-1091
आरओसीई	%	****	(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-79	-85	-146	-227

145. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान जब कि प्रति इकाई बिक्रियों की भारित औसत लागत में लगभग 15 % की वृद्धि हुई है, इसी अवधि के दौरान प्रति इकाई कीमत वसूली में लगभग 3 % की गिरावट आई है जिसके परिणाम स्वरूप आधार वर्ष में लाभप्रद स्थिति से निबल हानि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान ब्याज पूर्व लाभ में भी काफी गिरावट आई है और यह जांच अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया है। इस अवधि में नियोजित पूंजी पर नकद लाभ और प्रतिलाभ भी नकारात्मक हो गया है।

146. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन की लागत में वृद्धि और उसके परिणाम स्वरूप हुई घरेलू क्षति क्षति का कारण ओडिसा स्थित यूनिट में क्षमता संवर्धन रहा है जो कि क्षति की जांच अवधि के दौरान प्रचालन की ढलान पर था। प्राधिकारी नोट करते हैं गैर-क्षति कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन से उत्पादन की लागत, अतिरिक्त लागत के लिए सामान्य हो जाती है, यदि यह प्रचालन की ढलान के कारण और ओडिसा में स्थापित संयंत्र का कम उपयोग होने के कारण होती है। इन कारकों के कारण लागत के सामान्य हो जाने पर भी जांच अवधि के दौरान विचारार्थ उत्पाद की बिक्रियों की लागत, पाटित आयातों के प्रभाव को दर्शाती है।

(iii) बाजार हिस्से पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

147. जैसा कि विगत तालिकाओं में दर्शाया गया है, आधार वर्ष में भारत में उत्पाद की मांग में घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा, पूर्णतया 5 % की वृद्धि दर्शाता है, जबकि इसी अवधि के दौरान मांग में लगभग 60 % की वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि हालांकि क्षमताओं में संवर्धन होने और पाटन-रोधी संरक्षण उपलब्ध होने पर भी उद्योग, मांग में हुई इस वृद्धि से पर्याप्त लाभ उठा पाने में असमर्थ रहा है।

(iv) माल सूचियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

148. नीचे तालिका में दिए गए आंकड़ें दर्शाते हैं कि मांग में वृद्धि होने के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध माल सूची के स्तर में लगभग 46 % की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
औसत स्टॉक	मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	146	182

(v) रोजगार, उत्पादकता और वेतन पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

149. क्षति होने के संकेतकों के रूप में रोजगार, वेतन और उत्पादकता की दृष्टि से घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
उत्पादन	मी. टन	1,60,949	1,91,821	2,51,299	2,96,611	356072
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	156	184	221
कर्मचारी	संख्या	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	182	229	229
उत्पादन/कर्मचारी	मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	86	80	97
दैनिक उत्पादकता	मी. टन	447	533	698	824	989
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	156	184	221
वेतन/कर्मचारी	रुपए	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	132	154	157

150. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार का स्तर दुगुना हो गया है, जो कि इस अवधि के दौरान संवर्धित क्षमता के अनुरूप है। लेकिन उत्पादन ऐसी संवर्धित क्षमता के साथ गति नहीं बनाए रख सका है, जिसके फलस्वरूप प्रति कर्मचारी की उत्पादकता में गिरावट आई है। तथापि, दैनिक की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति व्यक्ति वेतन में वृद्धि, वेतन स्तरों में सामान्य वृद्धि होने के कारण हुई है।

(vi) विकास पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

151. घरेलू उद्योग के विभिन्न वास्तविक और वित्तीय प्राचलों की जांच करने से ऐसा पता चलता है कि मांग, उत्पादन और बिक्रियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद आधार अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग के लाभ, नकद लाभ के साथ-साथ निवेश के प्रतिलाभ की दृष्टि से घरेलू उद्योग का नकारात्मक विकास हुआ है। मुख्य प्राचलों में विकास निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध	-	10.43	-33.4	5.29
लाभ	सूचीबद्ध	-	-19,792	-6,160	-13,941
नकद लाभ	सूचीबद्ध	-	-19,685	-2,250	-10,200
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	सूचीबद्ध	-	-20.89	4.46	-2.3

152. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि क्षमता में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग को लाभ में अत्यधिक वृद्धि होने, पर्याप्त नकद प्रवाह होने और निवेश पर प्रतिलाभ के बढ़ने की प्रत्याशा थी। लेकिन घरेलू उद्योग निरंतर पाटित आयातों की उपस्थिति होने, आयात की काफी मात्रा का अधिक चौड़ाई के उत्पादों की ओर परिवर्तित हो जाने और संबद्ध देशों से कीमत दबाव होने के कारण वह इन्हें अधिप्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका है।

(vii) पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनेक देशों से पाटित आयातों से पाटन-रोधी शुल्कों के संरक्षण के अंतर्गत तथा देश में सामान्य बृहत्-आर्थिक परिस्थितियों के कारण मांग में हुई स्वस्थ वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की खपत में वृद्धि होने के कारण क्षति की जांच अवधि के दौरान पर्याप्त पूंजी निवेश होने से क्षमताओं में उल्लेखनीय संवर्धन हुआ है। घरेलू उद्योग ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि यदि संबद्ध देशों से पाटित और क्षति पहुंचाने वाले आयातों को, पाटन-रोधी शुल्कों के बिना देश में प्रवेश दिया जाना जारी रहता है तो इससे समस्त निवेश खतरे में पड़ जायेंगे। इससे घरेलू उद्योग की आगे निवेश करने की क्षमता काफी प्रभावित होगी क्योंकि निवेश की गई पूंजी के वर्तमान प्रतिलाभ नकारात्मक हैं।

(viii) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

154. उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि मांग में अच्छी वृद्धि हुई है। हालांकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा कम है और ये अभी भी उत्पादन की लागत से कम कीमतों पर और घरेलू उद्योग की कीमतों से कम बिक्री कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण कीमत में काफी कटौती हो रही है और भारतीय बाजार में कम कीमत पर बिक्री हो रही है। साथ ही यह भी नोट किया गया है कि जबकि संबद्ध देशों से 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले उत्पादों के आयातों में वृद्धि हुई है, पाटन-रोधी शुल्क के अध्यक्षीन वस्तुओं के आयात में काफी गिरावट आई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमतें, संबद्ध देशों से निरंतर पाटित आयातों के बने रहने के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गई वस्तुओं के बड़े हुए आयात से प्रभावित है।

(ix) पाटन का स्तर और पाटन मार्जिन

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है, हालांकि इस अवधि के दौरान पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के कारण संबद्ध देशों से आयात की मात्रा बहुत कम थी।

ट. वर्तमान क्षति और आकस्मिक संपर्क का समग्र मूल्यांकन

156. विभिन्न कारकों के उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान मांग में अच्छी वृद्धि होने से घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्य-निष्पादन में क्षमता, उत्पादन और संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों की दृष्टि से सुधार हुआ है। तथापि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के अपने घरेलू प्रचालनों में वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है जो कि प्रत्यक्षतः संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत दबाव के कारण प्रतीत होती है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटों और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ के रूप में निरंतर आर्थिक क्षति हो रही है।

157. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को ऐसी क्षति अन्य कारकों के कारण हुई है और उसका संबद्ध देशों से आयात होने से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि इन देशों से आयातों की मात्रा बहुत कम है। प्राधिकारी ने गैर-आरोपित कारकों को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों की जांच की है।

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमतें

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच किए जा रहे देश के अतिरिक्त अनेक देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात हो रहा है। नीचे तालिका में ऐसे आयात की मात्रा और उनकी कीमत की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश	मी. टन	20263	29700	17908	12291
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	88	61
अन्य देश	मी. टन	24588	31566	48593	38556
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	198	157
आयातों की भारित औसत सीआईएफ					

कीमत					
संबद्ध देश	रुपए/मी. टन	92,538	86,021	1,12,973	87,973
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	122	95
अन्य देश	रुपए/मी. टन	1,09,985	1,10,502	1,14,004	1,03,149
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	104	94

159. उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संबद्ध देशों की तुलना में अन्य देशों से आयातों की कीमतें अधिक हैं। इसलिए अन्य देशों से आयात ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन प्रभावित हो रहा है।

160. जैसा कि पहले नोट किया गया है, संबद्ध देशों से आयात, विचाराधीन उत्पादों के अंतर्गत शामिल की गई वस्तुओं से ऐसी अन्य वस्तुओं पर अंतरित हो गए हैं जिनकी चौड़ाई विचाराधीन उत्पादों के कार्य-क्षेत्र से अधिक है और ऐसे आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ii) मांग में संकुचन और/खपत के पैटर्न में परिवर्तन

161. यह नोट किया जाता है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग, आधार वर्ष से निरंतर बढ़ी है, जिससे देश में इनकी अच्छी मांग होने का पता चलता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध वस्तुओं के खपत के पैटर्न में ऐसा परिवर्तन होने के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। वास्तव में सामान्य आर्थिक कार्य-निष्पादन में विकास होने से संबद्ध वस्तुओं की खपत में वृद्धि होने की प्रत्याशा है, जो कि अच्छी मांग होने की स्थिति से परिलक्षित होती है। इसलिए मांग में संकुचन होना अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन होना, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के प्रभावित होने का कारक नहीं है।

(iii) व्यापार की प्रतिबंधित प्रक्रियाएं तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता घरेलू उद्योग, भारत में संबद्ध वस्तुओं का मुख्य उत्पादक है। वस्तुएं स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं और संबद्ध देशों सहित अनेक देशों से इन वस्तुओं के आयात किए जा रहे हैं। जांच के दौरान किसी भी पक्षकार ने व्यापार की प्रतिबंधित अथवा प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाओं का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

(iv) प्रोद्योगिकी में विकास

163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में ऐसा पता नहीं चला है कि प्रोद्योगिकी में ऐसा कोई विशेष परिवर्तन हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(v) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

164. क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था :-

वर्ष	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात (वार्षिकीकृत)
उत्पादन	मी. टन	1,60,949	1,91,821	2,51,299	2,96,611	356072
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	156	184	221
कर्मचारी	संख्या	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	182	229	229
उत्पादन/कर्मचारी	मी. टन	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	86	80	97
दैनिक उत्पादकता	मी. टन	447	533	698	824	989
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	156	184	221
वेतन/कर्मचारी	रूपए	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	132	154	157

165. उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग का बहुत अच्छा निर्यात- निष्पादन रहा है और निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, निर्यात-निष्पादन यहां प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्य-निष्पादन पर ही विचार किया है और घरेलू उद्योग के निर्यात - निष्पादन के कारण उसे यदि कोई क्षति हुई हो तो उसके लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

166. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधोंमें यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार यह उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि, आयात निरंतर कम हो रहे हैं लेकिन घरेलू उद्योग को हो रहे नुकसानों में वृद्धि हो रही है। अतः स्पष्ट तौर पर भारतीय घरेलू उत्पादकों के क्षति मापदंडों की प्रवृत्ति और संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और कीमतों के बीच कोई सह संबंध नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय घरेलू उत्पादकों को कथित क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि यद्यपि, संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उपरांत कमी आई है, लेकिन कथित उत्पादों के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो स्पष्ट तौर पर यह प्रमाणित करता है कि आयातों का शुल्क के दायरे से बाहर की ओर अंतरण हुआ है जिससे शुल्क का प्रभाव शून्य हो गया है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई सह संबंध नहीं है।

ठ. वर्तमान क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

167. विगत भागों में यथा उल्लिखित क्षति के विभिन्न प्राचलों और गैर-क्षति के प्राचलों की जांच करने से पता चला है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में अच्छी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने क्षमता का संवर्धन किया है जो कि बढ़ रही मांग के समनुरूप है तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी याचिकादाता उद्योग क्षमता का निरंतर कम उपयोग होने से नुकसान उठा रहा है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों से कीमत में निरंतर कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर कम कीमत पर बिक्री होने का प्रभाव पड़ रहा है तथा घरेलू उद्योग की कीमतों में निरंतर हास हो रहा है जिसके कारण उसे वित्तीय घाटे हो रहे हैं। इसलिए घरेलू उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी के साथ-साथ मूल जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र से बाहर की श्रृंखलाओं के आयातों की मात्रा में परिवर्तित हो जाने के कारण उत्पादन की लागत को वसूल करने के लिए लाभप्रद कीमतें वसूल कर पाने में निरंतर असमर्थ है। उपरोक्त गैर-जिम्मेदार विश्लेषण से ऐसे किसी कारक का पता नहीं चलता है जिसके कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो सकती हो। इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों/क्षेत्रों से निरंतर पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हो रही है।

ड. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा आवृत्ति होने की संभावना की जांच

168. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में निरंतर पर्याप्त रूप से प्रवेश करती रहेंगी हालांकि शुल्कों को लगाए जाने के बाद ऐसे आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई है। विगत भाग में क्षति की जांच से भी ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से बहुत कम कीमतों पर ऐसे आयात, जिनके खिलाफ पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाते हैं, के कारण हो रही क्षति से निरंतर पीड़ित रहेगा। नियमावली में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी इस तथ्य की जांच करेगा कि क्या पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या ऐसी संभावना है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति निरंतर जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी।

ड 1. घरेलू उद्योग के विचार

169. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदन में यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादों का पाटन होना निरंतर जारी है और हालांकि पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, फिर भी पाटन मार्जिन सकारात्मक है। यह भी निवेदन किया गया है कि यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त भी कर दिया जाता है तो भी संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादों के पाटन के अत्यधिक बढ़ने की संभावना है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निवेदन किया गया है कि-

- (क) घरेलू उद्योग पहले से ही क्षति से पीड़ित है और पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना होगी जिससे कीमत में हास होगा और यह न्यूनतम हो जाएंगी।
- (ख) संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास व्यापक और बेशी क्षमताएं विद्यमान हैं और यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो वे इन क्षमताओं का उपयोग, अत्यधिक पाटन करने के लिए करने लगेंगे। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की बेशी क्षमताएं होने के ऐसे दावे की पुष्टि करने के लिए *स्टेनलेस स्टील प्लेट प्रोडक्ट्स मार्केट आउटलुक्स* में प्रकाशित आंकड़ों से कुछ सूचना प्रस्तुत की है। साथ ही यह निवेदन भी किया है कि इन देशों में व्याप्त क्षमताएं होने और उनकी तुलना, घरेलू क्षमताओं, उत्पादन, बिक्रियों और भारत में मांग से करने से

संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संभावित खतरे तथा देश में बड़ी मात्रा में पाटित आयातों की निश्चित संभावना का आभास होने लगेगा। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की क्षमताओं और उत्पादन के अनुमानित आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(हजार मी. टन)

विवरण/देश	चीन	यूरोपीय यूनियन	कोरिया	संयुक्त राज्य अमरीका	ताईवान	थाईलैंड	दक्षिण अफ्रीका
भारतीय मांग	324	324	324	324	324	324	324
संबद्ध देशों/क्षेत्रों में क्षमता	13755	4460	1986	2776	1668	300	545
क्षमता उपयोग	78%	65%	54%	50%	75%	67%	57%
संबद्ध देशों/क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता	22%	35%	46%	50%	25%	33%	43%
संबद्ध देशों/क्षेत्रों में स्थानीय मांग	8519	2428	782	1284	677	272	164.6
संबद्ध देशों/क्षेत्रों से वर्तमान निर्यात	486	448	293	116	567	185	129
बेशी क्षमता	3026	1561	914	1375	424	100	234
निर्यात के लिए उपलब्ध निबल मात्रा	3512	2009	1207	1491	991	100	398.6
भारतीय मांग के % रूप में उपलब्ध क्षमता	1084%	620%	372%	460%	306%	31%	123%

ग. कि भारतीय मांग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की समेकित क्षमता का केवल 1% है और यदि शुल्कों में विस्तार नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वे भारतीय बाजार में अपने उत्पादों का पाटन जारी रखेंगे।

घ. कि वर्ष 2009 में जब प्रारंभिक शुल्क लगाया गया था, 7114 केएमटी की तुलना में जांच अवधि के दौरान चीन में क्षमता 93% बढ़कर 11473 केएमटी हो गई। जांच अवधि के पश्चात अर्थात् 2015 तक चीन के उत्पादकों ने वर्ष 2013 की तुलना में 25% और क्षमता जोड़ ली है। यह भी निवेदन किया गया है कि उसी अवधि के दौरान उनके निर्यातों में 266% की वृद्धि हुई और वह भी तब जबकि उनका औसत प्रचालन स्तर 78% से 82% के बीच था। यदि शुल्क की अवधि का विस्तार न किया गया तो चीन अकेला ही हमारे घरेलू बाजार की मांग को पूरा कर सकता है। आगे यह अनुरोध किया गया है कि यदि उसकी अप्रयुक्त क्षमता से उत्पादित संबद्ध वस्तु को

मौजूदा कीमतों पर भारत में भेज दिया जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी। अपने दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने चीन में संबद्ध वस्तु की क्षमताओं और अन्य विवरणों के संबंध में निम्नानुसार सूचना प्रस्तुत की है:

	इकाई	2009	2013	2015
क्षमता	मी.टन	7114	11473	14370
क्षमता उपयोग	%	73	78	72
अप्रयुक्त क्षमता	%	27	22	28
निवल निर्यात	मी.टन	-303	504	541
बेशी क्षमता से उत्पादन	मी.टन	1921	2524	4024
निर्यात हेतु उपलब्ध निवल मात्रा	मी.टन	1618	3028	4565
भारतीय मांग का %	%	499	934	1408

ग. कि कोरिया में उत्पादकों की निर्यातानुमुखता बहुत अधिक है और 2009 से 2013 में इस देश से निर्यात में 63% वृद्धि हुई है। उक्त अवधि के दौरान कोरिया के उत्पादकों ने अपनी क्षमता में 10% की वृद्धि की, तथापि वे केवल 50% से 55% की औसत रेंज में प्रचालन कर रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि यदि कोरिया के लिए शुल्क की अवधि में विस्तार नहीं किया गया तो लगभग 40% की अप्रयुक्त क्षमता के साथ वहां के निर्यातक निश्चय ही क्षतिकारक एवं पाटित कीमतों पर अपनी निर्यात की मात्राओं में वृद्धि करेंगे। यह भी तर्क दिया गया है कि विशेष रूप से 400 श्रेणी में कोरिया से अधिक चौड़ाई वाले रॉल्स जो पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर हैं, के आयात पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर किए जा रहे हैं, यह उनकी संभावित कीमतों का उत्तम संकेतक है।

घ. कि यूरोपीय संघ उन स्थापित और संघनित बाजारों में से है जहां उनके घरेलू उपयोग के लिए क्षमताएं तथा उनका उपयोग स्थिर बना हुआ है। वर्ष 2009 की तुलना में 2013 और 2015 में ईयू से निर्यातों में क्रमशः 52% और 74% वृद्धि हुई। इस निर्यातानुमुखता के साथ-साथ यह

तथ्य कि उनके पास लगभग 35% अप्रयुक्त क्षमता है जिसका तात्पर्य 1561 केएमटी उत्पादन है, भारतीय मांग का 482% बनता है। यदि मौजूदा कीमतों पर इस बेशी क्षमता का केवल एक हिस्सा भारतीय बाजार को भेजा जाए तो इससे घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि ईयू के निर्यातक भी चीन और ताइवान से पाटित एवं क्षतिकारक आयातों से प्रभावित हैं और वे अपनी वस्तुओं का पाटन करने के लिए निर्यात बाजार का विकल्प तलाश कर रहे हैं ताकि वे कम से कम अपनी स्थूल लागत प्राप्त कर सकें। इस स्थिति में घरेलू उद्योग को लगातार पाटित एवं क्षतिकारक आयातों से सुरक्षित रखने के लिए ईयू के लिए शुल्कों की अवधि में विस्तार करना बहुत आवश्यक है।

ड. कि दक्षिण अफ्रीका में संबद्ध वस्तु की खपत उनकी क्षमता का केवल 29% है जिसका तात्पर्य यह है कि उनकी क्षमता का 71% निर्यातों के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि इस 71% क्षमता का अर्थ 387 मी. टन (के.टी. में) है जो भारत में स्थानीय मांग से अधिक है। यदि मौजूदा कीमतों पर यह मात्रा भारत को भेजी जाए तो यह अवश्यंभावी है कि घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा।

च. कि थाइलैंड विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है और संबद्ध वस्तु की उनकी स्थानीय खपत में कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। अतः इस बात की संभावना है कि वे भारतीय बाजार में जहां कि अच्छी दर से वृद्धि हो रही है, अपने उत्पादों का पाटन करेंगे।

छ. कि चूंकि ताइवान और यूएसए के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर क्षति की संभावना का निर्धारण करना है। ताइवान और यूएसए की संयुक्त क्षमता भारतीय मांग का लगभग 1372% है। यह भी निवेदन किया गया है कि ताइवान और यूएसए के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए आरोपों को कोई चुनौती नहीं मिली है क्योंकि संबंधित सरकारों ने भी क्षति की संभावना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है और न ही घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का विरोध किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ताइवान और यूएसए के विरुद्ध शुल्कों की अवधि में भी विस्तार किया जाना चाहिए।

ज. कि भारत जैसा कीमत के लिए संवेदनशील बाजार वैश्विक बाजार में ऐसे आर्थिक परिदृश्यों में

पाटित और क्षतिकारक आयातों से अधिक प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थितियों में लागू पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनः शुरू होने की पूरी संभावना होगी।

झ. कि उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में भी वृद्धि होना अवश्यंभावी है जो कि इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बावजूद पाटित आयात जारी हैं।

ट. कि शुल्क के अधिरोपण के पश्चात आयातों में कमी और ऐसे आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन शुल्क को वापस लिए जाने पर पाटन की संभावना को दर्शाता है और यह अपने-आप में पाटनरोधी शुल्क की अवधि में विस्तार को उचित ठहराता है।

ठ. कि संबद्ध वस्तु के आयातों में 1250 मि.मी. से अधिक चौड़ाई की मात्रा बढ़ गई है और वह भी संबद्ध वस्तु से कम कीमतों पर। पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद 600 मि.मी. से 1250 मि.मी. चौड़ाई और 1250 मि.मी. से अधिक चौड़ाई वाली संबद्ध वस्तु का अनुपात (71:29) से बदलकर (15:85) हो गया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि जब उक्त ग्रेड शुल्क अधिरोपण योग्य विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं थी तब वर्ष 2010-11 में ग्रेड ईएन 1.4512 के आयात में 87% हिस्सा 600 मि.मी. से 1250 मि.मी. चौड़ाई का था। तथापि, दिनांक 07.02.2012 का शुद्धिपत्र जिसमें ग्रेड ईएन 1.4512 को पाटनरोधी शुल्कों के दायरे में लाया गया था, जारी किए जाने के बाद इस ग्रेड में 1250 मि.मी. से अधिक चौड़ाई वाली संबद्ध वस्तु का आयात किया जाने लगा जिसका हिस्सा 99% तक था। इस तथ्य से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यदि शुल्क वापस ले लिया जाए तो निर्यातक फिर से वस्तु को 1250 मि.मी. के दायरे में ले आएंगे। अतः शुल्क की अवधि का विस्तार किया जाना चाहिए।

ड. कि यूरोपीय संघ ने दिनांक 24 मार्च 2015 के विनियमन कार्यान्वयन आयोग (ईयू) 2015/501 के जरिए चीन एवं चीनी ताइपेई के विरुद्ध प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए हैं और चीन के लिए 24.3% से 25.2% और चीनी ताइपेई के लिए 10.9% से 12% तक पाटनरोधी शुल्क लगाया है। ऐसे मामले में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से इन देशों के विनिर्माताओं/निर्यातकों को संबद्ध वस्तु के पाटन के लिए मुक्त बाजार पहुंच उपलब्ध होगी और तदनुसार, पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की अत्यधिक संभावना

होगी।

ढ. कि संबद्ध देशों से भारत से इतर देशों को कीमत के आधार पर परिकलन किए जाने पर भी सकारात्मक एवं अत्यधिक क्षति और पाटन मार्जिन बनते हैं।

ण. कि शुल्क को वापस लिए जाने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की पूरी संभावना है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने से संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारत में संबद्ध वस्तु के पाटन के लिए मुक्त बाजार पहुंच उपलब्ध होगी

3.2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

170. हितबद्ध पक्षों ने अपने अभ्यावेदनों में तर्क दिया है:

क. कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि पाटन और क्षति के जारी रहने की कोई संभावना है।

ख. कि घरेलू उद्योग ने याचिका में जांच पश्चात की अवधि के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है, अतः हितबद्ध पक्ष घरेलू उद्योग के जांच पश्चात की अवधि के निष्पादन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

ग. हितबद्ध पक्षों ने घरेलू उद्योग के इन दावों का विरोध किया है कि संबद्ध देशों में भारी क्षमता मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप इन देशों से पाटन और संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। यह तर्क दिया गया है कि केवल भारी क्षमता की मौजूदगी पाटनरोधी शुल्क की अवधि में विस्तार का आधार नहीं हो सकती जैसाकि अपीलीय निकाय ने भी माना है। याचिकाकर्ताओं को भारी क्षमताओं की मौजूदगी का ठोस साक्ष्य देना चाहिए और डीजीएडी को केवल कयासों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

171. प्राधिकासी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग एवं हितबद्ध पक्षों के तर्कों को नोट किया है। वर्तमान जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियमानुसार प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की

समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण के कारण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात की मात्रा में गिरावट आई। तथापि आयात आंकड़ों से यह देखा गया है कि क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान 1250 मि.मी. से अधिक चौड़ाई वाली संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि हुई। अतः घरेलू उद्योग के इस दावे में सच्चाई है कि संबद्ध वस्तु के आयात अधिक चौड़ाई वाली संबद्ध वस्तु की ओर चले गए हैं जिससे विचाराधीन उत्पाद जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, के दायरे में आने वाली वस्तु के आयात की मात्रा में कृत्रिम रूप से कमी हुई है। सभी हितबद्ध पक्षों के दावों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने मुद्दों की जांच यह देखने के लिए की है कि क्या क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दों की जांच की गई है:

(i) संबद्ध देशों से मौजूदा और पूर्व पाटन मार्जिनों का स्तर

172. पूर्व खण्डों में की गई जांच से संकेत मिलता है कि इस तथ्य के बावजूद कि पाटनरोधी शुल्क लागू है, संबद्ध देशों/क्षेत्रों से मौजूदा पाटन मार्जिन का स्तर अत्यधिक है। मूल जांच में भी पाटन मार्जिन काफी अधिक था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ ने चीन और ताइवान से समान उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है तथा उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन भी काफी अधिक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि लंबे समय से उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

(ii) संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताएं और वैश्विक मांग एवं आपूर्ति का परिदृश्य

173. स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद बाजार आउटलुक, मई 2015 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार संबद्ध देशों के पास उपलब्ध और अनुमानित क्षमताएं तथा उन देशों में निकाली गई बेशी क्षमताएं निम्नानुसार हैं:

000मी.टन	चीन	कोरिया गण.	ताइवान	यूएसए	ईयू	अफ्रीका	थाइलैंड
अनुमानित भारतीय मांग	394	394	394	394	394	394	394
संबद्ध देशों की क्षमता	26600	2200	1776	4301	8352.4	1000	300

क्षमता उपयोग	66%	81%	46%	61%	77%	48%	62%
बेशी क्षमता	34%	19%	54%	39%	23%	52%	38%
स्थानीय मांग	9584	897	485	2102	3337	135	267
मौजूदा निर्यात	10624	1099	1172	1870	2658	281	185
बेशी क्षमता	9084	427	961	1375	424	100	234
निर्यात हेतु उपलब्ध निवल मात्रा	19708	1527	2133	1491	991	100	501.3
भारतीय मांग का %	5003%	388%	542%	460%	306%	31%	127%

स्रोत: सीआरयू मई 2015

174. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के उत्पादकों के पास बेशी क्षमता है, इसकी पुष्टि इस जांच में उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से भी होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सीआर मांग में 3.5% गिरावट आने की संभावना है जबकि क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे मांग एवं आपूर्ति में अत्यधिक असमानता का परिदृश्य उत्पन्न हो गया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि कुछेक देशों से वस्तुओं के अत्यधिक पाटन के कारण विभिन्न देशों जैसे यूरोपीय संघ (मार्च 2015, चीन एवं ताइवान); वियतनाम (सित. 2014, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया एवं मलेशिया); और ब्राजील (अक्तू. 2013: चीन, कोरिया, ताइवान, वियतनाम और फिनलैंड) में उत्पाद पर हाल में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है जिससे मांग एवं आपूर्ति का परिदृश्य और भी प्रभावित हुआ है। ऐसे परिदृश्य में बढ़ता हुआ भारतीय बाजार मामूली लागत कीमतों पर अपनी बेशी क्षमताओं के उपयोग हेतु विदेशी उत्पादकों के लिए बहुत आकर्षक होगा। यदि आयात किसी पाटनरोधी शुल्क के बिना मौजूदा कीमतों पर जारी रहे तो ऐसे आयातों से मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग के निष्पादन के प्रभावित होने की संभावना होगी।

(iii) संबद्ध देशों के लिए पाटनरोधी जांच

175. यह नोट किया गया है कि यूरोपीय संघ ने दिनांक 24 मार्च 2015 के विनियमन कार्यान्वयन

आयोग (ईयू) 2015/501 के जरिए चीन एवं चीनी ताइपेई के विरुद्ध प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए हैं और चीन के लिए 24.3% से 25.2% और चीनी ताइपेई के लिए 10.9% से 12% तक पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इससे इन दो देशों के निर्यातों की पाटन प्रवृत्ति भी प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त, ब्राजील ने अक्टू. 2014 में चीन, कोरिया, ताइवान, वियतनाम और फिनलैंड से सीआर फ्लैट उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। वियतनाम ने भी सित. 2014 से इन उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। अतः शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में इन देशों से संबद्ध वस्तु भारत को भेजे जाने की काफी संभावना है।

(iv) भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण और मांग परिदृश्य

176. संबद्ध वस्तु के लिए भारतीय बाजार में उत्पाद की अच्छी मांग है जो सामान्य आर्थिक प्रगति के अनुरूप है। तथापि, पूर्व का कीमत परिदृश्य यह दर्शाता है कि यह कम कीमत वाला बाजार बना रहेगा और बेशी क्षमता वाले वैश्विक निर्यातकों के लिए मामूली कीमत पर निर्यात के लिए आकर्षक बना रहेगा। तथापि, यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो भारतीय बाजार और भी आकर्षक बन जाएगा क्योंकि निर्यातक शुल्क के पूर्ण लाभ की सीमा तक बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

(v) जांच पश्चात की अवधि में आयात की प्रवृत्ति

177. मौजूदा मामले में जांच अवधि जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 थी और विस्तारित पाटनरोधी शुल्क 20 अप्रैल 2015 तक के लिए वैध था। अतः जांच पश्चात की अवधि के पहले छह माह के दौरान शुल्क लागू थे। अतः जांच पश्चात के आयात आंकड़े भी शुल्क से प्रभावित हैं और मात्रा एवं कीमतों में कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं दर्शाते हैं। फिर भी, किसी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए आंकड़ों की जांच की गई है। प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए जांच अवधि के बाद के छह माह के आयात आंकड़ों की जांच की गई है। पूर्व खण्ड में दिए गए जांच पश्चात की अवधि के आयात आंकड़ों से समान प्रवृत्ति के जारी रहने का संकेत मिलता है। वस्तुतः जांच पश्चात की अवधि में आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(vi) जांच पश्चात की अवधि का कीमत प्रभाव परिदृश्य

178. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों के साथ जांच पश्चात की अवधि की आयात कीमतों की तुलना से भी यह प्रदर्शित होता है कि आयात कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती

हो रही है।

179. गैर-क्षतिकारक कीमतों के साथ जांच पश्चात की अवधि के दौरान आयात कीमतों की तुलना किए जाने पर भी यह संकेत मिलता है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाएं और कीमतें उसी स्तर पर बनी रहें तो उससे घरेलू उद्योग पर कम कीमत पर बिक्री के रूप में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।

जांच पश्चात की अवधि	इकाई	चीन	चीनी ताइपेई	ईयू	कोरिया	दक्षिण अफ्रीका	थाइलैंड	यूएसए
मात्रा (वार्षिकृत)	मी.टन	8235	432	2407	752	1102	1248	1808
भारित औसत गैर-क्षतिकारक कीमत	रु./मी.टन	****	****	****	****	****	****	****
पाटनरोधी शुल्क के बिना भारित औसत पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	103631	113843	131844	118897	118897	122729	125574
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन	****	****	****	****	****	****	****
कम कीमत पर बिक्री	%	****	****	****	****	****	****	****
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	35-45	65-75	15-25	20-30	35-45	35-45	45-55
पाटनरोधी शुल्क के साथ कम कीमत पर बिक्री	%	****	****	****	(****)	****	****	(****)
पाटनरोधी शुल्क के साथ कम कीमत पर बिक्री	रेंज	25-35	30-40	0-10	(10) - 0	0-10	40-50	(15) - (5)

(vii) घरेलू उद्योग का जांच पश्चात की अवधि का निष्पादन

180. पूर्व खण्ड में दिए गए विवरण के अनुसार यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में जांच पश्चात की अवधि में सुधार आया है, तथापि जांच पश्चात की अवधि में घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में गिरावट प्रदर्शित होती है। जांच पश्चात की अवधि के दौरान घाटों में वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाएं तो घरेलू उद्योग को क्षति

होना जारी रहेगा।

ढ. हितबद्ध पक्षों की प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

181. अपनी पश्चः प्रकटन टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षों ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अधिकांशतः अपने तर्क दोहराए हैं। प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों ने आगे तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद केवल 1250 एमएम चौड़ाई तक है। यदि पीयूसी की सीमा के बाहर कोई अन्य उत्पाद घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है तो यह क्षति संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण नहीं हो सकती। यदि प्राधिकारी गैर-पीयूसी पर भी विचार करना चाहते हैं तो इस पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। विश्लेषण के लिए केवल गैर-पीयूसी के आयात की मात्रा पर विचार करना स्वीकार्य नहीं है। प्राधिकारी को 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई की वस्तुओं के लिए कीमत, मांग, घरेलू बिक्री और अन्य आर्थिक प्राचलों पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार के आयात को क्षति पहुंचाए बिना यह नोट किया गया था कि आयात आंकड़े स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि आयात उत्पाद की सीमा के बाहर उत्पाद रेंज से शिफ्ट हो गया है जिस पर शुल्क लागू था और इसलिए पीयूसी की मांग और खपत, बाजार हिस्से और कीमतों के आंकड़े उस सीमा तक प्रभावित हुए हैं। इसलिए अधिक चौड़ाई के आयात में शिफ्ट होने के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
182. प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों ने आगे तर्क दिया है कि जिस समय उस देश से आयात की मात्रा अत्यधिक कम होती है, उस समय किसी संबद्ध देश के विरुद्ध पाटनरोधी जांच को समाप्त करने के लिए प्राधिकारी की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसने आगे तर्क दिया है कि यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी निर्णायक समीक्षाओं में यह सिद्धांत अपनाया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा में संभावना विश्लेषण पर बल दिया जाता है। यदि क्षति जांच के दौरान आयात कम है तो प्रतिक्रिया देने वाले हितबद्ध पक्षों द्वारा उल्लिखित सिद्धांत उस समय लागू किए जाते हैं जिस समय पाटन की पुनरावृत्ति की अभी होने वाली कोई संभावना नहीं है। जिस समय मामले के तथ्यों के आधार पर स्पष्ट संभावना सिद्ध हो जाती है तो क्षति अवधि के दौरान आयात की कम मात्रा संगत नहीं है।
183. घरेलू उद्योगों ने अपने अनुरोधों में प्राधिकारी को आगे अनुरोध किया है कि भागीदार निर्यातकों द्वारा निर्यात नहीं की गई विशेष सीरीज पर बाकी शुल्क की सिफारिश करे।

इसके अतिरिक्त उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों अथवा उत्पादक और निर्यातक के संगठन जिन्होंने मूल जांच में भाग नहीं लिया था और निर्णायक समीक्षा जांच भाग लेने में विफल रहे, बाकी शुल्क भी लगाया जाना चाहिए।

184. प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों ने अपने पश्चः प्रकटन अनुरोधों में भी तर्क दिया था कि प्राधिकारी को पीओआई अवधि के दौरान निर्यात नहीं किए गए ग्रेडों के लिए पीओआई के दौरान निर्यात किए गए ग्रेडों के लिए निर्धारित वही पाटन मार्जिन/पाटनरोधी शुल्क लागू करना चाहिए क्योंकि यह परिकल्पना की जानी चाहिए कि पाटन यदि कोई हो, उन ग्रेडों के लिए भी उसी स्तर का होना चाहिए जो कि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा पीओआई के दौरान निर्यात नहीं किए गए हैं। प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातकों के लिए पीओआई के दौरान निर्यात नहीं किए गए ग्रेडों की पाटनरोधी शुल्क की दंडस्वरूप दरें लागू नहीं करनी चाहिए क्योंकि दंडस्वरूप दरों का उद्देश्य गैर-सहयोगी पक्षों को दंड देना है। प्रतिक्रिया देने वालों ने जांच के दौरान प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग दिया है और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई है। इसलिए प्राधिकारी को पीओआई के दौरान प्रतिक्रिया देने वालों द्वारा निर्यात नहीं किए गए ग्रेडों के लिए पाटनरोधी शुल्क की दंडस्वरूप दरें लागू नहीं की जानी चाहिए।

185. प्रकटन विवरण के लिए अपनी टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों की उनकी प्रासंगिकता की सीमा तक जांच की गई है।

ण. पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना का समग्र आकलन

186. संबद्ध देशों/क्षेत्रों में संबद्ध वस्तु की क्षमताओं और उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और ऊपर रेखांकित किए गए के अनुसार संबद्ध वस्तु के लिए समग्र वैश्विक मांग आपूर्ति परिदृश्य के जांच से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों के पास उक्त वस्तु के उत्पादन के लिए अत्यधिक बेशी क्षमता मौजूद है। वैश्विक मांग आपूर्ति परिदृश्य कई वृहत आर्थिक कारकों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है और ऐसी रिपोर्टों में उपलब्ध अनुमानों के अनुसार इस स्थिति के जारी रहने की संभावना है। उत्पाद को कई देशों में व्यापार सुधारात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है और पूर्व खण्ड में दिए गए विवरण के अनुसार कुछ संबद्ध देशों को प्रमुख बाजारों में ऐसे व्यापार सुधारात्मक उपायों का

सामना करना पड़ रहा है। अतः यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के बड़े स्तर पर निर्यात किए जाने की काफी संभावना है। सामान्य कीमत प्रवृत्ति से यह संकेत मिलता है कि मांग में वैश्विक कमी और प्रमुख बाजारों में व्यापार सुधारात्मक उपायों से संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए अपनी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग कर के अपनी स्थूल लागत की वसूली के लिए मामूली लागत कीमत पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करना काफी आकर्षक होगा। अतः शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में इन देशों से भारत को संबद्ध वस्तु भेजे जाने की काफी संभावना है।

187. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि, घरेलू उद्योग को पहले से ही सतत पाटित आयातों और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर उत्पाद रेंजों के आयात की अत्यधिक मात्रा के कारण कम क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ रहा है। बढ़े हुए उत्पादन और बिक्री स्तरों पर भी घरेलू उद्योग को उसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है जो कि पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के कारण है। अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातों में और वृद्धि होने से घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग और उसकी लाभप्रदता और भी अधिक प्रभावित होंगे। अतः शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग जो पहले से ही पाटित आयातों के कारण प्रभावित हो रहा है, को और अधिक क्षति होने की संभावना है।

त. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

188. प्राधिकारी द्वारा शुल्क संबंधी नियम का कम अनुसरण करने को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तुओं को आयात के संबंध में मार्जिन का भी निर्धारण किया गया है। क्षति के मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 3 में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। ऐसी एक जैसी उचित तुलना करने के प्रयोजन से गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) का निर्धारण, ग्रेड स्तर पर किया गया है तथा उसे संबद्ध वस्तुओं के संबंधित ग्रेडों की श्रृंखलाओं के स्तर पर समेकित किया गया है। इस प्रकार श्रृंखलाओं के स्तर पर निर्धारित की गई गैर-क्षति-कीमतों की तुलना, संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद की संबंधित श्रृंखलाओं के पहुंच

मूल्य से की गई है ताकि प्रत्येक देश के लिए क्षति के मार्जिन का पता लगाया जा सके । तदनुसार घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) और विचाराधीन उत्पादों के लिए क्षति के मार्जिन का निर्धारण, प्रत्येक संबद्ध देश के लिए किया गया है ।

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डुप्लेक्स ग्रेड की बहुत ही नगण्य मात्रा जांच की अवधि के दौरान कुछ देशों से आयात की गई है और कीमत संबंधी सूचना विश्वसनीय नहीं है। इसलिए, वह ग्रेड क्षति मार्जिन गणनाओं के लिए विचार नहीं किया गया है। क्षति मार्जिन ग्रेड/सीरीज स्तर पर पहले निर्धारित किया गया है और उसके बाद प्रत्येक उत्पादक के लिए ग्रेड/सीरीज स्तरों पर क्षति मार्जिन पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए उत्पाद हेतु समेकित किए गए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी और विचाराधीन उत्पादों के लिए क्षति के मार्जिन नीचे दिए गए अनुसार प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों के साथ-साथ प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्धारित किए गए हैं।

विवरण/देश		इकाई	200 सीरीज	300 सीरीज	400 सीरीज	भारत औसत
उत्पादक	निर्यातक					
चीन	सभी उत्पादक/ निर्यातक					
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी	****	****	****	****
क्षति मार्जिन		%	****	****	****	****
आईएम रेंज		%	85-95	15-25	15-25	50-60
यूरोपियन यूनियन						
मैसर्स एसेरिनाॅक्स एसएयू, स्पेन	मैसर्स एसेरिनाॅक्स एसएयू, स्पेन					
क्षति मार्जिन		%		****	****	****
आईएम रेंज		%		20-30	30-40	25-35
अन्य सभी						
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी		****	****	****
क्षति मार्जिन		%		****	****	****
आईएम रेंज		%		35-45	65-75	50-60
कोरिया आरपी						

मैसर्स पोसको कोरिया				मैसर्स ह्यूंडै कारपोरेशन	दैव इंटरनेशनल	
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी		****	(****)	****
क्षति मार्जिन		%		****	(****)	****
आईएम रेंज		%		10-20	(5-15)	0-10
अन्य सभी						
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी		****	****	****
क्षति मार्जिन		%		****	****	****
आईएम रेंज		%		10-20	0-10	10-20
दक्षिण अफ्रीका						
मैसर्स कोलंबस स्टेनलेस	मैसर्स कोलंबस स्टेनलेस					
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी	(****)	****	****	****
क्षति मार्जिन		%	(****)	****	****	****
आईएम रेंज		%	(30-40)	10-20	10-20	10-20
अन्य सभी						
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी	(****)	****	****	****
क्षति मार्जिन		%	(****)	****	****	****
आईएम रेंज		%	(30-40)	30-40	65-75	30-40
ताइवान	सभी उत्पादक/निर्यातक					
मात्रा		एमटी	****	****		****
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी	****	****		****
क्षति मार्जिन		%	****	****		****
आईएम रेंज		%	10-20	15-25		10-20
थाईलैंड						
मैसर्स पोसको थाईनॉक्स	मैसर्स पोसको थाईनॉक्स					
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी		(****)		(****)
क्षति मार्जिन		%		(****)		(****)
आईएम रेंज		%		(0-10)		(0-10)
मैसर्स पोसको थाईनॉक्स	मैसर्स ह्यूंडै कारपोरेशन	एमटी		91		
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी		****		
क्षति मार्जिन		%		****		
आईएम रेंज		%		5-15		

अन्य सभी						
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी		****		****
क्षति मार्जिन		%		****		****
आईएम रेंज		%		0-10		0-10
यूएसए	सभी उत्पादक/ निर्यातक					
क्षति मार्जिन		यूएस\$/एमटी	****	****	****	****
क्षति मार्जिन		%	****	****	****	
आईएम रेंज		%	20-30	5-15	45-55	5-15

190. उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि सीरीज स्तरों पर संबद्ध देशों/राज्य क्षेत्रों से पाटित आयात के उतराई तक के मूल्यों के भारित औसत क्षति मार्जिन थाईलैंड, जहां उत्पाद के लिए चालू क्षति मार्जिन पूर्ण रूप से ऋणात्मक है, को छोड़कर समनुरूपी सीरीजों की संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षति कीमतों से काफी कम है।
191. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के चालू आयातों पर आधारित पूर्ण रूप से परिगणित उत्पाद के साथ-साथ ग्रेड/सीरीज देशों से पाटन के जारी रहने की संभावना स्पष्ट है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि थाईलैंड से सहयोग करने वाले निर्यातकों को छोड़कर सभी संबद्ध देशों के लिए पूर्ण रूप से उत्पाद के साथ-साथ ग्रेड/सीरीज स्तरों पर क्षति के मार्जिन पर्याप्त हैं।
192. पोसको, थाईनॉक्स, थाईलैंड के मामले में यह नोट किया गया है कि उसी ग्रेड के लिए असंबद्ध निर्यातक के जरिए निर्यात कीमतें सीधे निर्यात किए जाने की स्थिति में निर्यात कीमतों से काफी भिन्न है, जिससे विभिन्न चैनलों के जरिए निर्यात किए गए उसी ग्रेड के लिए पाटन और क्षति मार्जिन काफी भिन्न हुआ और जिसके सौदों के मूल्यों को अविश्वसनीय बना दिया।-इन दो चैनलों के जरिए निर्यात की मात्रा भी कम है। चूंकि उत्पादक ने वही ग्रेड पीओआई के दौरान भिन्न कीमतों पर बेचा है। इसलिए, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यदि शुल्क को निरस्त किया जाता है तो उत्पादक कम कीमत, जिस पर पीओआई के दौरान वस्तुएं बेची गई हैं, पर वस्तुएं नहीं बेचेंगे। इसलिए, थाईलैंड से इस उत्पादक के लिए प्राधिकारी ने उन कीमतों, जिन पर अपनी असंबद्ध ट्रेडिंग कंपनी के जरिए भारत को वस्तुएं बेची हैं, पर आधारित संभावित

क्षति मार्जिन निर्धारित किया है।

थ. निष्कर्ष:

193. उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदनों तथा इस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्कों के अधिरोपण के पश्चात् संबंध देशों/क्षेत्रों से संबंध वस्तु का पाटन जारी है हालांकि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। संबंध देश से पाटित आयातों के प्रभाव और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर की उत्पाद रैंजों का आयात किए जाने के कारण मौजूदा क्षति विश्लेषण अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग के निष्पादन में और गिरावट आने की काफी संभावना है।

द. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

194. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उपयुक्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनःस्थापित किया जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण से किसी भी तरीके से संबंध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए संबंध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ध. सिफारिश:

195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षों को इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की सूचना दी गई थी और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों तथा शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सकारात्मक सूचना और सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने और यह स्थापित करने के बाद कि पाटन और क्षति जारी है तथा शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उनके जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी संबंध देशों/क्षेत्रों से संबंध वस्तु के आयातों पर नीचे वर्णित रूप और पद्धति से पाटनरोधी शुल्क की

अवधि के विस्तार की सिफारिश करना आवश्यक एवं उपयुक्त समझते हैं।

196. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए गए कम शुल्क के नियमों को देखते हुए प्राधिकारी जांच की अवधि के लिए इस जांच निष्कर्ष में इस प्रकार से निर्धारित कम पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के समान पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के क्षति संबंधी प्रभाव को हटाया जा सके। तदनुसार, जैसा कि नीचे शुल्क सारणी के कॉलम 9 में उल्लेख किया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की और अधिक अवधि के लिए संबद्ध देशों/ भूभागों के मूल के अथवा वस्तुओं के लदान मूल्य के प्रतिशत के रूप में पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। इस प्रयोजन के लिए आयातों का लदान मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्कों और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्कों द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा

शुल्क सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूलता का देश/ भूभाग	निर्यात का देश/भूभाग	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7219	स्टेनलेस स्टील के कोल्ड - रोल्ड फ्लैट 300 उत्पाद*	नीचे पाद टिप्पणी में के अनुसार छोड़े गए उत्पादों के अलावा सभी ग्रेड सभी सीरिज	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	कोई भी	57.39 %
2	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	चीन जन. गण.	कोई भी	कोई भी	57.39 %
3	-वही -	- वही-	- वही-	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	मैसर्ज पासको कोरिया	1. ह्यूंडई कारपोरेशन 2. देवू इंटरनेशनल	5.39 %
4	- वही-	- वही-	- वही-	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	उपरोक्त संयोजन के अलावा कोई अन्य		13.44 %
5	- वही-	- वही-	- वही-	कोरिया जन. गण.	कोई भी	कोई भी	कोई भी	13.44 %

6	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य कोई भी	कोरिया जन. गण.	कोई भी	कोई भी	13.44 %
7	- वही-	- वही-	- वही-	चीनी ताइपेई	कोई भी	कोई भी	कोई भी	15.93 %
8	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	चीनी ताइपेई	कोई भी	कोई भी	15.93 %
9	- वही-	- वही-	- वही-	दक्षिणी अफ्रीका	दक्षिणी अफ्रीका	कोलंबस स्टेनलेस	कोलंबस स्टेनलेस	12.34 %
10	- वही-	- वही-	- वही-	दक्षिणी अफ्रीका	दक्षिणी अफ्रीका	उपरोक्त संयोजन के अलावा कोई अन्य		36.91 %
11	- वही-	- वही-	- वही-	दक्षिणी अफ्रीका	कोई भी	कोई भी	कोई भी	36.91 %
12	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	दक्षिणी अफ्रीका	कोई भी	कोई भी	36.91 %
13	- वही-	- वही-	- वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	पोस्को थाइनेक्स	1. पोस्को थाइनेक्स 2. ह्यूंडई कारपोरेशन	4.58 %
14	- वही-	- वही-	- वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	उपरोक्त संयोजन के अलावा कोई अन्य		5.39 %
15	- वही-	- वही-	- वही-	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	कोई भी	5.39 %
16	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	थाइलैंड	कोई भी	कोई भी	5.39 %
17	- वही-	- वही-	- वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	कोई भी	कोई भी	9.47 %
18	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	कोई भी	9.47 %
19	- वही-	- वही-	- वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	एसरीनॉक्स यूरोपा एसएयू, स्पेन	एसरीनॉक्स यूरोपा एसएयू, स्पेन	29.41 %
20	- वही-	- वही-	- वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	उपरोक्त संयोजन के अलावा कोई अन्य		52.56 %
21	- वही-	- वही-	- वही-	यूरोपीय संघ	कोई भी	कोई भी	कोई भी	52.56 %
22	- वही-	- वही-	- वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य	यूरोपीय संघ	कोई भी	कोई भी	52.56 %

पाद टिप्पणी :

** निम्नलिखित को छोड़कर “सभी सीरिज के 600 मि.मी. से 1250 मि. मी. तक की चौड़ाई वाले स्टेनलेस स्टील के कोल्ड- रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो आगे 4 मि.मी. तक की मोटाई वाले कोल्ड रोल्ड (कम किए गए कोल्ड) से आगे काम के नहीं (मिल

एज्ड के लिए +30 मि. मी. का चौड़ाई टोलरेंस और ट्रिम एज्ड के लिए +4 मि. मी. का चौड़ाई टोलरेंस) :

- i. 1250 मि मी से अधिक चौड़ाई वाली संबद्ध वस्तुएं (प्लस टोलरेंस)
- ii. ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ई एन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 तथा ई एन 1.4509
- iii. चीनी ताइपेई (ताइवान) के मैसर्ज यी यूनाइटेड स्टील कोर्प (युस्को) द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई क्रॉनियम- निकल मैंगनीज- कॉपर ऑस्टेनितिक स्टेनलेस स्टील और वाई यू 1 तथा वाई यू 4 ग्रेड की लो निकल की वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट नं. 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद ।

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 में और साथ ही श्रेणी सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के तहत "बेस मेटल और बेस मेटल की वस्तुएं" के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं । इसमें उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यदि किसी अन्य सीमा शुल्क शीर्ष के तहत उत्पाद का आयात हुआ है तो शुल्कके लागू होने की किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है ।

197. केन्द्र सरकार द्वारा इस सिफारिश पर आधारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

198. प्राधिकारी अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों और इस संबंध में समय समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के तहत की गई सिफारिशों के अनुसार निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, संशोधन करने अथवा समाप्त करने की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं । प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी समीक्षा का कोई अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट समय सीमा के तहत हितबद्ध पक्षकार द्वारा दाखिल नहीं किया गया हो ।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES**New Delhi, the 12th October, 2015**NOTIFICATION****FINAL FINDING**

Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from the Peoples Republic of China, Republic of Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America.

F. No. 15/04/2014-DGAD:— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules);

A. Background

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) the Designated Authority, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, appointed under the Rules supra, (hereinafter referred to as “the Authority”), vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 25th November, 2008, initiated an anti-dumping investigation concerning import of Cold-rolled Flat products of stainless steel of all series of ASTM A240/A480M, not further worked than Cold rolled (cold reduced), width of 600 mm upto 1250mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edge and +4mm for Trimmed Edge), with a thickness of up to 4mm, (hereinafter also referred to as the subject goods) from the Peoples Republic of China, Republic of Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America (hereinafter also referred to as the subject countries/territories).
2. Preliminary Findings were issued by the Authority, vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 27th March, 2009 and provisional duty was imposed by the Central Government, vide Notifications No. 38/2009-Customs, dated 22nd April, 2009. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/06/2008-DGAD, dated 24th November, 2009. On the basis of the recommendations made by the Authority in the said final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, vide Notifications No. 14/2010-Customs, dated 20th February, 2010 effective from the date of the imposition of the provisional anti-dumping duty i.e., 22nd April, 2009 on the imports of the of the above goods, originating in or exported from the subject countries/territories.
3. Before expiry of the said duty M/s Jindal Stainless Limited, (hereinafter referred to as ‘petitioner’ or ‘applicant’), the major domestic manufacturer of the subject goods in India, filed a duly substantiated application in January 2014 before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from subject countries/territories and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, and requested for a review of the same for continuation and enhancement of the anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries/territories.
4. On the basis of duly substantiated application filed by the domestic industry, Authority, vide Notification No. 15/04/2014-DGAD, dated 17th April 2014, initiated a sunset review of the anti dumping duty in force on import of subject goods, originating in or exported from the above named countries/territories to examine whether the expiry of the duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. Consequent upon initiation of the sunset review, vide Notification No. 20/2014-Customs (ADD) dated 12th May, 2014, the validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries/territories, was extended by the Central Government up to and inclusive of 21st day of April 2015.
5. On the request of the Designated Authority, the Central Government extended the time for completion of the Investigation by six months, i.e., up to 15th October, 2015, in terms of Rule 17 of the AD Rules.

6. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries/territories.

B. Procedure

7. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

- i. The embassies/missions of the subject countries/territories in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
- ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassies/missions of the subject countries/territories in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within (40) forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):
 1. M/s Shanghai Krupp Stainless, China
 1. M/s Zhangjiagang POSCO Stainless Steel Co., Ltd., China
 2. M/s. ALZ NV, Belgium
 3. M/s Ugine (Division of Usinar), Immeuble Pacific, France
 4. M/s Acerinox Europa SAU, Spain
 5. M/s Acerinox SA, Italy
 6. M/s ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germany
 7. M/s ThyssenKrupp ACCAi Specialtereni SPA, Italy
 8. M/s Outokumpu Stainless, U.K.
 9. M/s Outokumpu Stainless, Finland
 10. M/s Outokumpu Stainless AB, Sweden.
 11. M/s A.K. Steel Corporation, USA
 12. M/s Allegheny Ludlum, USA
 13. M/s North American Stainless, USA
 14. M/s J & L Specialty Steel, Inc., USA
 15. M/s Yieh United Steel Corporation (YUSCO), Chinese Taipei
 16. M/s Columbus Stainless (Pty) Ltd, South Africa
 17. M/s POSCO, Korea
 18. POSCO, Thainox, Thailand
- iv. China being a Non-Market Economy country, a Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation of the review the normal value in China was estimated based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the market economy claims of the responding exporters in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of Annexure I referred above to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in that country. However, no response has been received from any producer/exporter from China PR in this regard.
- v. In response to the initiation notification the following exporters / producers from subject countries/territories have responded:

- a. M/s Acerinox Europa S.A.U, Spain
 - b. M/s Columbus Stainless (PTY) Ltd., South Africa
 - c. M/s POSCO, Korea
 - d. M/s Daewoo International, Korea
 - e. M/s Hyundai Corporation, Korea
 - f. M/s Posco Thainox, Thailand
- vi. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers/associations of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority) and advised them to make their views known in writing within forty (40) days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):
- a. M/s Honest Enterprise Ltd., Vadodara
 - b. M/s Kuber Steel Impex, Mumbai
 - c. M.M. Enterprises, Raigadh
 - d. Advance Metal Corporation, Mumbai
 - e. Bhandari Foils Pvt. Ltd., Dewas
 - f. Angel Pipes & Tubes Pvt. Ltd., Mumbai
 - g. IDMC Ltd., Gujarat
 - h. M.K. Steel Centre, Raigad
 - i. Riddhi Siddhi Impex, Mumbai
 - j. Salem Stainless Steel Suppliers, Chennai
 - k. Western Metal (India), Mumbai
 - l. Star Stainless Steel, Mumbai
 - m. Advance Metal Corporation
 - n. Arihant Steel Enterprises, Mumbai
 - o. Jindutt Steel, Mumbai
 - p. Madras Steel Agencies, Chennai
 - q. Nobel Impex, Mumbai
 - r. All India Stainless Steel Industries Association
 - s. Stainless Steel Exporters Welfare Association
 - t. Process Plant and Machinery Association of India
- vii. Importer's Questionnaire Response has been filed only by two importers namely:
- a. M/s Posco India Chennai Steel Processing Centre Pvt. Ltd., (ICPC), Chennai
 - b. Posco India Delhi Steel Processing Centre Pvt. Ltd., (IDPC), Delhi
- viii. However, submissions have been filed with regard to injury etc., by the following:
- i. M/s All India Stainless Importer Association;
 - ii. M/s MP Industries;
 - iii. M/s Vinod Cookware;
 - iv. M/s Meena Metal Impex Pvt. Ltd.
- ix. The following other known domestic producers were also asked to provide information relevant to the investigation. However, none of these known producers have filed any information relevant to the investigation:
- a. M/s Salem Stainless Steel, Chennai
 - b. M/s Shah Alloys Ltd., Gujarat
 - c. M/s BRG:-Corporate Office, West Bengal
- x. Transaction-wise imports data procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) has been relied upon for the analysis in present SSR investigation. Further, the Authority has also examined the Post-POI (January 2014 - June 2014) import data to analyze the trends for the purpose of likelihood assessment.

- xi. Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis have been examined with regard to reasonableness of the claim of confidentiality. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. Non-confidential versions of the evidence presented by interested parties were made available in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). Pursuant to the orders of the Hon'ble Delhi High Court in SanDisk matter, non-confidential version of the import data procured from DGCI&S has been kept in the public file open for inspection by the interested parties without prejudice to the appeal filed by the Authority before the Hon'ble Supreme Court of India in that matter.
- xiv. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to work out the cost of production and determined the non-injurious price of the subject goods in India as per its consistent practices so as to ascertain whether anti-dumping duty, lower than the dumping margin, would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28.10.2014. The interested parties were requested to file written submissions of their views expressed orally.
- xvi. In view of the change in the Designated Authority a fresh public hearing was held on 18th August, 2015 to provide an opportunity to the interested parties to present their views on various aspects of the investigation.
- xvii. In terms of Rule 16 of the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case through a disclosure statement issued on 6th October, 2015 and the comments to the said disclosure received from the interested parties have been considered to the extent they are relevant. The submissions made by the interested parties during the course of the investigations and written submissions after the public hearings have been addressed in this disclosure to the extent they are relevant and backed by evidence.
- xviii. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer as well as the responding exporters were carried out to the extent deemed necessary and feasible.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and has used "best information available" for the determinations to the extent required.
- xx. In this finding **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. For the purpose of this investigation the period of investigation was taken as January 2013 to 31st December, 2013 (12 months) and for the purpose of injury investigation data was taken for the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI has been considered.
- xxii. For the purpose of conversion of the transaction values in local currencies in the countries of exports the Authority has taken the exchange rates as reported by the cooperating/responding producers and exporters in their questionnaire response. For all other conversions, wherever the actual rate of conversion was not available, average exchange rate of US\$ to Rupee for the POI has been taken as Rs.58.97 = 1 US\$.

C. Scope of Product under consideration and like article

- 8. The product under consideration in the original investigation was Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel. The Designated Authority in its final recommendations restricted the scope of the product on which duty was recommended to Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel with widths upto and inclusive of 1250mm only with certain exclusions. The Central Government imposed the duties accordingly by defining the product in the Duty Table as follows:

“Cold Rolled flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250 mm of all series further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4 mm.

The subject goods will have the following exclusions from the scope of the product:

- i. Grade AISI 420 High carbon (0.28%-0.40%), Grade 420, Grade 430 BA supplied by M/s Thyssenkrupp Stainless International, Germany, Grade AISI 441 and Grade AISI 443;*
- ii. Duplex Stainless Steel grades 2205 (S31803), 2304 (S32304), EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grades EN 1.4509 and 1.4512;*
- iii. Product supplied under Indian Patent no. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing chromium Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).”*

9. Subsequently, the Domestic Industry filed a mid-term review, based on the application filed by the Domestic Industry and after following the due process of law, the Designated Authority recommended amendments to the original Customs Notification No. No. 14/2010-Customs dated 20th February, 2010 vide its Final Findings (Mid-term Review) No. 15/16/2009-DGAD dated 8.6.2011. Accepting the recommendations of the Designated Authority, the Central Government issued an amendment notification No. 86/2011-Customs dated 6.9.2011, inserting the following in the said notification, in para 1, after the Duty Table:-

“(a): Width tolerance of (+) 30mm shall apply to Mill edged, Cold-rolled flat products of stainless steel of specified width of 1000mm or more but not exceeding 1250 mm.

(b): Width tolerance of (+) 4mm shall apply to Trim edged Cold rolled flat products of stainless steel of specified width exceeding 1000mm but not exceeding 1250mm.”

10. The Designated Authority carried out a mid-term review in terms of the directions of the Hon’ble Punjab & Haryana High Court as a consequence of which certain further amendments were made in the products earlier excluded from the purview of the anti-dumping duties vide Corrigendum dated 5.12.2011. The Central Government vide corrigendum notification dated 7.2.2012 accepted the revised Final Findings of the Authority. After the said review the followings were excluded from the purview of the product under consideration:

- i. The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).*
- ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509*
- iii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh ;United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).*

11. In view of the aforesaid, the product under consideration for the purpose of this sunset review was defined as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”, excluding the following:

- i. The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).*
- ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509*
- iii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).”*

12. As per the petition the subject goods are classified under Base Metals and Articles of Base Metals” in Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 and imported under tariff codes 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

13. The petitioner, in its submissions, has requested to remove the restriction placed on the final PUC indicated in the duty table for collection of duties as the sole ground for exclusion of the widths above 1250mm (plus tolerances) was the conclusion of the Designated Authority that the Domestic Industry had not actually supplied the exact sizes from their existing facility during the period of investigation in the original investigation. Since the domestic industry has now started producing and supplying the wider widths, there is no legal or logical reason to not to remove the restriction placed on the product under consideration.

C.1 Submissions made by the Producers/Exporters/Importers and Associations

14. The interested parties, other than the domestic industry, have argued that Petitioner domestic industry's request to include those grades which were excluded in the original investigation should be rejected. It has been argued that in the initiation notice dated 17th April 2014, the Designated Authority has defined the product scope as defined in the original investigation as amended during the mid-term review. Therefore, the products/goods, which are not covered or explicitly excluded from the product scope earlier, are outside the purview of 'the' anti-dumping duty. Therefore, in view of proviso to Section 9A(5) of the Act, there cannot be any review (changed/sunset review) to examine the need to extend 'the' anti-dumping duty on any other products/goods outside the products scope in original investigation. It has been argued that it is an undisputed legal position that continuation or recurrence is possible of a thing/condition, if that was in existence in past. The products/goods, which were not found dumped and thus caused injury, cannot be examined for continuation and/or recurrence of dumping/injury.
15. It has also been submitted that Designated Authority being a quasi-judicial authority, cannot deviate from its earlier decisions and is bound to follow its earlier decisions for consistency and predictability, which controls arbitrariness. The Designated Authority had consistently, as a matter of practice, held that product scope cannot be enlarged in reviews. In view thereof it is requested that the Authority should not increased the scope of the product under consideration in the sunset review investigation.
16. Some of the interested parties have further submitted that the certain grades of subject goods, which are not manufactured by the domestic industry, need to be excluded from the purview of anti-dumping duty.

C.2 Submissions of the Domestic Industry

17. The domestic industry, in its submissions, has argued that they have not demanded for any fresh inclusion or expansion of scope of the Product under Consideration. They have only requested to remove the restriction placed on the final PUC indicated in the duty table for collection of duties. It has been further submitted that the Authority may recall that the sole ground for exclusion of the widths above 1250mm (plus tolerances) was the conclusion of the Designated Authority that the Domestic Industry had not actually supplied the exact sizes from their existing facility during the period of investigation in the original investigation. Since the domestic industry has now started producing and supplying the wider widths, there is no legal or logical reason to not to remove the restriction placed on the product under consideration.
18. The domestic industry has further submitted that they are producing and supplying all the grades with all the finishes. Moreover, certain grades which were not manufactured by the Domestic Industry during the original POI are being manufactured and supplied by the Domestic Industry.
19. Domestic industry further submitted that they are unable to appreciate the fact that the responding exporters are making a claim that PUC cannot be modified in sunset review on the one hand, while they themselves want to modify the PUC by seeking exclusions. The domestic industry submits that no fresh exclusions can be made as a part of this review. However, the Authority is certainly within its rights to extend the duties to those exclusions which were always an integral part of the PUC but were excluded for reasons of non-supply during the original POI.
20. According to the Domestic Industry, inclusion of the excluded categories would not amount to alteration of the scope of the PUC. The domestic industry has argued that the Designated Authority had merely restricted the imposition of anti-dumping duties keeping in mind the interests of the particular users. The Domestic Industry further points out that the restrictions made by the Designated Authority in the original findings can be removed particularly if the circumstances leading to such restriction/exclusion have now changed. In support of this argument the domestic industry submits that the initiation notification for this review specifically mentioned that the scope of the review will cover all aspects of the Notification No. 14/2010-Customs dated 20.2.2014, Custom Notification No. 86/2011 dated 6.9.2011 and dated 7.2.2012.

C.3 Examination by the Authority

21. Petitioner has contended that the only reason for excluding certain product types in original investigation was due to the fact that they had not supplied those grades and now that the Petitioner has started to supply such excluded grades or product types as well exclusion of such grades is not warranted.
22. The Authority notes that initiation notification in the original investigation defined the product under consideration as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of the width of 600 mm or more of all series further worked than Cold rolled (cold reduced) (hereinafter also referred to as subject goods). The product under consideration comprises of stainless steel coil, sheets and plates of above description. The subject goods are used for manufacturer of white goods, processed equipment, dairy equipment, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, etc. The subject goods are classified under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Sub-heading 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90. ...”

23. After a very detailed examination of various issues raised during the course of the investigation the Authority adopted certain broad principles for the purpose of exclusion of products of certain grades/specifications from the scope of the PUC. One such principle was whether the specification/ grade/production process/production technology pleaded by the interested parties resulted in a different product in terms of physical characteristics and chemical composition whereby the distinctiveness of the product can be established with clarity and precision. The second principle was whether the domestic industry claimed through their product broacher as manufacturer of these grades and was manufacturing/supplying such distinctive items at all during the POI or prior to the POI. Thirdly, whether any technical evidence was available to establish that the product grades supplied by the domestic industry during the POI were equivalent to the grades proposed/considered for exclusion. After a very detailed deliberation the Authority re-defined the product under consideration in the final findings of the original investigation as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of the width of 600 mm upto 1250mm of all series further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (hereinafter also referred to as subject goods).”

The subject goods (PUC) will have the following exclusions from the scope of the product on grounds as explained above:

a) Grade AISI 420 High carbon (0.28%-0.40%), Grade 420, Grade 430 BA supplied by M/s Thyssenkrupp Stainless International, Germany, Grade AISI 441 and Grade AISI 443.

b) Duplex Stainless Steel grades 2205 (S31803), 2304(S32304), EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grades EN 1.4509 and 1.4512.

c) Product supplied under Indian Patent no. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

24. Subsequently, the product scope was further modified in the midterm reviews carried out in June 2011 and December 2011 on the behest of the domestic industry and the orders of the Hon'ble Punjab and Haryana High Court and took into account the edge tolerance and other inclusions/exclusions and the final product scope as it exists today and on which the duty was in force and for which the sunset review has been initiated is defined as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”, with the exclusions excluding the following:

- i. The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).*
- ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509*
- iii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades*

YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

The product under consideration is classified under the category “Base Metals and Articles of Base Metals” in Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. It is used for manufacture of White Goods, Process Equipment, Dairy Equipment, Automotive Components, Rail Cars, Metro Coaches, Architecture, Building, kitchen products & Construction etc.”

25. The Authority notes the arguments of the domestic industry regarding inclusion of certain products within the scope of the product under consideration on the grounds that domestic industry has now started manufacturing the same and the criterion of actual supply and production set in the original findings is now fulfilled. The domestic industry has, in effect argued that the exclusion of certain grades/types etc. from the PUC at the time of the Final Findings did not really alter the scope of the PUC or the investigation. It has been further argued that the quintessential principle to define the scope of the PUC is whether the specific product is a “like article” to the product being imported or not. The underlying rationale of excluding certain product grades/types in the original investigation was that these products may not cause injury despite their being “like articles” on the premise that such products were not produced by the Domestic Industry. Now that the domestic industry produces and supplies these product types/grades/sizes continued exclusion of those product types/grades/sizes would adversely affect the domestic industry.
26. While there is some merit in the arguments of the domestic industry in a scenario where the product definition remains wide but certain restriction or exclusion has been placed only for the application and collection of duty. A careful examination of the case reveals that that is not the case here. The scope of the product under consideration itself has been restricted after detailed deliberation before proceeding for various determinations and the dumping and injury investigations are with respect to those included product types/grades/sizes only. Therefore, it is not a case where the scope of the PUC continues to be broad but application of the duty is restricted as has been argued.
27. It is further observed that in this case, the review has been initiated for the scope of the product as defined in the final finding and as modified by subsequent reviews. The Domestic Industry did not file any application for the review of the scope of the product under consideration as it did in 2011. The information supplied by the Domestic Industry did not include information of excluded products. Even the cooperating interested parties were not asked to include the information relating to the excluded products. In view of this, the Authority cannot accept the arguments of the domestic industry for inclusion of the excluded grades within the scope of the product under consideration.
28. As regards the issue of exclusion of certain other grades as argued by the other interested parties, the Authority notes that as per the information submitted by the domestic industry they have manufactured and supplied those grades. Accordingly, claim of the interested parties regarding exclusion of certain grades has no merit and therefore not accepted by the Authority.
29. No other argument has been made by any interested party on the product under consideration and like article issue. The Authority therefore, confirms that the scope of the product under consideration in the present review remains the same as that of the original investigation (as amended) and as defined in para 24 above for the purpose of this investigation.
30. The Authority notes that the subject goods being exported from the subject countries are alike in all respect to the goods being manufactured by the domestic industry. Therefore, the domestic goods are being held as like articles to the subject goods being imported within the meaning of the Rules.

D. Domestic Industry and Standing

31. The current application for the sunset review has been filed by M/s Jindal Stainless Limited who commanded 83% share in Indian production of the subject goods during the Period of investigation. As per the information available with the Authority there are three other known producers of the product under consideration in the country i.e., M/s BRG, Salem Steel Plant of Steel Authority of India Ltd. and M/s Shah Alloys. There is no opposition to the domestic industry’s application from any other producer in the country in the present investigation. Therefore, the petitioners command the standing to file the application and also constitute the domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules for the purpose of injury examination. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to scope and standing of the domestic industry.

E. Interested parties to this investigation

32. On the basis of questionnaire responses and other submissions filed by the responding producers/exporters and importers listed in sub para v, vii and viii in para-7 above, alongwith the Govt.s of the Countries named in this investigation and the domestic industry in India have been treated as interested parties to this investigation.

F. Issues regarding Confidentiality claims

33. The opposing interested parties have made the following submissions with regards to the confidentiality claims of the domestic industry:
- a. That the Petitioner has claimed excess confidentiality and also refrained from providing any meaningful summary of information provided by it on confidential basis. In addition, Petitioner has failed to provide a statement of reasons why information provided on confidential basis is not susceptible to summarization. This has restrained the Respondent from making complete analysis of injury claims in the petition.
 - b. The Petitioner has claimed confidentiality on the costing information at Section VI of the Petition. Even though the claim of the Petitioner that the disclosure of information may give a significant advantage to the competitors may be correct and not be disputed, yet in such cases, the Petitioner is required to furnish non-confidential summary of such costing information. The petitioner is not at liberty to respond to each question with respect to costing with same brush. Wherever it is possible to provide an indexed version of submission, the petitioner is bound to provide the same.
 - c. Petitioner also failed to provide Production Process, Purchase Policy, Sales Policy, Inventory and Quality Control Procedure etc.
34. The domestic industry has also made the following submissions with respect to the confidentiality claims and arguments of the interested parties:
- a. That the domestic industry has claimed confidentiality on its business sensitive information with adequate reasons in accordance with the legal provisions and the guidelines prescribed by the Authority. The reasons and grounds for claiming confidentiality have been given in the non-confidential version of the application. Hence, the claim of certain interested parties alleging excessive confidentiality is without any substance.
 - b. That the exporters by putting [] or ***** at various places in their response have kept the vital information confidential without providing any reasons. The exporters have also not given any summary of the information on which confidentiality has been claimed due to which the Domestic Industry is not in a position to offer its comments and defend its interests.
 - c. That Product specifications and product coding system used by the exporters are kept confidential without providing any reasons.
 - d. That the volume related figures in all the Appendices have been kept as confidential by the responding exporters whereas the domestic industry has disclosed all volume related information in the non-confidential version.
 - e. That allocation of costs among different cost centers has been kept confidential by the exporters. Further, whether the inputs consumed for production are purchased or captively produced by the company itself has also not been disclosed in the non-confidential version.
 - f. That the exporters have not provided their complete sales and distribution channel. In this context, domestic industry expressed its apprehension that this information was specifically withheld to hide the complete supply chain. It is submitted by the Domestic Industry that had the complete supply chain been placed in the non-confidential version, they would have been able to make effective submissions and provide additional information to the Authority which could have led to the rejection of their entire response.

F.1 Examination of the issue

35. Various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

36. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

37. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. As regards the contention of the opposing interested parties with regard to non-disclosure of the costing information, the Authority notes that costing and price related information is confidential in nature and generally not amenable to summarization. Therefore, the claim of the interested parties regarding excessive confidentiality by the Domestic Industry is not valid and hence rejected. On the other hand, the Authority observes that the Domestic Industry has vehemently contended that exporters has not revealed certain basic information relating to their volume related information and that most of the appendices in the questionnaire response have not been indexed which could provide a meaningful understanding to the concerned parties. The Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, of the domestic industry and opposing interested parties and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. Accordingly, all the arguments of the parties regarding confidentiality claims and non-confidential disclosure issues have been disposed off.

G. Other issues raised by the interested parties**G.1 Submissions of Exporters/Importers and other interested parties**

38. The exporters/importers and other interested parties, in their various submissions, have argued/submitted as follows:

- (i) That the present sunset review cannot be conducted due to lack of jurisdiction and must be terminated immediately. Since the duty lapsed on 21st April, 2014 and the extension was only formalized vide Notification dated 12th May, 2014, the continuation of present sunset review is rendered *otiose* under law;
- (ii) That the sunset review is required to be terminated because review proceedings cannot be carried on beyond one year period. Section 9A (5) read with Rule 23(2) empowers the Central Government to extend the levy of the anti-dumping duty for a period of one year only and the sunset review is to be concluded before the expiry of that period.
- (iii) That the initiation of sunset review is not on *suo motu* basis but based on a request made by the Petitioner to DGAD. The information has been filed by the Petitioner but such insufficient and inaccurate information cannot be said to be 'duly substantiated' information in terms of Rule 23(1B) of AD Rules;

- (iv) That in the Petition provided by the Petitioner, there is no explanation as to how Petitioner refined the import statistics from the raw import statistics procured by it. Petition also fails to disclose how Petitioner segregated subject product from non-subject product and what all product types has been included in the import statistics relied upon. There is also no mention about any other factors considered by the Petitioner while sorting the import data. Unless such information is made available, correctness of the information provided with respect to allegation of injury cannot be analyzed properly;
- (v) That the domestic industry has not provided any evidence for the deductions made under the categories of ocean freight, marine insurance, port handling, inland freight, and sales commission, or bank charges in the petition to arrive at the net export prices;
- (vi) That Jindal is practically the sole operator in the Indian market with more than 80% market share and enjoys unlimited supply and pricing power. There is no reason why Jindal should be enriched at the cost of thousands of user industries and at the cost of loss of Custom revenue.
- (vii) That the imports from all the subject countries are below *de minimus* and therefore, there is no occasion for imposing anti-dumping duty.
- (viii) That the anti-dumping duty should not be extended as this will create virtual monopoly for the domestic industry
- (ix) That the Authority should determine the dumping and injury margin for each grades of subject goods bearing in mind the vast differences in technical characteristics as well as end use of various grades of subject goods.
- (x) That the domestic industry has received adequate protection from DGAD since the imposition of provisional duty in the original investigation. Hence, antidumping duty should not be extended any further.

G.2 Submissions made by the Domestic Industry

39. The domestic industry, in its various submissions, has *inter alia* argued/submitted that:

- (i) That the import data of the subject goods have been sorted out based on the description given in each transaction in the transaction-wise import data. Basis of compilation of the import data for PUC has been explicitly mentioned in the petition itself. Further, the source, period and tariff headings of the raw data have been indicated in the application itself. There is no legal requirement to provide the raw data so long as the entries pertaining to the PUC as well as the headings from which the same have been taken out are disclosed in the non-confidential version of the submissions. Further, the domestic industry has submitted that if the plea of the interested parties is accepted, then it would actually mean that the Domestic Industry would be required to file details even of those sub-headings which have not been used for compiling the import data;
- (ii) That the domestic industry has submitted all the evidence which is reasonably available to it. The domestic industry has claimed the adjustments to the export price as per its market intelligence, which is considered to be sufficient evidence for initiation of an investigation as per consistent practice of the Designated Authority.
- (iii) That the costing data has been provided on per ton to facilitate proper comparison of costs and prices of the different grades/types of the product under consideration.
- (iv) That the claim of the interested parties that sunset review is required to be terminated because review proceedings cannot be carried on beyond one year period, is without any legal or logical merit. In this context, reference has been drawn to the provisions of Section 9A (5) wherein the chapeau itself prescribes that the duties shall remain in effect for a period of five years from the date of its imposition. In terms of the first proviso, this period can be extended by another five years period subject to the satisfaction of the conditions mentioned therein. The second proviso allows collection of duties for another one-year period pending conclusion of the investigations. Accordingly, it is important to note that there is no specific bar, direct or indirect, on the investigations continuing beyond the six-year period though there may be a bar under the second proviso that duty may continue to remain in force not exceeding one year. Clearly, the term “not exceeding one year” could at best be read in the context of duty and not in the context of review investigation.
- (v) Further, domestic industry has invited the attention of the Authority to Rule 17 of the Anti-dumping Rules, which allows a time period of upto 18 months to complete the investigations. Furthermore, Rule 23(3) clearly states that the provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be *mutatis mutandis* applicable in the case of

review investigation. Accordingly, provisions of Rule 17 are applicable to a sunset review case also. First proviso to Rule 17(1) categorically states that the Central Government may extend further the period of one year by six months for the completion of the investigation.

- (vi) Attention of the Authority was invited to recent decision of the Hon'ble Delhi High Court [NBR case of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. V/s UOI] wherein the Authority was permitted to continue the investigations despite the fact that the anti-dumping duties beyond the period of five years was set aside. It is further submitted that the only harmonious interpretation of the provisions of Section 9A (5), Rules 23 and 17, would be to read the provision of collection of duty disjunct from the period permissible for the completion of the investigation proceedings. Any other interpretation would invariably violate the vested rights of the Domestic Industry provided in Section 9A (5) itself. In any case, Rule 23 cannot be read in a manner that it takes away rights vested by Legislature. It is settled principle of law that a Rule cannot be interpreted in a manner that it frustrates the object and purpose of the main Act. Therefore, it is amply clear that even in the sunset review case, proceedings can be carried on beyond one-year period and the embargo, at best, can be applied only to the collection of duties beyond a period of six years. Thus, there is no legal infirmity or lacuna in the proceedings before the Authority.
- (vii) That the Authority has taken a consistent view that the purpose of anti-dumping duty is to create a level playing field and to provide relief to domestic industry due to injurious effect of dumped imports from the subject countries or the threat of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury once the duties are withdrawn.
- (viii) That the apprehension of a monopoly being created is baseless as the domestic industry is not the only player in the Indian domestic market. Besides other domestic produces, domestic industry has to compete with the imported subject goods which are freely available in the market from subject countries as well as from other countries also. Therefore, the submissions of the interested parties are legally and factually untenable.
- (ix) The *de minimis* criterion of imports does not apply in the sunset review investigations. The Domestic Industry submits that the reason for declining quantum of imports of subject goods from subject countries is because importers are bringing the higher widths i.e., widths above 1250MM only to circumvent anti-dumping duties. This was precisely the reason as to why the domestic industry, in the current proceedings as well as in the original investigations, pleaded before the Authority not to restrict the scope of the product under consideration on the basis of widths.
- (x) That the related importers of M/s Posco, Korea have not submitted the importer's questionnaire response. Further, no reasons have been advanced by them as to why the importer's questionnaire has not been filed by their related importers.
- (xi) That the responses of exporters/ producers from Korea cannot be accepted as they have failed to provide complete value chain. All the exporters of Posco Korea, has not responded and participated in the investigation. Therefore, their responses cannot be said as complete and needs to be rejected.

G.3 Examination by the Authority

40. The Authority has examined the issues raised by the domestic industry and other parties in their various submissions. The interested parties have contended that anti dumping duty cannot be continued by Ministry of Finance after expiry of existing anti dumping duty. The Authority notes in this regard that the decision of Hon'ble Delhi High Court was challenged before Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble Court has granted an interim stay on the operation of the orders of the Hon'ble Delhi High Court. In the present case, the investigation was initiated before expiry of the duty. The Authority also notes that in similar situations the Hon'ble Delhi High Court [NBR case of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. V/s UOI] upheld initiation of the sunset review investigations and permitted to continue the investigations despite the fact that the anti-dumping duties beyond the period of five years was set aside.
41. The interested parties have also argued that review proceedings cannot be carried on beyond one year period and therefore the present sunset review is required to be terminated. The Authority notes that constructive interpretation of Section 9 A (5) of the Act and Rule 23 of the Rules indicates that there is no specific bar on the continuation of the review investigations beyond one year from the date of initiation. Further, the Authority notes that the issue has been agitated by various parties before the Hon'ble Courts and the Courts have not yet ruled against this interpretation. In view of the aforesaid, the Authority accepts the contentions of the Domestic Industry that the only harmonious way to

read the various provisions mentioned above is to hold that sunset review proceedings can be carried on beyond one-year period without infringing upon any specific provision of law.

42. As regards the issue that the domestic industry has received adequate protection for last 5 years and continuation of the duty will adversely impact the user industry as the petitioners are using this protection to maximize their profits, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to domestic industry due to injurious effect of dumping. Further, it is also noted that the anti-dumping duty is not envisaged to provide undue protection to the domestic industry. Moreover, none of the interested parties has provided any evidence whatsoever, as to how the continuation of duties against imports from the subject countries would be detrimental to the larger interests of the economy or the country. However, the issues of undue protection, if any, has been examined in the relevant section so that the duty is not unduly imposed for a period beyond which it is required.
43. As far as adequacy of information submitted by the petitioner in its application for sunset review is concerned, the Authority notes that the prima facie evidence submitted by the petitioner was examined by the Authority before initiation of the investigation and being satisfied with the prima facie evidences the subject investigation was initiated. However, the actual determination is based on actual data of the responding exporters and importers and other facts available with the Authority. Therefore, the interests of the parties have not been compromised.
44. As regards, the submission of questionnaire responses by the exporters and related importers of POSCO, Korea is concerned, the Authority notes that the responses are in record and the issue has been addressed in determination of the dumping margin of this responding exporter/producer from Korea.
45. In their post disclosure submissions the domestic industry and the interested parties have reiterated their respective positions with regard to various aspects of the investigation. All other issues raised by the parties to the investigation have been dealt in the respective sections in this statement to the extent they are relevant and not repeated here for the sake of brevity.
46. In its post disclosure submissions the domestic industry has argued that nine of the cooperating exporters should be granted individual treatment as they have suppressed significant information with regard to their related parties involved in production and supply of the subject goods in various countries. It has been further argued that though two of the related importers of POSCO, Korea have filed importers' questionnaire response, the third related importer and processor located at Pune has not filed questionnaire response, therefore the response of POSCO should be rejected. The domestic industry has quoted the decision of the Authority in a recent finding of the Authority where the responses of certain exporters were rejected on the grounds that the related companies of the responding exporters did not file questionnaire response. In this connection the Authority notes that the questionnaire responses filed by the producers and exporters in this case provide sufficient and complete information required for the determination to the extent relevant and necessary and the information filed have been verified to the extent required. Determinations in the present case have not been in any way affected by alleged non-participation of the related parties of the cooperating exporters in other countries. If some related party of the responding producer/exporter in a third country, involved in production or sale of the subject goods, has not filed questionnaire response, the said party will automatically be covered under the non-cooperating residual duties. Therefore, neither the determinations nor the interests of the domestic industry have been affected due to non-participation of the so called related parties of the cooperating exporters in other countries. In view of the above, the objections of the domestic industry in this regard have not been accepted.
47. The domestic industry has further argued that the data of the responding exporters should be reconciled with DG Systems data as has been done in other cases. In this connection the Authority notes that reconciliation with DG System data or any other data base is resorted to in certain cases where there is certain data discrepancy in exporter's data or any prima facie evidence to that effect is available. It is neither a mandatory requirement, nor a general practice. No such specific discrepancy has been brought to the notice of the Authority during the course of the investigation necessitating such an exercise.

H. Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

H.1 Legal Positions

48. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that:-

"The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition."

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”

49. Accordingly, a sunset review investigation is to examine:

- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

50. Therefore, continuation of dumping and injury has been examined first before examining whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, and injury is likely to continue or recur in such a situation.

H.2 Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

51. The investigation was initiated against the goods originating in or exported from Peoples Republic of China, Republic of Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America. In response to the initiation notification the following producers/exporters have filed their questionnaire responses:

- i. M/s Acerinox Europa S.A.U, Spain
- ii. M/s Columbus Stainless (PTY) Ltd., South Africa
- iii. M/s POSCO, Korea
- iv. M/s Daewoo International, Korea
- v. M/s Hyundai Corporation, Korea
- vi. M/s Posco Thainox, Thailand

52. No response has been filed by any producer/exporter from Peoples Republic of China, Chinese Taipei, and the United States of America. Domestic industry has submitted that in the absence of response from these countries/territories normal values in these countries/territories should be constructed as per the best information available, including that of the domestic industry.

53. The Authority has considered the responses submitted by various interested parties and have arrived at the determination based on these submissions after verification, wherever considered necessary and unless rejected summarily. The Normal value has been arrived at by doing grade to grade comparison under each series, after applying the (ordinary course of trade test) OCT test and sufficiency test and as per the methodology prescribed under the rules. The export price and adjustments claimed have been allowed on the basis of submissions and verification, wherever undertaken.

54. Basis of determination of Normal Values and Export Prices with respect to the cooperating exporters and other non-cooperating exporters in the subject countries/territories were disclosed by the Designated Authority in the disclosure statement issued on 6th October 2015. The comments received from the interested parties with regard to the methodology and accuracy of the data therein have been examined to the extent they are relevant and considered for this final determination. Accordingly, the determination of degree and extent of current dumping from the subject countries have been outlined in the following paragraphs.

a. China PR

55. The domestic industry has submitted that China being a non-market economy, normal value of the subject goods in that country cannot be determined on the basis of price prevailing in that country and therefore, needs to be constructed. With regard to determination of a normal value in China the domestic industry has *inter alia* argued that:

- i. Market economy status cannot be granted unless the responding exporter/company and its group as a whole make a claim. In the present case, there is no claim for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment.
- ii. The normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit as per procedure described in Para 7 of Annexure I and consistent practice being followed by the Authority in case when no response has been filed by the exporter. Normal Value in China should be determined based on the cost of production in India, duly adjusted.
- iii. The normal value in China may be constructed by considering international price of the raw material and adopting the consumption norms and conversion cost as per the best information available, including that of the domestic industry.

Normal Values: China PR

56. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters has filed any response. The Authority notes that in the past several years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members.
57. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with Para 7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
58. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:
"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."
59. The Authority has examined the possibility of determination of the normal value in China in terms of first and second options in Para 7 of Annexure I of the AD Rules. In this regard it is noted that none of the interested parties has provided any meaningful information for selection of an appropriate third country as a surrogate country for determination of the normal value on the basis of cost and prices in that country or price from such country to other countries, including India as the normal value in China as per the first two alternatives in the Para 7 referred above.
60. Therefore, the normal value in China has been determined as per the third alternative provided in the Rules referred above and normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer/plant in India after making due adjustment for the international prices of major raw material. The Authority has also provided for reasonable profit as per its consistent practice. Accordingly, weighted average constructed normal values, for the grades/series of the goods originating in or exported from China PR, has been determined as follows:

Country	Series 200	Series 300	Series 400
	USD/MT	USD/MT	USD/MT
China	****	****	****

Export Prices: China PR

61. Weighted average export prices of the grades/series of the subject goods imported from China PR has been determined on the basis of the import data relied upon after adjusting the CIF price for ocean freight and insurance, inland freight and other handling expenses as per facts available, in the absence of cooperation from the exporters from China PR. The Authority also notes that the subject goods attract VAT refund @13%. Therefore, 4% VAT paid but not refunded has been adjusted to arrive at weighted average net ex-works export prices at series level as follows:

Particulars	UOM	200 Series	300 Series	400 Series
Net ex works export price	USD/MT	****	****	****

Dumping Margins: China PR

62. The weighted average Normal values at series level have been compared with the weighted average net export prices to arrive at the dumping margins as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series	400 Series	Wt Average
Qty in MT	7017	743	37	7797
Normal Value	****	****	****	
Export Price	****	****	****	
Dumping Margin	****	****	****	
Dumping Margin %	****	****	****	
DUMPING MARGIN Ranges	125-135	35-45	30-40	105-115

b. European Union

63. The Authority notes that as per the import statistics obtained from DGCI&S and analysed 2085 MTs of the subject goods have been imported from the European Union during the period of investigation covering 300 and 400 series. However, only one producing company located in the European Union i.e., M/s Acerinox Europa SAU, Spain, has filed its questionnaire response though questionnaires were sent to several producers in the European Union. Therefore, the Authority has determined the dumping margins for the exporters in the European Union based on the information provided by the cooperating exporter as well as facts available on record as follows:

Normal Values: Acerinox Europa , S A U, Spain (Acerinox)

64. Acerinox Group is one of the largest stainless steel producers in the world with their presence in Asia, Europe, Africa and America and produces both hot rolled and cold rolled stainless steel products. The questionnaire response filed by this cooperating producing exporter was verified through an on spot investigation. Acerinox, Spain produces and sells the subject goods in whole of European Union. For the purposes of this investigation, European Union being a single market, all sales to customers within EU countries have been considered as domestic sales. There were **** transactions of domestic sales within the European Union aggregating to **** MT of the subject goods. The company has produced three major grades of the subject goods in 300 and 400 series in the domestic market. The company had sold **** MT to unrelated parties in the domestic market compared to **** MTs sold to related parties in the home market. The average prices to related parties are found to be marginally higher compared to the prices to unrelated parties in the domestic market. Therefore, all sales in the domestic market has been considered for determination of Normal Value of this producing exporter.
65. The domestic sales transactions were subjected to ordinary course of trade test on the basis of verified grade-wise cost of production maintained by the Company for determination of Normal Values of individual grades for fair comparison with the respective grades in export transactions for determination of the dumping margins. Wherever the corresponding exported grades were not sold in the domestic market or the domestic transactions did not pass ordinary course of trade test the normal value has been determined on the basis of profitable sales transactions or verified cost of production plus

reasonable profit of 5% to arrive at the normal value of that grade. The domestic selling prices have been adjusted for all selling expenses, as verified, to arrive at ex-works prices. Accordingly, the ex-works Normal Values of various Grades of the subject goods produced and exported by Acerinox, Spain to India during the POI have been first determined at the individual grade level and then consolidated at the series level as follows:

Grade/Series	Quantity Sold in MT (of Grades exported to India)	NV US\$/MT
200	Nil	-
300	****	****
400	****	****
Total	****	

Export Prices: Acerinox Europa S A U, Spain

66. The company had exported only two grades of the subject goods, covering 300 and 400 series, totaling to **** MT directly to the unrelated Indian customers during the POI. All direct selling expenses, including expenses towards logistics, insurance, bank charges, commission and credit costs etc. incurred on the export sales to India have been adjusted to arrive at ex-works export prices of the grades/series exported to India works out as follows:

Grades	Sum of Quantity (MT)	Sum of Net Invoice value in USD	Sum of Total deductions (USD)	Sum of Ex-factory export Price	Net EP US\$/MT
200	-	-	-	-	-
300	****	****	****	****	****
400	****	****	****	****	****
Grand Total	****	****	****	****	****

Dumping margin: Acerinox Europa S A U, Spain

67. The ex-works normal values and the net-ex-works export prices, so determined, have been compared to determine the dumping margin for the responding exporter as follows:

Grade/Series	NV US\$/MT	Net EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM %
200	-	-	-	
300	****	****	****	
400	****	****	****	
Weighted Average			****	25-35%

All other exporters from the European Union

68. The Authority notes that there are a number of other producers of the subject goods in the European Union who produce and export the subject goods and participated in the original investigation. However, none of them have participated in the current review investigation. Since none of the other producers and exporters in EU has submitted any evidence with regard to the Normal Values and export prices of the subject goods the dumping margin for the remaining non-cooperative producers / exporters is proposed to be determined based on best facts available, taking into account the information submitted by the cooperating exporter from the European Union and the information available in the petition. Accordingly, the dumping margins for the non-cooperating exporters from the European Union have been determined as follows:

Grade/Series	Net EP US\$/MT	NV US\$/MT	DM US\$/MT	DM %
300 Series	****	****	****	
400 Series	****	****	****	
Weighted average	****	****	****	50-60%

c. South Africa

69. As per the DGCI&S data only **** MTs of the subject goods have been exported from South Africa during the POI. Only producing exporter in South Africa, i.e., by M/s Columbus Stainless (Pty) Ltd., South Africa, has filed the questionnaire response in this review investigation. The information submitted by this company was also verified in an on-spot investigation. The Authority has relied upon the information submitted by this cooperating producer/exporter for determination of their dumping margin as follows:

Normal Values: Columbus Stainless

70. The Company sold ****MT of the subject goods in the domestic market during the POI against **** transactions. All sales are to unrelated customers in South Africa. The domestic sales transactions were subjected to ordinary course of trade test on the basis of verified grade-wise cost to make and sale maintained by the Company for determination of Normal Values of individual grades for fair comparison with the respective grades in export transactions for determination of the dumping margins. Wherever the corresponding exported grades were not sold in the domestic market or the domestic transactions did not pass the ordinary course of trade test the normal value has been determined on the basis of profitable sales transactions only or verified cost of production plus reasonable profit of 5% to arrive at the normal value of that grade. All direct selling expenses have been deducted from the domestic transactions to arrive at the normal values at the ex-works level. Accordingly, the weighted average ex-works Normal Values of various Grades exported by Columbus to India during the POI have been first determined at the individual grade level and then consolidated at the series level as follows:

Columbus Stainless Pty Ltd., South Africa	Quantity Sold (of Grades exported to India)	NV
Series	MT	USD/MT
200	****	****
300	****	****
400	****	****
Total	****	

Export Prices: Columbus

71. During the POI, Columbus had exported **** MT of the subject goods to India covering all three series to unrelated customers in India. All direct selling expenses including, expenses towards logistics, insurance, bank charges and credit costs incurred on export sales to India have been adjusted to arrive at ex-works export prices of the grades/series exported to India works out as follows:

Columbus Stainless Pty Ltd., South Africa	Qty	EP
Series	MT	USD/MT
200	****	****
300	****	****
400	****	****
Total	****	

Dumping Margins: Columbus

72. The ex-works normal values and the net-ex-works export prices, so determined, have been compared to determine the dumping margin for the responding exporter as follows:

Columbus Stainless Pty Ltd., South Africa	Export Qty	EP	NV	DM	DM%
Series	MT	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%
200	****	****	****	****	
300	****	****	****	****	
400	****	****	****	****	
Total	****			****	10-20

Other exporters from South Africa

73. For all other exporters from South Africa dumping margins have been determined on the basis of information available in the questionnaire response filed by the cooperating exporter in Korea RP as follows:

Series	NV (US\$/MT)	EP (US\$/MT)	DM (US\$/MT)	%
200	****	****	****	
300	****	****	****	
400	****	****	****	
Total		****	****	45-55%

d. Korea RP

74. As per the DGCI&S import data analysed 2306 MTs of the subject goods were imported from Korea RP during the POI. M/s POSCO, Korea, who is a major producer and exporter of the subject goods in Korea has filed questionnaire response. During the POI POSCO has exported the subject goods to India through two Korean Trading Companies namely M/s Daewoo International and M/s Hyundai Corporation. POSCO has filed its questionnaire response as producer supported by the questionnaire responses of the above trading companies. The responses of POSCO and the trading companies named above were also verified in accordance with the procedure. The dumping margins of this Korean producer have been determined on the basis of the responses filed by them. Dumping margins for other non-cooperating producer/exporters from Korea have been determined on the basis of information filed by cooperating exporters and other facts available.

Normal Values: POSCO, Korea

75. POSCO is an integrated steel manufacturer and produces full range of carbon steel products, including hot-rolled coil and sheet, alloy steel, cold-rolled coil and sheet, electrical coil, galvanized coil and sheet, plate, and wire rod, as well as various stainless steel coil and sheet products. POSCO sold **** MT of the subject goods of wide range of grades in the domestic market during the POI to both related as well as unrelated customers in Korea against **** transactions. POSCO has single channel of distribution and sold its product concerned to domestic customers directly from the factory or from the warehouses. The related party sales are about ****% of the total sales in the domestic market. However, only few grades have been exported to India and in case of grades sold to India the related party sales is about ****% and the average prices to related parties is higher compared to the average price to unrelated buyers in the domestic market. Therefore, all sales of the relevant grades exported to India, including related party and unrelated party sales have been considered for determination of Normal Value for POSCO for like to like comparison with the export transactions and determination of dumping margin. POSCO, Korea, in its comments to the disclosure statement, has pointed out certain errors in sorting of domestic sales transactions while determining the Normal Value. The errors have been rectified and the normal values have determined accordingly.

76. The domestic sales transactions have been subjected to ordinary course of trade test on the basis of verified grade-wise cost of production maintained by the Company for determination of Normal Values of individual grades for fair comparison with the respective grades in export transactions for determination of the dumping margins. Wherever the corresponding exported grades were not sold in the domestic market or the domestic transactions did not pass ordinary course of trade test the normal value has been determined on the basis of profitable sales transactions or verified cost of production plus reasonable profit of 5%. Domestic sales have also been adjusted for all selling expenses as verified. Accordingly, the weighted average ex-works Normal Values of various Graded exported by POSCO to India during the POI are proposed to be first determined at the grade level and then consolidated at the series level as follows:

POSCO Korea	Quantity Sold (of Grades exported to India)	NV
Series	MT	USD/MT
200	-	-
300	****	****
400	****	****
Total	****	

Export Prices: POSCO, Korea

77. During the period of investigation POSCO sold **** MT of CR Coils, falling within the scope of the product under consideration, to two traders in Korea namely M/s Daewoo International and M/s Hyundai Corporation for exports to India. **** MTs were exported through the unrelated trader i.e., Hyundai Corporation. Balance **** MTs were sold to their related trading Company M/s Daewoo International for exports to India. The goods have however, been shipped directly to India from the production facility of POSCO to the customers of the trading companies, while the commercial invoices were raised by the trading companies on the Indian Customers. Hyundai Corporation and Daewoo International have also filed separate questionnaire responses. All the responses have been verified through on-spot investigations. Certain minor errors in calculation of the export prices as pointed out by the exporter, in its post disclosure comments, have also been taken into account in determination of the export prices.

(i) POSCO: through Hyundai Corporation

78. Hyundai Corporation has reported export of **** MTs of the subject goods manufactured by POSCO to unrelated customers in India. The export sales are on CIF terms. POSCO and Hyundai have provided the details of expenses towards logistics, handling, insurance cost, ocean freight and credit cost etc. to arrive at ex-works price. Accordingly, net ex-works prices of exports by POSCO through Hyundai Corporation works out as under:

POSCO	Grade	Sum of Quantity	Net EP US\$/MT
HYUNDAI CORPORATION	200 Series	-	-
	300 Series	****	****
	400 Series	-	-

(ii) POSCO: through Daewoo Corporation

79. Though POSCO had supplied **** MTs of the subject goods to Daewoo for exports to India Daewoo has exported 399.888MTs of stainless steel flat products conforming to the scope of Product Under Consideration and rest were slit by them in local service centre of POSCO to lower widths as per the requirements of the customer and exported to India as non-PUC. Daewoo has exported the goods to its related parties in India as well as unrelated customers. The related customers in India, i.e., POSCO India Delhi Steel Processing Centre PVT. Ltd. (IDPC) and POSCO India Chennai Steel Processing Centre Pvt. Ltd. (ICPC), as well as the trading Co. i.e., Daewoo International, have filed separate questionnaire responses. Therefore, all entities have been treated as a single entity for determination of the export price, which has been constructed in terms of Section 9A(1)(b) of the Act taking into account the price at which the goods have been first resold by IDPC and ICPC in India. Accordingly, constructed net ex-works export prices of POSCO exported through Daewoo International works out as under:

POSCO	Grade	Quantity	Constructed EP US\$/MT
Daewoo International	200 Series	-	-
	300 Series	-	-
	400 Series	****	****

80. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has submitted that the Authority should confirm deduction of all sales related expenses and profit margins of Daewoo and the related importers while arriving at the ex-works export

price of the producer in view of the relationship of the parties involved in the transactions. In this connection the Authority notes that the intermediate related parties i.e., M/s Daewoo and IDPC and ICPC have sold the goods at sufficient margins to cover the sales related expenses and profit.

81. POSCO, in its post disclosure comments, has argued that adjustment of duty drawback, as claimed by them, should have been allowed by the Authority as this adjustment is granted to neutralize the impact of duties and taxes paid on raw materials/inputs which are refunded / rebated in case of exports of goods. Differences in sales price due to difference in levels of taxation on inputs do not constitute unfair pricing behavior. The Authority notes that the claim of adjustment of duty drawback could not be adequately substantiated with clearly verifiable evidence directly linked to the product exported to India. Therefore, the claim could not be accepted.

Dumping Margins for POSCO and its exporters

82. The ex-works normal values and the net-ex-works export prices, so determined, have been compared to determine the dumping margin for the above responding producer and exporters as follows:

Producer: POSCO, Korea	Export Qty	EP	NV	DM	DM%
Exporter: Hyundai Corporation					
Series	MT	USD/MT	USD/MT	USD/MT	
200	-	-	-	-	
300	****	****	****	****	20-30
400	-	-	-	-	
Total	****	****	****	****	20-30
Exporter: Daewoo International					
Series					
200	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	
400	****	****	****	****	0-10
Total	****	****	****	****	0-10
Product as a whole					20-30

All other exporters from Korea RP

83. For all other exporters from the Korea RP dumping margins have been determined on the basis of information available in the questionnaire response filed by the cooperating exporter in Korea RP as follows:

All Others	EP	NV	DM	DM%
Series				
200	-	-	-	
300	****	****	****	40-50%
400	****	****	****	30-40%
Weighted average	****		****	35-45%

e. Thailand

84. As per the DGCI&S import data analysed 1394 MTs of the subject goods were imported from Thailand during the POI. M/s POSCO, Thainox, who is a major producer and exporter of the subject goods in Thailand has filed questionnaire response.

POSCO, Thainox, Thailand

85. POSCO Thainox produces cold rolled products from the HR/black coils procured from other producers and carries out annealing & pickling, cold-rolling and surface finishing. During the POI POSCO Thainox has exported the **** MTs of the subject goods to India. The Company has exported the subject goods to India directly as well as through Hyundai Corporation, an unrelated Trading Company, located in Korea RP. The Company exported **** MT of subject goods through Hyundai Corporation and rest was exported directly. M/s Hyundai Corporation has also submitted the information related to the exports of goods manufactured by POSCO Thainox. The responses of POSCO Thainox and its trading company named above were also verified in accordance with the procedure. Therefore, the dumping margin of this Producer-exporter from Thailand has been determined on the basis of the responses filed by the cooperating exporters and other facts available as follows:

Normal Values: Posco Thainox

86. Thainox had sold a total quantity of *** MT of the subject goods in the domestic market covering a wide range of grades. Out of total domestic sales only *** MT (****%) were sold to its affiliated companies in Thailand. However, against large number of grades sold in domestic market only 6 grades were exported to India during the POI. Therefore, for fair like to like comparison only grades exported to India have been considered for determination of normal value of this exporter. **** MTs of comparable grades were sold in the domestic market and 100% of the sales were to unrelated customers in Thailand. The domestic sales transactions have been subjected to ordinary course of trade test on the basis of verified grade-wise cost of production maintained by the Company for determination of Normal Values of individual grades for fair comparison with the respective grades in export transactions for determination of the dumping margins. Wherever the corresponding exported grades were not sold in the domestic market or the domestic transactions did not pass ordinary course of trade test the normal value has been determined on the basis of profitable sales transactions or verified cost of production plus reasonable profit of 5% to arrive at the normal value of that grade. The exporter has also provided the details of direct selling expenses in the domestic market to arrive at the ex-works prices which was also verified in on-spot investigation. Accordingly, the ex-works normal values of this producing exporter have been determined as follows:

POSCO, Thainox	Qty MT	NV
Series	MT	USD/MT
200	-	-
300	****	****
400	-	-
Total	****	****

Export Prices: POSCO Thainox

87. M/s POSCO Thainox has exported ****MT of the subject goods under ****Transactions during POI for a total value of THB ****. The Company has exported the subject goods to India directly as well as through Hyundai Corporation, an unrelated Trading Company, located in Korea RP. The Company exported **** MT of subject goods through Hyundai Corporation and rest was exported directly. The goods have been shipped directly to India from the production facility of Thainox to the customers in India. In cases of the exports through the trading company only commercial invoices were raised by the trading company on the Indian Customers while goods were directly shipped by Thainox. Hyundai Corporation has also filed separate questionnaire responses covering these transactions.

88. The exports are on CIF and FOB terms and the payment has been received through L/Cs or TT. Thainox and Hyundai have provided the details of expenses towards logistics, handling, insurance cost, ocean freight wherever applicable, packing cost, bank charges and credit cost for the credit periods availed to arrive at ex-works price. Accordingly, net ex-works prices of exports by Thainox directly and through Hyundai Corporation works out as under:

Thainox	Series	Sum of Quantity	NET EP US\$/MT
Direct	300 Series	****	****
Hyundai	300 Series	****	****
Total		****	****

Dumping Margin: Thainox and its exporters

89. The ex-works normal values and the net-ex-works export prices, so determined, have been compared to determine the dumping margin for the above responding producer and exporters as follows:

Producer: POSCO Thainox	Export Qty	EP	NV	DM	DM%
Exporter: Direct					
Series	MT	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%
200	-	-	-	-	
300	****	****	****	****	0-10%
400	-	-	-	-	
Total	****	****	****	****	0-10%
Exporter: Hyundai Corporation					
Series					
200	-	-	-	-	
300	****	****	****	****	20-30%
400	-	-	-	-	
Total	****	****	****	****	20-30%

All other Exporters in Thailand

90. For all other exporters from Thailand dumping margins have been determined on the basis of information available in the questionnaire response filed by the cooperating exporter in Thailand as follows:

All Others	EP	NV	DM	DM%
Series				
200	-	-	-	-
300	****	****	****	25-35%
400	-	-	-	-
Total	****	****	****	25-35%

f. USA

91. The Authority notes that none of the producers of the subject goods in the United States of America has responded to the initiation notification or provided any information for determination of Normal Values and Export prices of the subject goods from that country though about 1014 MTs of the subject goods have been imported from this country as per the import data examined. Therefore, in the absence of any other information about the prices of the subject goods sold in the domestic market and exported to India the determination of dumping margins for the producers and exporters from this country have been determined on facts available basis as follows:

Normal Values: USA

92. In the absence of the domestic selling prices of the subject goods in USA, due to non-participation of any producer, Normal Value in that country has been determined in terms of second proviso of Sec 9A(1)(c) of the Act taking into account the cost of production of the said article in the country of origin alongwith reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profit on the basis of facts available. For the purpose of this determination, to the extent possible, international costs of raw materials, consumption norms and conversion costs of the domestic industry has been adopted as best facts available and reasonable profit margin of 5% has been added to arrive at the normal values of the respective grades/series of the product exported to India, as per the information available in the imports statistics relied upon. Accordingly, weighted average normal values, at the series level, for all producers/exporters from USA works out as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series	400 Series
Normal Value	****	****	****

Export Prices: USA

93. Weighted average export prices of the grades/series of the subject goods imported from USA are proposed to be determined on the basis of the import data relied upon after adjusting the CIF price for ocean freight and insurance, inland freight and other handling expenses, as per facts available, in the absence of cooperation from the exporters from this country, as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series	400 Series
Export Price	****	****	****

Dumping Margins: USA

94. The weighted average Normal values at series level have been compared with the weighted average net export prices to arrive at the dumping margins for all producers/exporters in USA as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series	400 Series	Wt Average
Qty	118	836	55	1009
Normal Value	****	****	****	****
Export Price	****	****	****	****
Dumping Margin	****	****	****	****
Dumping Margin %				40-50%

g. Taiwan

95. The Authority notes that none of the producers of the subject goods in Taiwan has responded to the initiation notification or provided any information for determination of Normal Values and Export price of the subject goods from that country though about 322 MTs of the subject goods have been imported from this country as per the import data examined. Therefore, in the absence of any other information about the prices of the subject goods sold in the domestic market and exported to India the determination of dumping margins for the producers and exporters from this country have been determined on facts available basis as follows:

Normal Values: Taiwan

96. In the absence of the domestic selling prices of the subject goods in Taiwan due to non-participation of any producer, Normal Value in that country has been determined in terms of second proviso of Sec 9A (1)(c) of the Act taking into account the cost of production of the said article in the country of origin alongwith reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profit on the basis of facts available. For the purpose of this determination, to the extent possible, international costs of raw materials, consumption norms and conversion costs of the domestic industry has been adopted as best facts available and reasonable profit margin of 5% has been added to arrive at the normal values of the respective grades/series of the product exported to India as per the information available in the imports statistics relied upon. Accordingly, weighted average normal values at the series level for all producers/exporters from Taiwan works out as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series
Normal Value	****	****

Export Prices: Taiwan

97. Weighted average export prices of the grades/series of the subject goods imported from Taiwan have been determined on the basis of the import data relied upon after adjusting the CIF price for ocean freight and insurance, inland freight and other handling expenses as per facts available, in the absence of cooperation from the exporters from this country as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series
Export Price	****	****

Dumping Margins: Taiwan

98. The weighted average Normal values at series level have been compared with the weighted average net export prices to arrive at the dumping margins for all producers/exporters in Taiwan as follows:

USD/MT	200 Series	300 Series	Wt Average
Qty	70	252	322
Normal Value	****	****	****
Export Price	****	****	****
Dumping Margin	****	****	****
Dumping Margin %			45-55%

Dumping Margin Table: All Countries

Country/ Producer	Series/ Exporter	200	300	400	Weighted Average (Product as a whole)	%
China PR						
Any Producer	Any Exporter	****	****	****	****	100-115
S. Korea						
POSCO Korea	Hyundai Corp.	****	****	****	****	20-30
POSCO Korea	Daewoo International	****	****	****		
Any Other Producer	Any Other Exporter	****	****	****	****	35-45
Taiwan						
Any Producer	Any Exporter	****	****	****	****	45-55
S. Africa						
Columbus Stainless	Columbus Stainless	****	****	****	****	10-20
Any Other Producer	Any Other Exporter	****	****	****	****	45-55
Thailand						
POSCO Thainox	POSCO Thainox	****	****	****	****	5-15
POSCO Thainox	Hyundai	****	****	****		
Any Other Producer	Any Other Exporter	****	****	****	****	25-35
USA						
Any Producer	Any Exporter	****	****	****	****	40-50
EU						
Acerinox	Acerinox	****	****	****	****	25-35
Any Other Producer	Any Other Exporter	****	****	****	****	50-60

99. The Authority notes that the margins of dumping of the goods originating in or exported from each of the subject countries, as determined above are significant.

I. Examination of injury to the domestic industry and Causal Links

100. As noted earlier, in a sunset review investigation, with regard to injury examination, the Authority is required to examine:
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue in the event of revocation of anti dumping duties;
 - In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.
101. The domestic industry has *inter alia* submitted that there is continued dumping of the product under consideration from the subject countries though the volume of dumped imports has declined as a result of current anti-dumping duties and dumping is likely to intensify should the current anti-dumping duties are revoked.
102. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject countries. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.
103. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... Taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the prices of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
104. It is noted that the application for continuation of antidumping duty has been filed by M/s Jindal Stainless Limited, who command a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the petitioners have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioner, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

I.1 Views of the responding Exporters and Importers on the injury claims of domestic industry

105. The exporters, importers and other interested parties, in their various submissions with regard to the injury and causal link, have argued as follows:
- i. That as per the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India in Rishiroop Polymers matter, the Designated Authority should examine the conditions which existed at the time of imposition of anti-dumping duty and compare such conditions with the present scenario to see whether the conditions have altered to such an extent that continuation of duty is no longer required.
 - ii. That at the time of the original investigation, the share of imports from all subject countries in demand was 34% and the share of domestic industry in demand was 42%. However, in the present POI, share of imports from subject countries have drastically fallen to 5.39% in demand, while the share of domestic industry has dramatically increased to 82%. In light of such low imports from the subject countries and the fact that the domestic industry is in a dominant position in the domestic market, the present review against the subject countries should be terminated
 - iii. That there is no injury on account of the subject imports as the volume of imports from the subject countries is very low in absolute term as well with respect to the demand in India.
 - iv. That during these 5 years the domestic industry had been providing subject goods at an exorbitant rate and thereby increasing their profits, without making any effort to improve the situation by offering the product at a competitive rate. Now the domestic industry wants to continue the levy so that it can continue to make profits at the cost of Indian consumers and Indian economy.

- v. That the presumptions of the petitioner that the domestic price of the subject goods went down because of presence of dumped imports is incorrect considering the fact that pricing of CR Steel, especially 300 series depends largely on raw material prices.
- vi. That the argument of the Applicant Domestic Producers that it is fixing its price based on import prices is an absolute falsity. As can be perused from the petition filed by the Applicant Domestic Producers, accounts for significant market share and imports from subject countries holds a market share of mere 3.85%. Compared to the miniscule share of imports from the subject countries, the domestic producers commands around 85% of the market share. The claim of domestic industry is mere rhetoric and needs to be rejected by the Authority.
- vii. That due to the high cost of the local subject goods, the processing industry is facing the threat of extinction as customers are showing less interest to buy their goods. If this trend continues, the downstream industry will vanish from the scene and thousands of families will be out in the street due to unemployment.
- viii. That the injury parameters do not show any injury to the domestic industry as domestic industry's production and sales consistently improved during the injury analysis period. Moreover, from the very limited non-confidential information provided in the application, it can be clearly inferred that there is even no causal link between the imports from subject countries and performance of the domestic industry.
- ix. That excess capacity, high interest cost and depreciation cost are causing injury to the domestic industry.
- x. That the price undercutting and price underselling analysis provided in the petition pertain to POI and not for post POI period. Unless information with respect to post POI is examined, it cannot be said that there is a likelihood of injury to the domestic industry.
- xi. That the profit & loss account of Petitioner Company for the last few years shows that during 2012-13 the domestic industry incurred a significant amount towards power and fuel expense, which was one of the critical reasons for losses to the Petitioner.
- xii. That the likelihood determination under Article 11.3 entails an analysis of future events based on positive evidence available and as a result, the mere computation of a dumping margin will not discharge the burden required under Article 11.3. It is further contented that in the petition filed by the domestic industry, there is no post-POI data given.
- xiii. That the interested parties requested the authority to direct the domestic industry to submit the Post-POI data in order to conduct likelihood determination by the authority and also provide the interested parties a copy of the same for their comments thereon.
- xiv. That the evidences provided by the domestic industry in relation to freely disposable capacities in the subject countries are not fully substantiated.
- xv. That the domestic industry has provided no evidence to establish the likelihood of recurrence of dumping. Moreover, there is no merit in the argument of domestic industry provided in relation to likelihood of recurrence of dumping.
- xvi. That the domestic industry has determined non-injurious price and resultant price underselling based on some confidential consideration, without even disclosing the components included. It is very much likely that Petitioner has not determined non-injurious price based on principles enunciated under Annexure III of the AD Rules. The Authority should determine the non-injurious price keeping in view information brought forward by the interested parties and by applying the principles provided under Annexure III of the anti-dumping rules.
- xvii. That DG Safeguards, in March 2015, in its investigation against import of Cold-Rolled Steel Products of 400 series, concluded that the domestic industry suffers injury due to intrinsic reasons such as high finance charges and depreciation charges leading to operational losses and not imports.

I.2 Submissions by the Domestic Industry

106. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- i. That the Authority may kindly appreciate the fundamental differences between the original and sunset review investigations. In original investigations, the Authority needs to establish whether dumping exists during the period of investigation and the relationship between dumped imports and injury caused to the domestic industry. On the other hand, dumping, current injury and their causal relationship are not relevant in a sunset review. This view and interpretation of the law has been adopted by the Appellate Body in relation to the nature and scope of the sunset review in several matters.
- ii. That in a sunset review where only the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury are required to be determined, the importance of current imports into India recedes into background while reaching the conclusion on likelihood.
- iii. That the arguments of the interested parties that the imports are *de minimis* is irrelevant as the principle of *de minimis* imports is not applicable in case of sunset review investigations. In this context, the domestic industry further submitted that the exporters from the subject countries have been circumventing the duties by bringing widths above 1250mm in India which were excluded from the purview of duties in the original investigations. It is due to this fact that the imports of the widths below 1250mm appear to be lower as the widths are interchangeably used.
- iv. That grade-wise/series-wise analysis should be carried for all the subject countries for fair and proper comparison. The domestic industry also agrees with the proposition of the exporters insofar as it relates to price analysis including price undercutting, price underselling, etc. It is further submitted that Domestic Industry has already provided all the relevant data and analysis to the Authority in the manner prescribed by the Authority.
- v. That the domestic industry has provided all the information as per the requirements of the law. Moreover, it is only after getting satisfied with all the evidence that the Authority has initiated the sunset review investigation. The domestic industry reiterates that the petition fulfills all the requirements of law in terms of Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules.
- vi. That the exporters from the subject countries have not denied the allegation made by the domestic industry that the exporters continue to dump the subject goods. It is a settled principle that continued dumping is a very good indicator of the fact that there is every likelihood of continued dumping in the event duties are not extended.
- vii. That the import data clearly establishes that the landed values from subject countries are seriously undercutting the prices of domestic industry. Further, due to presence of dumped and injurious imports, domestic industry's prices of subject goods are significantly suppressed.
- viii. That the exporters from the subject countries have not provided any volume related information and therefore, domestic industry is handicapped to make any submissions or to assist the Authority in relation to their claims and submissions.
- ix. That the domestic industry has followed the guidelines issued and followed by the Authority while constructing and providing the non-injurious price in the application for the purpose of the initiation of the sunset review investigation. It may also be important to note that the Authority has examined the information supplied by the Domestic Industry thoroughly even at the time of initiation. Therefore, the arguments of the interested parties that the domestic industry has not followed principles followed laid down in Annexure III are wrong and contrary to the facts on record.
- x. That the price underselling is significantly positive, and therefore, there is clear likelihood of increase in the imports of the subject goods in India at such injurious prices from the subject countries in the event Authority reaches a conclusion to withdraw the anti-dumping duty.
- xi. That the injury margin and dumping margin are significantly positive which is also a clear indicator that the likelihood of continuation of dumped and injurious imports of the subject goods is imminent in the event the Authority reaches a conclusion to withdraw the Anti-dumping duty.

- xii. That there is no change in the pattern of consumption with regard to the product under consideration.
- xiii. That there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- xiv. That technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in coming future. Developments in technology are therefore, not a factor of injury.

I.3 Examination by the Authority

- 107. The various submissions of the interested parties and the domestic industry on injury to the domestic industry have been taken note of and have been examined as per the information available on record in the relevant parts in this examination. All relevant issues concerning the facts and figures are addressed *ipso facto* in the injury analysis.
- 108. With regard to the scope of the sunset review, as argued by the interested parties, the Authority notes that the scope of original investigation, mid-term review and sunset review are materially different and have been well defined and settled by the various appellate forums. The Authority has been consistently following those settled principles and the same principles have been applied in this investigation also. While current level of imports, dumping margins and injury margins are also examined in a sunset review the focus is on the likelihood scenario to see what is likely to happen if the duties are removed. Therefore, while the current dumping and injury are guiding factors, they are not deterministic. Accordingly, the arguments of the interested parties that the volumes of imports are low or de minimis and therefore, investigation should be terminated are not tenable. The principles of *de minimus* limits are not applicable in case of sunset review investigations
- 109. With regard to the submissions made by interested parties that the Domestic Industry is exploiting the anti-dumping provisions to establish their monopoly in India, it is noted that the purpose of the anti-dumping law is to create a level playing field for production and consumption of the goods in the Indian market by protecting domestic production of the goods against unfair trade practices of producers from other countries. It is also noted that existence and sustainability of a domestic production base is important for general economic development which has to be protected against injurious dumping. In any case, imposition of anti-dumping duties does not create a situation of monopoly as the imports from other suppliers including those from the subject countries are not prevented from competing in the Indian market. However, the Authority has examined the cost and price behavior of the domestic producers in this finding in an objective manner to arrive at the conclusion on injury and causal link to address the concerns of the consumer industry.
- 110. As regards the data of the various parties the Authority notes that data and information as verified during the course of investigation, to the extent considered necessary and feasible, have been used in this investigation.
- 111. As regards the arguments of the interested parties that Post POI data should be considered for examination of the likelihood analysis, the Authority notes that Antidumping duties were in force for a substantial part of the post POI period and therefore, the data for this period may not provide a clear indication of the trends, Nevertheless the post POI data on various parameters have been adequately examined in the relevant sections of the likelihood analysis to the extent such data was available and considered necessary.
- 112. As regards the arguments of the interested parties that the injury suffered by the domestic industry due to high depreciation cost and fuel etc. the argument has been noted and appropriately addressed while computing the Non-injurious price of the domestic industry. Therefore, injury, if any, caused due to these factors have not been attributed to the dumped imports.
- 113. As regards the findings of DG Safeguards, with respect to its investigation against import of Cold-Rolled Steel Products of 400 series, is concerned, the Authority notes that the proceedings before that Authority is of a different nature and for a part of the product covered under this investigation. The current investigation is a sunset review of antidumping duty in force and the scope of this investigation is entirely different. The Authority, however, has noted the issues raised and has appropriately examined them in the factual matrix of the present case.
- 114. As regards the post POI data the Authority notes that post POI data has been adequately examined to analyse the likelihood of dumping and injury in the appropriate section in this disclosure.

115. All other issues raised by the parties to this investigation have been addressed in the appropriate places and therefore, not repeated here.

J. Examination of current Injury and Causal Link

116. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
117. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined in the following paragraphs.
118. The Authority notes that this review investigation has been initiated to examine the alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the Peoples Republic of China, Republic of Korea, the European Union, South Africa, Chinese Taipei, Thailand and the United States of America, and consequent injury to the domestic industry. In view of the fact that the goods are continuing to enter the Indian market from the subject countries at dumped prices and the conditions of *inter se* competition between the dumped imported articles and the like domestic articles exists cumulative assessment of the effects of imports is appropriate to examine the injury and causal links. Therefore, the Authority proceeds to examine the impacts of dumped imports accordingly.

(a) Volume Effects of Dumped imports

119. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

(i) Import volumes & share in imports

120. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject countries/territories and other countries based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S. Transaction-wise import data considered by the Authority has also been placed in the public file in view of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in SanDisk matter. The Authority notes that Cold Rolled Flat Products of Stainless steel, falling under Customs heading 7219, are being imported in various sizes of width whereas the product under consideration in this investigation covers width range 600 to 1250mm only. Therefore, the import data has been pruned on a reasonable basis for estimation of volume of imports for the product under consideration. Accordingly, volume of imports of the subject goods during the injury investigation period, as per the above analysis, are as follows:

Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI	Post POI (A)
China PR	MT	1996	4257	9092	7797	4117	8235
Chinese Taipei	MT	176	289	211	322	216	432
EU	MT	1948	3285	3248	428	1204	2407
Korea RP	MT	14626	20596	2583	1188	376	752

South Africa	MT	624	33	56	166	551	1102
Thailand	MT	797	729	1320	1376	624	1248
U S A	MT	97	512	1399	1014	904	1808
Imports from subject countries (MT)	MT	20264	29701	17909	12291	7992	15984
Trend	Indexed	100	147	88	61	39	79
Imports from other countries (MT)	MT	24588	31566	48593	38556	18034	36068
Trend	Indexed	100	128	198	157	73	147
Total Imports (MT)	MT	44852	61267	66502	50847	26026	52052
Trend	Indexed	100	137	148	113	58	116
Share of subject countries in Imports	%	45%	48%	27%	24%	31%	31%
% Share of other countries in Imports	%	55%	52%	73%	76%	69%	69%

121. The above data indicates that total imports from the subject countries have declined by about 21% in POI compared to the base year though imports from China PR has significantly increased by over four times. Major decline in imports is from Korea RP. However, the domestic industry has argued that the exporters in these countries have resorted to exports of higher widths or exported the PUC in slit conditions, as there is width restriction in the product under consideration. Therefore, while the import volume of product under consideration is low actual import of Cold Rolled Flat products would be much higher.
122. The Authority notes that the product under consideration in the original investigation was defined with width restrictions. Therefore, this review investigation has been restricted to these widths only. However, it is possible that significant exports are taking place beyond the widths specified and in certain instances it has been noted that the goods have actually been slit to lower widths and exported as per customer requirement. In fact the import data indicates that the volume of imports of the product outside the width ranges specified is significant as may be seen from the table below:

Widths above 1250MM	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI Annualized
China P RP	MT	616	144	7737	18942	17848	19188	16202
Chinese Taipei	MT	2326	896	5988	6871	2114	1591	13877
EU	MT	10612	8960	23735	23757	19604	16422	28952
Korea RP	MT	2818	234	4688	10276	27554	28523	3611
South Africa	MT	2596	1278	1606	1861	3359	2143	2561
Thailand	MT	716	59	1451	1585	979	788	3424
U S A	MT	252	249	1598	6263	7889	8197	8513
Imports from subject countries (MT)	MT	19936	11820	46804	69555	79346	76852	77140
Trend	Indexed	100	59	235	349	398	385	387

123. The above data indicates that though the imports of the Cold Rolled flat products, as a whole, from the subject countries, have increased significantly during the injury investigation period the import of product under consideration has declined while products outside scope of this investigation has increased by about 300% over the base year. In fact the transaction-wise data indicates that in certain product types/grades/ series the imports have completely shifted from the widths covered under the product under consideration to the widths outside the range giving credence to the arguments of the domestic industry.
124. In view of the above position the Authority notes that the arguments of the interested parties that the volume of imports of the subject goods are low and therefore, does not affect the domestic industry do not appear to be correct.

(ii) Demand & Market Share

125. Demand or apparent consumption of the product under consideration in the country has been estimated as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The trend in demand and share of domestic industry and dumped imports in the total demand are as follows:

Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI	Post POI (A)
Domestic Sales of the Applicant	MT	121191	147564	177949	209827	138446	276893
Trend	Indexed	100	122	147	173	114	228
Sales of Other Domestic Producers	MT	34124	38844	56119	58925	32500	65000
Trend	Indexed	100	114	164	173	95	190
Dumped Imports from subject countries	MT	20264	29701	17909	12291	7992	15984
Trend	Indexed	100	147	88	61	39	79
Imports from other countries	MT	24588	31566	48593	38556	18034	36068
Trend	Indexed	100	128	198	157	73	147
Total Imports	MT	44852	61267	66502	50847	26026	52052
Trend	Indexed	100	137	148	113	58	116
Total demand in India	MT	200167	247675	300570	319599	196972	393945
Trend	Indexed	100	124	150	160	98	197
% Share of subject countries in demand	%	10.12	11.99	5.96	3.85	4.06	4.06
% Share of other countries in demand	%	12.28	12.74	16.17	12.06	9.16	9.16
% Share of domestic industry in demand	%	60.55	59.58	59.2	65.65	70.29	70.29
% Share of other domestic producers in demand	%	17.05	15.68	18.67	18.44	16.5	16.5
Total		100	100	100	100	100	100

126. The above data indicates that there is a healthy growth in demand for the subject goods in the country and the demand has increased by about 60% during the injury investigation period. The market share of the domestic industry during the same period increased by about 5% in absolute term and share of the subject countries declined by about 6%. However, as noted above the imports of the subject goods from the subject countries/territories have declined whereas the goods outside the scope of the product under consideration have considerably increased. Since there is a significant shift in imports from the product with widths as defined in the PUC to products of higher width or lower widths the above demand and market share analysis based on the subject goods alone do not present the true volume impact of dumped imports on the domestic industry in terms of market share and the decline in market share of the dumped imports as argued by the interested parties does not appear to be correct.

(b) Price effect to dumped imports and impact on domestic industry

127. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Therefore, the impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression.
128. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the weighted average landed values of imports from the subject countries. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The landed values of the imports have been determined taking into account corresponding grade-wise and series-wise import data from the subject countries.

i. Price Undercutting effects

129. For the price undercutting analysis the weighted average domestic selling prices of the subject goods have been compared with the weighted average landed values of the subject goods imported from the subject countries as stated above. The price undercutting of imports from all subject countries at cumulated level works out as follows:

Country	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (Annualized)
Subject Countries	Qty MT	20,263	29,700	17,908	12,291	15983
Trend	Indexed	100	147	88	61	79
Net Sales Realization	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	96	140	131	131
Landed Value without ADD	Rs./MT	98,277	91,355	1,19,979	93,429	113900
Trend	Indexed	100	93	122	95	116
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	0 - 10	0 - 10	15-25	40-50	15-25
Landed Value with ADD Duty	Rs./MT	105670	97631	134719	108203	138274
Trend	Indexed	100	92	127	102	131
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	****	****	****	(****)
Price Undercutting with ADD	%	(****)	****	****	****	(****)
Price Undercutting with ADD	Range	(5) - 5	0 - 10	0 - 10	20 - 30	(5) - 5

130. The above data indicates that the imports from the subject countries without application of antidumping duty are undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market and the level of price undercutting has significantly increased over the injury investigation period though the quantities of imports decreased during the same period notwithstanding the overall increase in imports if the imports outside the defined width ranges are considered.
131. Though the injury is required to be analysed cumulatively, price undercutting of the imports from each of the subject countries/territories have also been examined to see the trends. At the individual country level the price undercutting margins work out as under when the weighted average landed values of imports from the individual countries are compared with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the corresponding grades/series of the subject goods.

China PR	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (Annualized)
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	0-10	25-35	15-25	65-75	0-10
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	****	****	****	(****)
Price Undercutting with ADD	%	(****)	****	****	****	(****)
Price Undercutting with ADD	Range	(5) - 5	0 - 10	0 - 10	20 - 30	(5) - 5

Chinese Taipei						
Price Undercutting	Rs./MT	(****)	(****)	(****)	****	****
Price Undercutting	%	(****)	(****)	(****)	****	****
Price Undercutting	Range	(10) - 0	(10) - 0	(5) - 5	0-10	45-50
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	(****)	(****)	(****)	****
Price Undercutting with ADD	%	(****)	(****)	(****)	(****)	****
Price Undercutting with ADD	Range	(20)-(10)	(15)-(5)	(10)-0	(10)-0	15-25
European Union						
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	0-10	0-10	10-20	20-30	0-10
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	(****)	(****)	****	(****)
Price Undercutting with ADD	%	(****)	(****)	(****)	****	(****)
Price Undercutting with ADD	Range	(15) - (5)	(10) - 0	(5) - 5	0 - 10	(15) - (5)
Korea RP						
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	0-10	0-10	0-10	25-35	0-10
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	****	****	****	(****)
Price Undercutting with ADD	%	(****)	****	****	****	(****)
Price Undercutting with ADD	Range	(10) - 0	0 - 10	0 - 10	15 - 25	(25) - (15)
South Africa						
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	15-25	50-60	50-60	15-25	15-25
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	****	****	(****)	(****)
Price Undercutting with ADD	%	(****)	****	****	(****)	(****)
Price Undercutting with ADD	Range	(10) - 0	25 - 35	20 - 30	(10) - 0	(15) - (5)
Thailand						
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting	Range	15-25	5-15	40-50	20-30	40-50

Price Undercutting with ADD	Rs./MT	****	****	****	****	****
Price Undercutting with ADD	%	****	****	****	****	****
Price Undercutting with ADD	Range	5 - 15	0 - 10	25 -35	5 - 15	25 -35
USA						
Price Undercutting	Rs./MT	****	****	****	(****)	****
Price Undercutting	%	****	****	****	(****)	****
Price Undercutting	Range	0-10	65-75	25-35	(5)- 5	25-35
Price Undercutting with ADD	Rs./MT	(****)	(****)	(****)	(****)	(****)
Price Undercutting with ADD	%	(****)	(****)	(****)	(****)	(****)
Price Undercutting with ADD	Range	(45) - (35)	(35) - (25)	(35) - (25)	(40) - (30)	(25) - (15)

132. The above data indicates that the landed values of imports from the subject countries/territories, without application of antidumping duty, continue to significantly undercut the domestic industry's prices in the Indian market during the injury investigation period except the imports from USA for the POI. Even with application of antidumping duties imports from some of the countries are having positive undercutting margins.

ii. Price underselling Effects

133. The impacts of dumped imports on the domestic industry's prices have also been examined with reference to the price underselling effects of the dumped imports. For the purpose of this analysis the weighted average landed values of imports of the subject goods based on grade-wise and series wise analysis of the import data as stated above has been compared with the weighted average of the non-injurious prices of the corresponding grades determined by the Authority as per the principles outlined in Annexure III to the Antidumping Rules by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The price underselling effects are as follows:

POI	Unit	Subject Countries POI	Post POI (Annualized)
Quantity	MT	12291	15983
Trend	Indexed	100	130
Non-Injurious Price	Rs./MT	****	****
Trend	Indexed	100	100
Landed Value	Rs./MT	93429	113900
Trend	Indexed	100	100
Price Underselling without ADD	Rs./MT	****	****
Price Underselling	%	****	****
Price Underselling	Range	45-55	35-45
Landed Value with ADD	Rs./MT	108203	138274
Price Underselling	Rs./MT	****	****
Price Underselling	%	****	****
Price Underselling	Range	25 - 35	10-20

134. The above data indicates that the weighted average landed price of imports from the subject countries during the POI is significantly below the weighted average non-injurious prices of the domestic industry for the corresponding grades of the subject goods, resulting in significant price underselling. The price underselling is significantly positive during the POI. Even with application of the corresponding antidumping duties the overall underselling margin are significantly high.

135. As stated above underselling margins of the individual countries have also been examined to see the trends by comparing the weighted average landed values from each country with the weighted average NIP of the corresponding grades as follows:

Particulars	Unit	China	Chinese Taipei	EU	Korea	South Africa	Thailand	USA
Quantity	MT	7797	322	428	1188	166	1376	1014
Weighted average Non-Injurious Price	Rs./MT	****	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Landed value Without AD Duty	Rs./MT	76557	142421	146243	80562	138866	120695	155939
Price Underselling	Rs./MT	****	****	****	****	****	****	****
Price Underselling	%	****	****	****	****	****	****	****
Price Underselling	Range	70-80	15-25	30-40	20-30	30-40	35-45	5-15
Weighted average Landed value with ADD Duty	Rs./MT	81942	164986	171898	84254	177348	135583	244766
Price Underselling	Rs./MT	****	****	****	****	****	****	(****)
Price Underselling	%	****	****	****	****	****	****	(****)
Price Underselling	Range	60 - 70	0 - 10	10 - 20	15 - 25	0 - 10	15 - 25	(35 - 25)

136. The above data indicates that the landed value of imports from each of the countries being investigated have remained significantly below the non-injurious price of the domestic industry during the POI. Even with antidumping duties the landed values are significantly below the NIP except for the imports from USA.

III, Price Suppression / Depression effects

137. To examine the price suppression or depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales of the corresponding grades/ series of the subject goods manufactured and sold by the domestic industry as follows:

200 Series	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI
Cost of sales	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	108	117	115	123
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	103	103	106	109

300 Series	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI
Cost of sales	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	116	106	109	117
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	99	93	88	93

400 Series	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI
Cost of sales	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	112	114	129	139
Selling Price	Rs./MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	100	103	106	117

138. The above data indicates that the cost of sales of the domestic industry has increased by about 23% for 200 series, 17% for 300 series and 39% for 400 series over the injury investigation period but the selling prices have remained depressed and have not increased commensurate with the increase in its cost of sales during this period.

(c) Examination of Other Economic Parameters of the Domestic Industry

139. Annexure II to the Anti- dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry have been examined as follows:

i. Actual and Potential Impact on Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

140. The petitioner domestic industry originally had only one unit for at Hissar for production of cold rolled flat products. The second unit for production of cold rolled flat products in Odisha was added in 2011 which went into production w.e.f. January 2012. The capacities of the new unit have been gradually ramped up in the subsequent period. The plants do not have dedicated capacities for the product under consideration as the plants roll products up to 1690 mm while the product under consideration covers only upto 1250mm. Therefore, the capacities for the product under consideration have been derived based on the ratio of PUC and Non-PUC rolled in these plants during the injury investigation period. Accordingly, the capacities, production and sales of the domestic industry has been shown below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (A)
Cold Rolling Capacity	MT	2,75,000	3,87,500	7,25,000	7,25,000	7,25,000
Capacity for the PUC	MT	2,00,696	2,11,768	4,39,009	4,74,994	552525
Trend	Indexed	100	106	219	237	275
Production	MT	1,60,949	1,91,821	2,51,299	2,96,611	356072
Trend	Indexed	100	119	156	184	221
Capacity Utilization	%	80	91	57	62	64
Trend	Indexed	100	113	71	78	80
Domestic Sales	MT	121191	147564	177949	209827	276893
Trend	Indexed	100	122	147	173	228

141. The above data indicates that the capacities have increased by about 137% and the production has increased by about 84% in the POI compared to the base year. Therefore, there is a decline in capacity utilization compared to the base year. But capacity utilization has improved compared to the previous year.
142. The domestic sales of the domestic industry have increased by about 74% in the POI as compared to base year as there is increase in production as well as demand during the POI vis-à-vis base year. However, this increase in volume of sales has contributed to only 5% increase in market share of domestic industry while the demand increased by around 60%. Therefore, it appears that despite huge growth in demand and production capacity, domestic industry has been able to capture only 5% more share during injury investigation period.
143. However, as noted earlier the demand of the product is under-represented as substantial volume of imports have been shifted to the products of widths outside the scope of product under consideration. Therefore, capacity addition of the domestic industry appears to be in tandem with the increase in demand for the flat rolled products as a whole in the country.

ii. Actual and Potential Impact on Profitability, Profits, return on investment and cash flow

144. The financial performance of the domestic industry during the injury investigation period in terms of its return on investment and profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (A)
Weighted average Selling Price	Rs/MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	102	97	97	99
Weighted average Cost	Rs/MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	115	111	115	123
Profit	Rs Lakh	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Indexed	100	-588	-802	-1286	-2372
Profit/ Loss	Rs/MT	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Indexed	100	-483	-546	-743	-1038
Profit before interest	Rs Lakh	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Indexed	100	-90	-115	-226	-541
Cash Profit	Rs Lakh	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Indexed	100	-214	-250	-413	-1091
ROCE	%	****	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	Indexed	100	-79	-85	-146	-227

145. The above data indicates that while the weighted average cost of sales per unit has increased by about 15% in the POI compared to the base year the price realization per unit has dropped by about 3% during the same period resulting in net loss from a profitable situation in the base year. The profit before interest has also declined significantly in the POI as compared to the base year and has reached substantial negative levels in the POI. Cash profit and return on capital employed have also become negative in this period.
146. The interested parties have argued that the increase in cost of production and the consequent losses to the domestic injury is on account of the addition of capacity of the Odisha unit which was under ramp up operation during the injury investigation period. The Authority notes that the cost of production has been duly normated to account for the additional cost if any due to ramp up operation and under utilization of the Odisha plant for the purpose of determination of Non-injurious price. Even after normating the costs on account of these factors the cost of sales of the product under consideration remains significantly above the selling price during the period of investigation indicating the impact of the dumped imports.

iii. Actual and potential impact on Market Share

147. As indicated in the previous tables the market share of the domestic industry in demand of the product in India shows an increase of about 5% in absolute term over the base year while the demand has grown by about 60% during the same period indicating thereby the inability of the industry to significantly benefit from increase in demand though the capacities have been added and the antidumping duty protection is available.

iv. Actual and potential impact on Inventories

148. The data given in the table below shows that the inventory levels with the domestic industry have increased significantly by about 46% in the POI compared to the base year despite increasing demand.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (Annualized)
Average stock	MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	113	124	146	182

v. Actual and potential impact on Employment, Productivity and Wages

149. The performance of the domestic industry in terms of employment and wages and productivity as indicators of injury has been analysed as follows:

Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (A)
Production	MT	1,60,949	1,91,821	2,51,299	2,96,611	356072
Trend	Indexed	100	119	156	184	221
Employees	No.	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	123	182	229	229
Production/employee	MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	97	86	80	97
Productivity per day	MT	447	533	698	824	989
Trend	Indexed	100	119	156	184	221
Wages/ employee	Rs.	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	105	132	154	157

150. The data indicates that the employment level of the domestic industry has doubled over the injury investigation period which is commensurate with the capacity added during this period. But the production has not kept pace with the capacity added leading to decline in per employee productivity. However, per day productivity has increased significantly. The increase in wages per employee is apparently due to normal increases in the wage levels.

vi. Actual and potential impact on Growth

151. Examination of various physical and financial parameters of the domestic industry indicates that there was negative growth of the domestic industry in terms of capacity utilization profits, cash profit as well as ROI in the POI as compared to the base year despite significant increase in demand and increase in production and sales. Growth in critical parameters are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity Utilization	Indexed	-	10.43	-33.4	5.29
Profit	Indexed	-	-19,792	-6,160	-13,941
Cash Profits	Indexed	-	-19,685	-2,250	-10,200
ROCE	Indexed	-	-20.89	4.46	-2.3

152. The domestic industry has contended that with increase in capacity, the domestic industry had expected robust growth in profits, comfortable cash flow and increase in return on investments. However, the domestic industry was not able to achieve the same due to the presence of the continuous dumped imports, diversion of significant volume of imports to higher widths and price pressure from the subject countries.

vii. Ability to raise capital investments

153. The Authority notes that under antidumping duty protection against dumped imports from several countries and with a healthy growth in demand due to general macroeconomic conditions in the country leading to increase in consumption of the subject goods the domestic industry has added significant capacities during the injury investigation period at substantial capital investment. The domestic industry has submitted that all these investments would be financially jeopardized if the dumped and injurious imports from the subject countries are allowed to enter into the country without the anti-dumping duties. It will significantly affect the ability of the domestic industry to make further capital investment as the current return on capital invested is negative.

viii. Factors affecting domestic prices

154. The above analysis indicates that there is a healthy growth in demand. The dumped imports from the subject countries, though low in volume, are still entering the Indian market at prices much below the cost of production and selling prices of the domestic industry causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. It is also noted that the imports from the subject countries of widths above 1250MM has increased while imports of the goods subjected to antidumping duty have declined. The domestic prices are thus affected by the combined effects of continued dumped imports from the subject countries as well as increased imports of goods not covered under the scope of the product under consideration.

ix. Level of dumping & dumping margins

155. The Authority notes that the dumping margins of the imports of the subject goods from the subject countries are positive and substantial though the volumes of imports from the subject countries were low due to the antidumping duty in force during this period.

K. Overall Assessment of current Injury and Causal Link

156. The above analysis of various factors indicate that physical performance of the domestic industry in terms of capacity, production and domestic sales of the subject goods improved during the injury investigation period with a healthy growth in demand. However, the financial performance of the domestic industry, in its domestic operations, has deteriorated during this period apparently because of the price pressure of dumped imports from the subject countries. Thus the domestic industry continues to suffer material injury in terms of financial losses and negative return on capital employed.
157. The interested parties have argued that this injury to the domestic industry is on account of other factors and has nothing to do with the imports from the subject countries as the volume of imports from these countries is very low. The Authority has examined other issues raised by the interested parties through the following non-attribution factors:

(i) Volume and prices of imports from other sources

158. The Authority notes that the subject goods are being imported from number countries, apart from the countries under investigation. The data below shows the volume of imports and their price trends:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Import Volume					
Subject Countries	MT	20263	29700	17908	12291
Trend	Indexed	100	147	88	61
Other Countries	MT	24588	31566	48593	38556
Trend	Indexed	100	128	198	157
Weighted average CIF Price of Imports					
Subject Countries	Rs/MT	92,538	86,021	1,12,973	87,973
Trend	Indexed	100	93	122	95
Other Countries	Rs/MT	1,09,985	1,10,502	1,14,004	1,03,149
Trend	Indexed	100	100	104	94

159. The above data clearly establishes that the prices of the imports from other countries are higher than that of Subject Countries. Therefore, import from other countries is not a factor affecting the performance of the domestic industry.
160. As noted earlier the imports from the subject countries have clearly shifted from the goods covered under the PUC to products with width beyond the scope of the product under consideration and the volume of such imports have significantly increased.

(ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

161. It is noted that the demand of the subject goods in the country has grown consistently from base year indicating a healthy demand situation in the country. None of the interested parties has made any submission about the change in the pattern consumption of the subject goods causing injury to the domestic industry. In fact, with the growth in general economic performance the consumption of the subject goods is expected to increase which is reflected in the healthy demand position. Therefore, contraction in demand or change in consumption pattern is not a factor affecting the performance of the domestic industry.

(iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

162. The Authority notes that the petitioner domestic industry is the major producer of the subject goods in India. The goods are freely importable and the goods are being imported from several countries including the subject countries. No evidence of trade restrictive or anti-competitive practices has been produced by any interested party during the course of the investigation.

(iv) Development in Technology

163. The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

(v) Export performance of the domestic industry

164. The export performance of the domestic industry during the injury investigation period was as follows:

Year	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI (A)
Production	MT	1,60,949	1,91,821	2,51,299	2,96,611	356072
Trend	Indexed	100	119	156	184	221
Employees	No.	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	123	182	229	229
Production/employee	MT	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	97	86	80	97
Productivity per day	MT	447	533	698	824	989
Trend	Indexed	100	119	156	184	221
Wages/ employee	Rs.	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	105	132	154	157

165. The above data shows that the domestic industry has a very healthy export performance and the exports have grown significantly. However, export performance is not relevant here since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis and injury if any due to the export performance of the domestic industry has not been attributed to the dumped imports.

166. In their post disclosure submissions the interested parties have argued that as per the data of domestic industry it can be observed that while imports are continuously decreasing, the losses suffered by domestic industry are increasing. Therefore, clearly there is no correlation between the trend of injury parameters of the Indian domestic producers and the volume and price of imports of the subject product. This demonstrates that there is no causal link between alleged dumped imports and alleged injury to the Indian domestic producers. In this regard, the Authority notes that though the volume of imports of the subject goods has decreased after imposition of antidumping duty the imports of the said products with higher widths have significantly increased clearly establishing the shifting of imports to outside the scope of duty thereby nullifying the impact of duty. Therefore, it cannot be said that there is no correlation between the imports and the losses suffered by the domestic industry.

L. Conclusion on current Injury and Causal Link

167. Examination of various injury parameters and the non-attribution parameters as outlined in the previous section indicates that there is a healthy increase in demand for the subject goods in India. The domestic industry has added capacity which is in line with the growing demand, and the production and sales of the domestic industry has also increased the petitioner domestic industry continues to suffer from low capacity utilization. The dumped imports from the subject countries continue to have significant price undercutting and underselling effect on the prices of the domestic industry and the prices of the domestic industry continue to be suppressed resulting in financial losses. The domestic industry is unable to realize remunerative prices to cover cost of production and sales due to the presence of dumped imports as well as diversion of large volume of imports to ranges outside the scope of the product under consideration as defined in the original investigation. Non-attribution analysis as above does not show any other factor that could have significantly contributed to the injury suffered by the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry continues to suffer material injury due to continued dumped imports from the subject countries/territories.

M. Examination of Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

168. It is noted that the subject goods continue to enter the Indian market from the subject countries at substantially dumped prices though volume of imports have significantly declined after imposition of duties. Examination of the injury in the previous section also indicates that the domestic industry continues to suffer injury on account of imports at very low prices from subject countries against which anti-dumping duties are in force. The Rules require the Authority to examine if the dumping is likely to continue or recur and whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties are revoked.

M.1 Views of the Domestic Industry

169. The domestic industry, in its submissions, has argued that there is continued dumping of the products under consideration from the subject countries and though the volume of dumped imports has declined, the dumping margin is positive. It has been submitted that dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries should the current anti dumping duty be revoked. It has been *inter alia* submitted:
- That the domestic industry is already suffering injury and revocation of anti-dumping duty shall lead to intensified injury to the domestic industry. Cessation of anti-dumping duty is likely to have significant suppressing and depressing effect on the prices of the product under consideration in the market.
 - That the producers in subject countries maintain huge capacities and spare capacities available shall be used to intensify dumping if the duties are revoked. In this regard, the domestic industry has submitted certain information from the published data from *Stainless Steel Flat Products Market Outlook* to substantiate the claim of surplus capacities of the subject goods in subject countries. It has been submitted that the capacities in these countries and their comparison with the domestic capacities, production, sales and demand in India give an insight into the potential danger of the dumped imports from the subject countries and the imminent likelihood of dumped imports into the country in large volumes. The estimated data on the capacities and production of the subject goods in the subject countries as provided by the domestic industry, is as follows:

In thousand MT							
Particulars/Country	China	EU	Korea	USA	Taiwan	Thailand	South Africa
Indian Demand	324	324	324	324	324	324	324
Capacity in subject countries/territories	13755	4460	1986	2776	1668	300	545
Capacity Utilization	78%	65%	54%	50%	75%	67%	57%
Excess Capacity in the subject countries	22%	35%	46%	50%	25%	33%	43%
Local Demand in subject countries/territories	8519	2428	782	1284	677	272	164.6
Current Export from the subject countries	486	448	293	116	567	185	129
Surplus capacity	3026	1561	914	1375	424	100	234
Net Qty Available for Export	3512	2009	1207	1491	991	100	398.6
Available capacity as % of Indian Demand	1084%	620%	372%	460%	306%	31%	123%

- c. That the Indian demand is merely 1% of the consolidated capacity of subject goods from subject countries and in the event duties are not extended, there is every chance that they will continue to dump their production in Indian market.
- d. That capacity in China increased by 93% in the POI to 11473 KMT as compared to 7114 KMT in the year 2009 when preliminary duties were imposed. In the post POI period i.e., by 2015, Chinese producers have added around 25% more capacity as compared to 2013. It is also submitted that during the same period their exports grew by 266% and that too when their average operating level was in the vicinity of 78% to 82%. In the event duties are not extended China can alone cater to our domestic market. It is further submitted that even if the subject goods produced from its idle capacity is diverted to India at current prices there is every likelihood that domestic industry will continue to suffer injury. In support of their claim the domestic industry has submitted the following information regarding the capacities and other details of the subject goods in China as follows:

	Unit	2009	2013	2015
Capacity	MT	7114	11473	14370
Capacity utilization	%	73	78	72
Unutilized Capacity	%	27	22	28
Net Export	MT	-303	504	541
Production from Surplus Capacity	MT	1921	2524	4024
Net Qty Available for Export	MT	1618	3028	4565
% of Indian Demand	%	499	934	1408

- e. That export orientation of the producers in Korea is significant and the exports from that country have increased by 63% from 2009 to 2013. During the said period the producers in Korea increased their capacity by 10%, however, they are only operating in the average range of 50% to 55%. It has been argued that with almost 40% of the idle capacity, exporters from Korea will definitely increase their volumes at the injurious and dumped prices if the duties are not extended against them. It has been further argued that the imports from Korea, in particular 400 series, is coming in the higher widths, which is outside the purview of the anti-dumping duty, at significantly dumped and injurious prices, which is a good indicator of their likely prices.
- f. That the European Union is among those established and saturated markets where capacities and their utilization remain constant for their domestic consumption. Exports from EU grew by 52% and 74% when compared from 2009 to 2013 and 2015 respectively. This export orientation coupled with the fact that they have around 35% idle capacity, which translates into 1561KMT of production, is around 482% of Indian demand. If only part of this surplus capacity is diverted towards India at the current prices, it can adversely impact the financial performance of the domestic industry. It has been further argued that the exporters from EU are also suffering from dumped and injurious imports from China and Taiwan and looking for options in export market to dump goods so that at least they can cover fixed cost. In this situation, it is extremely important to extend the duties against EU to safeguard domestic industry, from continued dumped and injurious imports.
- g. That the consumption of subject goods in South Africa is merely 29% of their capacity, which means around 71% of their capacity, is available for exports. In this context, it is also important to note that this 71% of the capacity translates into 387MT (in KT) which is more than the local demand in India. If this quantity is diverted towards India at current prices, it is imminent that the domestic industry will continue to suffer injury.
- h. That Thailand is passing through very difficult times and their local consumption of subject goods is on a declining trend. Therefore, it is very likely that they will dump their production in Indian market which is growing at decent pace.
- i. That since none of the producers/ exporters has participated from the Taiwan and USA the Authority has to determine the likelihood based on the information available in the public domain. The combined capacity of Taiwan and USA is almost 1372% of the Indian demand. It is also submitted that all the allegations made by the domestic industry in relation to Taiwan and USA remained unchallenged as even the concerned governments have not provided any information about likelihood or rebutted to the information provided by the domestic industry. In view of the above, the duties against Taiwan and USA should also be extended.

- j. That a price sensitive market like India becomes more vulnerable to dumped and injurious imports in such economic scenarios in the global market. In such circumstances, withdrawal of anti-dumping duty in force will certainly lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry. Therefore, there is every likelihood of huge potential imports if the duties are lifted.
- k. That from the above, it is clear that in case the of revocation of anti-dumping duties, the volume of imports of the subject goods is bound to increase further, which is also evident from the fact of continued dumped imports in spite of imposition of duty from the subject countries.
- l. That decline in imports, post imposition of duty, and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.
- m. That the volume of subject goods has shifted to widths above 1250MM and that too at prices lower than that of subject goods. The ratio of subject goods of widths 600MM to 1250MM and above 1250MM mix has changed from (71:29) to (15:85) respectively subsequent to the imposition of the anti-dumping duty. It is further submitted by the domestic industry that the 87% of the import of the grade EN 1.4512 in 2010-11 was in the widths of 600mm to 1250mm, when the said grade was not part of product under consideration liable for duties. However, after the issuance of the corrigendum dated 7.02.2012, wherein this grade EN 1.4512 was brought within the purview of dumping duties, the imports of this grade shifted to widths width 1250mm accounting for share as high as 99%. This fact clearly indicates that if duties are revoked, exporters will again bring the goods in the range of 1250MM only. Therefore, the duties should be extended.
- n. That European Union has issued preliminary findings against China and Chinese Taipei, *vide* Commission Implementing Regulation (EU) 2015/501 of 24 March 2015 and imposed anti-dumping duty of 24.3% to 25.2% from China and 10.9% to 12% from Chinese Taipei. In such case, withdrawal of the anti-dumping in force will provide a free market access to the manufacturers/exporters in these countries to dump the subject goods and accordingly, there is very strong likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- o. That there are positive and significant injury & dumping margins even when calculated based on the prices from the subject countries to countries other than India.
- p. That there is every likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury once the duties are withdrawn, as withdrawal of the anti-dumping duties will provide a free access to the manufacturers/exporters of the subject goods from the subject countries to dump the subject goods in India.

M.2 Views of the producers/exporters/importers/other interested parties

170. The interested parties, in their submissions, have argued:

- a. That the domestic industry has not provided any evidence to prove that there is any likelihood or continuation of dumping and injury.
- b. That the domestic industry has not provided post POI information in the petition, therefore, interested parties cannot comment on the post POI performance of the domestic industry.
- c. Interested parties have disputed the claims of the domestic industry that there exist huge capacities in subject countries which would lead to a likelihood of recurrence of dumping from these countries and injury because of imports from subject countries. It has been argued that mere existence of huge capacity is not a ground for extension of antidumping duty as has been held by the Appellate Body. The petitioners should provide concrete evidence for the existence of huge capacities and mere conjecture must not be accepted by the DGAD.

M.3 Examination by the Authority

171. The Authority has noted the arguments of the domestic industry and other interested parties with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from subject countries. Under the Rules, the Authority is required to determine whether revocation of the anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury. It is noted that the volume of subject goods from subject countries declined in the POI, due to the presence

of anti-dumping duties. However, it is observed from the import data that imports of subject goods of widths above 1250MM increased during the injury investigation period. Therefore, there is merit in the claims of domestic industry that imports of subject goods gets shifted to higher widths thereby artificially reducing the volume of imports of the goods covered under the scope of the product under consideration on which duties are in force. After examining the claims of all the interested parties the Authority has examined the issues to see whether there is a likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury from subject countries during the injury investigation period. In this connection the following issues have been examined.

(i) Level of current and past dumping margins from the subject countries

172. The examination in the previous sections indicates that the levels of current dumping margins from subject countries/territories are significant in spite of the fact that duties are in force. The dumping margins in the original investigation were also significant. The Authority also notes that European Union has imposed antidumping duties on the same product from China and Taiwan and the dumping margins determined by that Authority is also significant. Therefore, the product seems to have a history of dumping.

(ii) Available capacities in the subject countries and global demand supply scenario

173. As per the latest report of Stainless Steel Flat Products Market Outlook, May 2015, The available as well as projected capacities and demand in the subject countries, and derived surplus capacities in these countries are as follows:

000MT	China	Korea RP	Taiwan	USA	EU	Africa	Thailand
Projected Indian Demand	394	394	394	394	394	394	394
Capacity in subject countries	26600	2200	1776	4301	8352.4	1000	300
Capacity Utilization	66%	81%	46%	61%	77%	48%	62%
Excess Capacity	34%	19%	54%	39%	23%	52%	38%
Local Demand	9584	897	485	2102	3337	135	267
Current Export	10624	1099	1172	1870	2658	281	185
Surplus capacity	9084	427	961	1375	424	100	234
Net Qty Available for Export	19708	1527	2133	1491	991	100	501.3
% of Indian Demand	5003%	388%	542%	460%	306%	31%	127%

Source: CRU May 2015

174. The data indicates that the producers in the subject countries/territories have huge surplus capacities, which is also corroborated by the information submitted by the responding producers in this investigation. As per this report the global CR demand is expected to drop by 3.5% while the capacities have increased rapidly creating a significant demand supply mismatch scenario. The Authority further notes that due to significant dumping of the goods from certain countries the product has been recently subjected to antidumping duties in various countries such as, the European Union (March 2015, China and Taiwan); Vietnam (Sept 2014: China, Taiwan, Indonesia and Malaysia; and Brazil (Oct 2013: China, Korea, Taiwan, Vietnam and Finland) thereby further affecting the demand supply scenario. In such a scenario growing Indian market would be attractive for the foreign producers to utilize their surplus capacities at marginal cost pricing. Such imports will have potential to adversely affect the performance of the domestic industry through volume as well as price effects, if imports continued to come at the current prices without anti-dumping duty.

(iii) Anti-dumping Investigation on Subject Countries

175. It is noted that the European Union has issued preliminary findings against China and Chinese Taipei *vide* Commission Implementing Regulation (EU) 2015/501 of 24 March 2015 and imposed anti-dumping duty of 24.3% to 25.2% from China and 10.9% to 12% from Chinese. This also shows the dumping behavior of the exports from these two countries. Apart from this, antidumping duties have been imposed by Brazil in Oct 2014 on CR Flat Products from China, Korea, Taiwan, Vietnam and Finland. Vietnam has also imposed antidumping duties on these products in Sept 2014. Therefore, there is an imminent likelihood of diversion of subject goods to India, from these countries, if the duties are revoked.

(iv) Price Attractiveness of the Indian Market and Demand scenario

176. Indian market for the subject goods continues to have a healthy demand for the product which is in line with the general economic growth. However, the price scenario of the past indicates that it would continue to remain a low price market and attractive for the global players with surplus capacity to export at marginal cost pricing. However, if the duties are removed the Indian market will become much more attractive as the exporters would be able to realize better prices to the extent of the duty absorption by them.

(v) Trend in imports in the post POI period

177. The POI in the instant case was January 2013 to December 2013 and the extended antidumping duty was valid till 20th April 2015. Therefore, during the first six months of the post POI period the duties were in place. Therefore, the post POI import data is also affected by the duties and would not provide any significant trend in volume and prices. Nevertheless, the data has been examined to see any significant trend, if any. 6 months import data beyond the POI has been examined to see the trends. The data on post POI imports given in the previous section indicates continuation of the same trends. In fact the volume of imports shows a significant increase in the post POI period.

(vi) Post POI price effects scenario

178. Comparison of post POI import prices with the selling prices of the domestic industry also shows that the prices continue to significantly undercut the prices of the domestic industry.
179. The import prices during the post POI period, when compared with the non-injurious prices, also indicates that if the duties are revoked and the price line holds at that level it will have significant price underselling effect on the domestic industry.

Post-POI	Unit	China	Chinese Taipei	EU	Korea	South Africa	Thailand	USA
Quantity (Annualized)	MT	8235	432	2407	752	1102	1248	1808
Weighted average Non-Injurious Price	Rs./MT	****	****	****	****	****	****	****
Weighted Average Landed value Without AD Duty	Rs./MT	103631	113843	131844	118897	118897	122729	125574
Price Underselling	Rs./MT	****	****	****	****	****	****	****
Price Underselling	%	****	****	****	****	****	****	****
Price Underselling	Range	35-45	65-75	15-25	20-30	35-45	35-45	45-55
Price Underselling with ADD	%	****	****	****	(****)	****	****	(****)
Price Underselling with ADD	Range	25-35	30-40	0-10	(10) - 0	0-10	40-50	(15) - (5)

(vii) Post POI performance of the domestic industry

180. Though the domestic industry's production and sales during the post POI has improved as per the data presented in the previous section, Post POI financial performance of the domestic industry shows deterioration. The losses have increased during the post POI period indicating that the industry would continue to suffer injury if the duties are revoked.

N. Post Disclosure comments of the interested parties

181. In their post disclosure comments the interested parties have mostly re-iterated their arguments with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The responding exporters have further argued that product under consideration is only upto 1250mm width. If any other product beyond the scope of PUC is causing injury to domestic industry then this injury cannot be attributed to imports of subject goods. If authority wants to consider Non-PUC also, then it should be considered in totality. Merely considering volume of imports of Non-PUC for analysis is not acceptable. The authority should consider the price, demand, domestic sales and other economic parameters for goods beyond 1250 mm width. In this connection the Authority notes that without attributing any injury to such imports it was noted that the import data clearly establishes that the imports have shifted from the product

ranges beyond the scope of the product on which duty was in force and therefore, the data on demand and consumption, market shares and prices of the PUC is affected to that extent. Therefore, the impact of shift in imports to wider widths cannot be ignored.

182. The responding exporters have further argued that it is a settled practice of the Authority to terminate an anti-dumping investigation against a subject country when the volumes of imports from that country are extremely low. It has been further argued that this principle is adopted the European Union also in its sunset reviews. In this connection the Authority notes that in a sunset review the focus is on the likelihood analysis. If the import during the injury investigation is low the principle highlighted by the responding interested parties is applied when there is no imminent likelihood of recurrence of dumping. When a clear likelihood is established on the basis of the facts of the case low volume of imports during the injury period is not relevant.
183. The domestic industry, in its submissions, has further requested the Authority to recommend the residuary duties on those particular series not exported by the participating exporters. Further, all those produces / exporters or combination of producer and exporter who had participated in the original investigation and failed to participate in the sunset review investigation should also be awarded residuary duty.
184. The responding exporters, in their post disclosure submissions, have also argued that the authority should apply the same dumping margin / antidumping duty determined for the grades exported during the POI for the grades not exported during POI as it should be presumed that dumping, if any, shall be of same level for those grades also which have not been exported during POI by cooperating producer/exporter. The authority should not apply the penal rates of antidumping duty to grades not exported during POI for cooperating exporters as the objective of penal rates is to punish the non-cooperating parties. Respondents have fully cooperated with the authority during the course of investigation and provided all the information requested by the authority. Therefore, authority should not apply penal rates of antidumping duty to grades not exported by the Respondents during POI.
185. The issues raised by the interested parties in their comments to the disclosure statement have been examined to the extent they are relevant.

O. Overall assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

186. Examination of the publicly available data on capacities and production of the subject goods in the subject countries/territories as well as overall global demand supply scenario for the subject goods as outlined above clearly establishes the fact that the subject countries/territories have significantly high spare capacities for production of the said goods. The global demand supply scenario is adversely affected due to several macro-economic factors and the situation is likely to continue as per the projections available in such reports. The product also faces trade remedial measure in several countries and some of the subject countries are facing such trade remedy measures in some of the major markets as detailed in the previous section. Therefore, there is an imminent possibility of large scale export of the subject goods from the subject countries if the duties are revoked. General price trend indicates that on the face of global slump in demand and trade remedial measures in major markets it would be attractive for the producers in the subject countries to increase their exports to India at marginal cost pricing to recover their fixed cost by utilizing the idle capacities. Therefore, there is an imminent likelihood of increase in dumped imports if the duties are revoked.
187. The Authority notes that though the volume of imports of the product under consideration has declined after imposition of antidumping duties the domestic industry is already faced with low capacity utilization due to continued dumped imports and diversion of a significant volume of imports to product ranges outside the scope of the product under consideration. Even at increased production and sales levels the domestic industry is already facing significant decline in its financial results because of the price effects of dumped imports. Therefore, further increase in imports from the subject countries/ territories at dumped prices, in the event of revocation of duty, will further affect the domestic industry's capacity utilization and profitability. Therefore, injury to the domestic industry, which still continues to be affected because of dumped imports, is likely to be intensified if the duties are revoked.

P. Magnitude of injury and injury margin

188. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority margins of injury with respect to the importation of the subject goods from the subject countries/territories have also been determined. For determination of injury margin the Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry as per the procedures laid down in

Annexure III of the Anti Dumping Rules. For the purpose of like to like fair comparison the NIPs have been determined at the grade levels and consolidated at series level of respective grades of the subject goods. The Non-injurious prices, so determined at series level, have been compared with the corresponding landed values of the respective series of the product being imported from the subject countries, to arrive at the injury margins for each country. Accordingly, the NIP for the domestic industry and the margins of injury, for the products under consideration, have been determined for each of the subject countries.

189. The Authority notes that very negligible quantities of duplex grade has been imported from some of the countries during the period of investigation and the price information is not reliable. Therefore, that grade has not been considered for the injury margin calculations. Injury margins have been first determined at the grade/series level and then consolidated for the product as a whole taking into consideration the injury margins at the grade/series level for each producer. Accordingly, the NIP for the domestic industry and the margins of injury for the products under consideration have been determined for each of the subject countries as well as the responding exporters as follows:

Particulars/ Country		Unit	200 Series	300 Series	400 Series	Weighted Average
Producer	Exporter					
China	All Producer/ Exporters					
Injury Margin		US\$/MT	****	****	****	****
Injury Margin		%	****	****	****	****
IM Range		%	85-95	15-25	15-25	50-60
European Union						
M/s Acerinox Europa SAU Spain	M/s Acerinox Europa SAU, Spain					
Injury Margin		%		****	****	****
IM Range		%		20-30	30-40	25-35
All Others						
Injury Margin		US\$/MT		****	****	****
Injury Margin		%		****	****	****
IM Range		%		35-45	65-75	50-60
Korea RP						
M/s POSCO Korea				M/s Hyundai Corp.	Daewoo International	
Injury Margin		US\$/MT		****	(****)	****
Injury Margin		%		****	(****)	****
IM Range		%		10-20	(5-15)	0-10
All Others						
Injury Margin		US\$/MT		****	****	****
Injury Margin		%		****	****	****
IM Range		%		10-20	0-10	10-20
South Africa						
M/s Columbus Stainless	M/s Columbus Stainless					
Injury Margin		US\$/MT	(****)	****	****	****
Injury Margin		%	(****)	****	****	****
IM Range		%	(30-40)	10-20	10-20	10-20
All Others						
Injury Margin		US\$/MT	(****)	****	****	****
Injury Margin		%	(****)	****	****	****
IM Range		%	(30-40)	30-40	65-75	30-40

Taiwan	All Producer/ Exporters					
Quantity		MT	****	****		****
Injury Margin		US\$/MT	****	****		****
Injury Margin		%	****	****		****
IM Range		%	10-20	15-25		10-20
Thailand						
M/s POSCO Thainox	M/s POSCO Thainox					
Injury Margin		US\$/MT		(****)		(****)
Injury Margin		%		(****)		(***)
IM Range		%		(0-10)		(0-10)
M/s POSCO Thainox	M/s Hyundai Corporation	MT		91		
Injury Margin		US\$/MT		****		
Injury Margin		%		****		
IM Range		%		5-15		
All Others						
Injury Margin		US\$/MT		****		****
Injury Margin		%		****		****
IM Range		%		0-10		0-10
USA	All Producer/ Exporters					
Injury Margin		US\$/MT	****	****	****	****
Injury Margin		%	****	****	****	
IM Range		%	20-30	5-15	45-55	5-15

190. The above data indicates that the weighted average injury margins of the landed values of the dumped imports from the subject countries/territories at series levels are significantly below the Non-injurious prices of the subject goods of the corresponding series except for Thailand where the current injury margin for the product as a whole is negative.
191. The Authority notes that the margins of dumping at grade/series levels as well as for the product as a whole computed based on the current imports of the subject countries is significantly high and there is a clear likelihood of continuation of dumping from the subject countries. The Authority also notes that the margins of injury at grade/series levels as well as for the product as a whole is significant for all the subject countries except for the cooperating exporter from Thailand.
192. In case of POSCO Thainox, Thailand, it is noted that for the same grades the exports prices through the unrelated exporter is significantly different from the export prices when exported directly, resulting in significantly different dumping and injury margins for the same grades exported through different channels. The volumes of export through these two channels are also low. Since the producer has sold the same grades at differential prices during the POI, there is no reason to believe that the producer will not sell the goods at the lower prices at which the goods are sold during the PIOI if the duties are revoked. Therefore, for this producer from Thailand the Authority has determined the likely injury margin based on the prices at which the goods have been sold to India through its unaffiliated trading Company.

Q. Conclusions:

193. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that there is continued dumping of the subject goods from the subject countries/territories though the volume of imports has declined after imposition of duties. The performance of the domestic industry has deteriorated in the current injury period due to the impact of the dumped imports from the subject country and diversion of imports to product ranges outside the scope of the product under consideration. The dumping is likely to continue and the performance of the domestic industry is likely to deteriorate, should the present anti dumping duty is revoked.

R. Indian industry's interest & other issues

194. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

S. Recommendations:

195. The Authority notes that this sunset review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information and verifiable evidence on various aspects of dumping, injury and causal links and likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of the duties. Having conducted the investigation as per the procedure prescribed and having established that dumping and injury are continuing and are likely to continue, or recur, if the duties are revoked, the Authority considers it necessary and appropriate to recommend extension of anti-dumping duty on imports of subject goods, from the subject countries/ territories, in the form and manner described hereunder.
196. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends extension of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in this finding for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as a percentage of the landed value of the goods, as indicated in Col 9 of the duty table given below, is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries/territories for a further period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Tariff Item	Description of Goods	Specification	Countries/Territories of origin	Countries/Territories of Export	Producer	Exporter	Duty Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7219	Cold-rolled Flat 300 products of stainless steel*	All Grades, All Series except the exclusions as per footnote below	People's Republic of China	Any	Any	Any	57.39%
2	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	People's Republic of China	Any	Any	57.39%
3	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	M/s POSCO Korea	1. Hyundai Corporation 2. Daewoo International	5.39%
4	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	Any other than above combination		13.44%
5	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Any	Any	Any	13.44%
6	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Korea RP	Any	Any	13.44%
7				Chinese Taipei	Any	Any	Any	15.93%
8	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Chinese Taipei	Any	Any	15.93%
9	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	South Africa	Columbus Stainless	Columbus Stainless	12.34%
10	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	South Africa	Any other than above combination		36.91%
11	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	Any	Any	Any	36.91%
12	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	South Africa	Any	Any	36.91%

13	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Thailand	POSCO Thainox	1.POSCO Thainox 2. Hyundai Corporation	4.58%
14	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Thailand	Any other than above combination		5.39%
15	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Any	Any	Any	5.39%
16	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Thailand	Any	Any	5.39%
17	-Do-	-Do-	-Do-	USA	Any	Any	Any	9.47%
18	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	USA	Any	Any	9.47%
19	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	European Union	Acerinox Europa SAU, Spain	Acerinox Europa SAU, Spain	29.41%
20	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	European Union	Any other than above combination		52.56%
21	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	Any	Any	Any	52.56%
22	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	European Union	Any	Any	52.56%

Foot Note:

****** “Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”, excluding the following:

- i. The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).
- ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509
- iii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

The product under consideration is classified under the category “Base Metals and Articles of Base Metals” in Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 as per Customs Classification. Customs classification indicated herein is indicative only and is in no way binding on the scope of the application of duty if the products are imported under any other head of customs.”

197. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
198. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and the Rules, and Public Notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A. K. BHALLA, Designated Authority